

## हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 20 मार्च, 2008

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सेक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9:30 बजे हुई। अध्यक्ष (डॉ० रघुवीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर, अब सवाल होंगे।

### **Upgradation of 66 K.V. Sub-station to 132 K.V. Sub-station at Madlaoda**

**\*950. Smt. Raj Rani Poonam :** Will the power Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade 66 K.V. Sub-station to 132 K.V. Sub-station at Madlaoda in district Panipat?

**Power Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) :** The existing sub-station at Madlaoda is already of 132 K.V. level and its present installed capacity is defficient to feed the load of the area.

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्या को यह भी बता चाहूंगा कि इस सब-स्टे इन को 20 गुणा 25 एमवीए का ट्रांसफार्मर लगाकर ऑगमेंट किया है, जिस पर 150 लाख रुपए की लागत आई है जो 23.11.2007 को कमी इन कर

दिया गया था। इसके अलावा सरकार यह भी सोच रही है कि एक 33 केवीए का सब-स्टे इन ब्राह्मण माजरा में और 44 केवीए का सब-स्टे इन डाहर में भी हम बनायेंगे।

**श्रीमती राज रानी पूनम :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या इस सब-स्टे इन को 132 केवीए से अपग्रेड करने का सरकार का कोई प्रावधान है?

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला :** अध्यक्ष महोदय, यह सब-स्टे इन 132 केवीए का तो पहले से ही है। माननीय सदस्या ने यही प्रश्न पूछा था कि क्या 66 केवीए के सब-स्टे इन को 132 केवीए सब-स्टे इन में अपग्रेड करने का सरकार का कोई विचार है। इसके जवाब में मैंने पहले ही बता दिया है कि 132 केवीए सब-स्टे इनों को 23.11.2007 को फरदर ऑगमेंट करके कमी इन कर दिया गया है जिस पर 150 लाख रुपए की लागत आई है। इस इलाके को बेहतर सुविधा देने के लिए 33 केवीए के सब-स्टे इन ब्राह्मण माजरा और डाहर में भी बनायेंगे;

**श्रीमती सुमिता सिंह:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि जब लोकल लेवल पर करनाल में 132 केवीए का सब-स्टे इन लगाने का प्रपोजल है और उस सब-स्टे इन को लगाने के लिए म्यूनिसिपल काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास करके सरकार को भेज दिया है। मैं भाहरी विकास मंत्री जी और बिजली मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि जब

लोकल लेवल पर कोई केस पास होकर सरकार को भेज दिया जाता है तो उसको सरकार फोलो अप करे ताकि यह काम जल्दी हो जाये क्योंकि 3-4 महीने हो गये हैं सरकार की तरफ से कोई रिसपॉस नहीं मिला है।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला:** अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि जमीन के स्थानांतरण का मामला है जो माननीय भाहरी विकास मंत्री जी के विभाग से जुड़ा हुआ है लेकिन माननीय भाहरी विकास मंत्री जी स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अभी सदन में मौजूद नहीं हैं। मैं माननीय सदस्या से अनुरोध करूंगा कि वे इस बारे में भाहरी विकास मंत्री जी को और मुझे लिखकर भिजवा दें। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जमीन का हस्तांतरण जल्द हो जाए।

**श्री भाकुन्तला भगवाड़िया:** अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्र न पहले भी पूछा था। क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो 132 केवीए के सब-स्टे इन 15-15 साल पहले बनाये गये थे उनको फरदर एक्सटें इन करने का सरकार का कोई प्रावधान है। इसके अतिरिक्त बिजली की जो तारें टूटी पड़ी हैं उनको ठीक करवाने का कोई प्रावधान सरकार के पास विचाराधीन है क्योंकि मेरे हल्के के भाड़ावास गांव में बिजली की तारें टूटी पड़ी हैं।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला:** अध्यक्ष महोदय, इस बारे में माननीय सदस्या स्पैसिफिक सब-स्टे इन जिन-जिन गांवों के हैं

वे लिखकर भिजवा दें हम जांच करवाकर उनको सूचित करवा देंगे।

### **Upgradation of Power Sub-Station**

\*858 Dr. Sita Ram : Will the power Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade or augment the power Sub-stations in district Sirsa, if so, whether there is any proposal to upgrade 132 K.V. Sub-station of Asha Khera also?

#### **Power Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala):**

During the period from March, 2005 to January, 2008, five new 33 K.V. Sub-station and 28.9 Km 33 KV lines have been constructed, existing one 220 K.V., seven 132 KV & six 33 K.V. Sub-Stations augmented at an investment of Rs. 26.33 crore in District Sirsa.

In the next two years, it is proposed to construct eight new 33 KV sub-stations and 64.52 Km. associated lines as well as augment one 33 K.V. and two 132 KV Sub-stations at an investment of Rs. 15.69 crore in District Sirsa.

At present, there is no proposal to upgrade the 132 KV Sub-station Asha Khera. However, there is a proposal to create a new 220 K.V. Sub-station in the area around Asha Khera to meet the load growth of the area and land is being identified for the purpose. The feeding source of this Sub-station will be from a planned 400 K.V. Sub-station at Nuhiyawali in Sirsa district which is likely to be commissioned in 2010-11. The 220 K.V. Sub-Station in the area surrounding

Asha Khera and its Associated transmission lines will be commissioned in about 3 years at a cost of approximately Rs. 30 crore.

**डॉ० सीता राम:** अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने आ पाखेड़ा के सब-स्टे टान की अपग्रेडे टान के बारे में कहा है कि "नहीं" लेकिन जो 132 के०वी०ए० सब-स्टे टान हैं इस सब-स्टे टान से कई गांवों को बिजली जाती है और जब बिजली के पीक आवर्स होते हैं और बिजली का डिमंड होता है, उस समय बिजली बार-बार ट्रिप करती है, बिजली के कट लगते हैं और जब हम अधिकारियों से इस बारे में पूछते हैं कि यह ट्रिपिंग क्यों हो रही है तो वे कहते हैं कि इस सब-स्टे टान में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वह छोटी कैपेसिटी का है। इसलिए मैं मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि जब तक इस ट्रांसफार्मर को बड़ा नहीं किया जाता, तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि इस उपकेंद्र का फीडिंग स्रोत जिला सिरसा के नुहियावाली में एक 400 के०वी० के प्रस्तावित उपकेंद्र से होगा जो वर्ष 2010-11 में चालू होना संभावित है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूँ कि क्या इससे पहले हमारी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे?

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला:** अध्यक्ष महोदय, जहां बिजली का उत्पादन महत्वपूर्ण है, वहीं बिजली की ट्रांसमिशन व्यवस्था को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित होना भी उतना ही महत्वपूर्ण

है। माननीय सदस्य की चिन्ता वाजिब है और मैं उनकी चिन्ता से अपने आपको जोड़ते हुए कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा था आ पाखेड़ा में 132 के 0वी 0 सब-स्टे इन की अपग्रेडे इन करेंगे या नहीं। अध्यक्ष महोदय, हमने यह कह दिया कि हम 132 नहीं 220 के 0वी 0 का नया सब-स्टे इन बनाएंगे और 220 के 0वी 0 is much higher than 132 K.V. अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त हमने जो कदम उठाए हैं वे बड़े एलोबेट हैं और मैंने उनकी भी चर्चा करके बता दिया। डिस्ट्रीब्यूशन, ऑगमेंटेशन और क्रिएटिंग ऑफ न्यू सब-स्टे इंज तीनों को लेकर हम काफी गंभीर हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य जी को और सदन को बताना चाहूंगा कि मार्च 2005, के बाद हमने अब तक 68 नए सब-स्टे इन बनाए हैं, 182 सब-स्टे इनों को पूरे हरियाणा में ऑगमेंट किया है, 1137 किलोमीटर की बिजली की नई लाइनें लगाई हैं जिन पर कुल खर्चा अब तक 538 करोड़ 57 लाख रुपए आ चुका है। माननीय सदस्य की चिन्ता के साथ मैं अपने आप को जोड़ते हुए सदन को बताना चाहूंगा कि इस समय to reinforce our transmission, distribution and infrastructure की हमारी प्रपोजल है। हम 164 नए सब-स्टे इन 18 से 24 महीनों के अंदर बनायेंगे, 94 एग्जिस्टिंग सब-स्टे इनों को ऑगमेंट करेंगे और 2678 किलोमीटर लाइनें सरकार अगले 18 से 24 महीनों में खीचेंगी और इन पर 2142 करोड़ रुपए खर्चा आएगा जो हरियाणा के गठन के बाद अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है।

**डॉ० सीता राम :** अध्यक्ष महोदय, मैंने भारतीय मंत्री महोदय जी से सवाल पूछा है उसका जवाब नहीं आया। इन्होंने और चीजें तो पढ़ दी लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा है कि जो आ गाखेड़ा सब-स्टे टान है इसकी ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ाएंगे या नहीं क्योंकि 2010-11 तक दो-तीन साल कौन इंतजार करेगा। मेरा सवाल यह है और मंत्री जी को इसका स्पेसिफिक जवाब देना चाहिए।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला:** अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी मेरी बात को समझ नहीं पाये हैं, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि आ गाखेड़ा में 132 के०वी० का सब-स्टे टान ऑगमेंट करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है लेकिन इस क्षेत्र को और पूरे सिरसा जिले को अच्छी बिजली मिले उसके लिए सरकार 32 के०वी० के 8 नये सब-स्टे टान सिरसा जिले में लगा रही है। Speaker Sir, I think, Dr. Sita Ram ji, does not know the distinction between a 220 K.V. Sub-station and 132 K.V. Sub-station. Now, what can I do about it? Speaker Sir, he should come to me and I will explain him the modality. We are creating a new 220 K.V. Sub-station in the immediate vicinity of Asha Khera. Speaker Sir, once we are creating 220 K.V. Sub-station where is the need to augment 132 K.V. Sub-station in Ashakhera?

**डॉ० सीता राम:** अध्यक्ष महोदय, यह बात मेरी समझ में आ गई है कि आ गाखेड़ा में 132 के०वी० का सब-स्टे टान नहीं

लगाया जायेगा। लेकिन मैंने यह भी पूछा है कि क्या वहां पर अभी बड़ा ट्रांसफार्मर लगाया जायेगा ताकि ट्रिपिंग की समस्या न हो।

इसका जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया। (विधन)

### **Sarav Shiksha Abhiyan**

**\*937. Dr. Sushil Indora :** Will the Education Minister be pleased to state-

(a) Whether it is a fact that the Sarav Shiksha Abhiyan has been started to eliminate the curse of illiteracy and for promoting the education; and

(b) the year-wise and district-wise amount spent under this scheme during the period from March, 2005 to date?

### **Education Minister (Shri Mange Ram Gupta):**

(a) Yes Sir,

(b) A statement is placed on the table of the house.

### **Statement**

**Details of Yearwise and Districtwise amount spent under the SSA during the period from March 2005, to date**

(Rs. in lacs)

Sr.No.	Distt.	2005-06	2066-07	2007-08 (upto 31-01-



				08)
		Amount Spent	Amount Spent	Amount Spent
1.	Ambala	779.49	1713.78	1002.35
2.	Bhiwani	1734.68	2339.77	1581.34
3.	Faridabad	2009.38	2670.32	1637.29
4.	Fatehabad	1034.35	1797.37	982.40
5.	Gurgoan	1725.05	1692.04	1123.83
6.	Hisar	1436.25	1857.34	984.12
7.	Jhajjar	501.52	919.35	544.77
8.	Jind	973.13	1248.49	757.11
9.	Kaithal	866.35	1313.94	912.98
10.	Karanl	1415.67	1707.7	932.92
11	Kurukshetra	917.56	1498.2	1044.37
12.	M/Garh	832.33	1093.67	644.21
13.	Mewat		1960.01	1432.03
14.	Panchkula	337.75	731.92	491.39
15.	Panipat	694.78	1194.07	748.13
16.	Rewari	682.00	985.65	663.02

17.	Rohtak	585.49	809.31	499.49
18.	Sirsa	1023.82	1967.62	942.41
19.	Sonepat	698.04	1059.81	703.36
20.	Y. Nagar	1365.45	1573.73	1423.08
21.	SPIU	245.45	254.59	216.95
	Total	19858.60	30388.69	19267.55

**डॉ० सु गील इन्दौरा :** अध्यक्ष महोदय, हमारे शिक्षा मंत्री जी बहुत अनुभवी और सीनियर मंत्री हैं और मेरे लिये ये विशेषकर आदरणीय भी हैं। सर्व शिक्षा अभियान का मतलब यह निकलता है कि सबको शिक्षा मिले। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में दर्शाया है कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2007-2008 के दौरान विभिन्न जिलों में 19267.55 लाख रुपये खर्च हुआ है और सर्व शिक्षा अभियान ने अपना टार्गेट भी पूरा किया है। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सर्व शिक्षा अभियान के लिए कितना बजट अलॉट किया गया था और जो पैसा खर्च किया गया है वह किन-किन कार्यों पर खर्च किया गया है?

**श्री मांगे राम गुप्ता:** अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय साथी ने बजट अलॉटमेंट की बात की है, इस बारे में माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि सर्व शिक्षा अभियान के लिए व र्

2005-06 में 249.88 लाख रुपये का बजट रखा गया था जिसमें से 198.58 लाख रुपये खर्च किया गया। वर्ष 2006-07 के दौरान 365.91 लाख रुपये का बजट रखा गया जिसमें से 303.6 लाख रुपये खर्च हुआ है और करेंट ईयर है उसमें 31.1.2008 तक 357.6 लाख रुपये अलॉट किए गए हैं जिसमें से 192.67 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं तथा बाकी की फिगर अभी आना बाकी है तकरीबन 250 करोड़ रुपये खर्च हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इसमें जो पैसा बचता है वह अगले साल ट्रांसफर हो जाता है क्योंकि बिल्डिंग वगैरा कंसट्रैक्ट बन करनी होती है जिनका एस्टीमेट बाद में बनाया जाता है और अगले साल पैसा यूज हो जाता है।

**डॉ० सु लील इन्दौरा:** अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यह तो बतायें कि यह पैसा किन-किन कार्यों में खर्च किया गया है?

**श्री मांगे राम गुप्ता:** अध्यक्ष महोदय, 2007 में भारत सरकार ने एक स्कीम दी थी कि पूरे देश में उन्होंने हर बच्चे को शिक्षा देनी है और विशेषकर 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे जो गरीब हों, झोंपड़ी में रहने वाले हों उनके लिए पूरी तरह से कोशिश की जाये कि उन्हें शिक्षा मिले, वे अनपढ़ न रहें। इस सेंट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम के तहत नौवीं पलन के तहत 85 : 15 प्रति शत के बच्चों के हिसाब से भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा खर्च करना था। दसवीं प्लान के तहत 75 : 25 प्रति शत के बच्चों से पैसा खर्च करना था और ग्यारहवीं प्लान के तहत 50 : 50 प्रति शत के बच्चों के हिसाब से पैसा खर्च करना है। अध्यक्ष,

महोदय, मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इस स्कीम के कई आब्जेक्ट्स हैं। जैसे प्राइमरी स्कूलों को बनाना, बच्चों को किताबें देना, मिड डे मिल मुहैया करवाना, स्कूल में कमरे और टायलैट्स बनवाना आदि यादि की जो भी बच्चों की जरूरत पढ़ाई को लेकर हैं उनको पूरा करना इस स्कीम के मेन आब्जेक्ट्स हैं। मैंने अपने जवाब में पूरी डिटेल् दी हुई है, उसमें से किसी स्पेसीफिक के बारे में माननीय सदस्य जानना चाहते हैं तो मुझे बतायें। स्पीकर सर, यह तो हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की स्कीम थी इसमें हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। हम पूरे विवास के साथ यह कह सकते हैं कि आज गरीब से गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और इसमें हमें काफी सफलता मिल रही है। इसमें हमें सभी का सहयोग चाहिए जिससे हम इसमें प्रगति के नये आयाम स्थापित कर सकें।

**डॉ० सु गील इन्दौरा :** अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपना जवाब बड़े विस्तार से दिया है लेकिन इसमें फिर भी कुछ रह गया है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सर्व शिक्षा अभियान का यह भी मकसद था कि प्राइमरी एजुकेशन में गरीब बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट न हों, वे स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूलों में या अपने घर न जायें। इसलिए क्या शिक्षा को गुणात्मक रूप से प्रभावी बनाने के लिए कोई कदम सरकार ने उठाये हैं। इसके अतिरिक्त क्या मंत्री महोदय यह भी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक कितने बच्चे

सरकारी स्कूलों से ड्राप टीचर्ज हैं भले ही उनकी संख्या कम हो। तो क्या इन टीचर्ज की कमी को दूर करते हुए सरकार द्वारा ऐसी गुणात्मक शिक्षा का प्रबंध किया जायेगा जिससे सामाजिक एवं भौक्षणिक डिसपैरिटी भी न आये और गरीब बच्चों द्वारा जो सरकारी स्कूलों से विभिन्न स्तरों पर ड्राप आउट किया जाता है वह भी रुके।

**श्री मांगे राम गुप्ता:** स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी और सदन को यह बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार द्वारा इस बात के पूरे प्रयास किये हैं कि कोई भी बच्चा सरकारी स्कूल में दाखिला लेने के बाद ड्राप न कर सके। इस मकसद को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा गरीब बच्चों के लिए बड़े-बड़े इंशैटिव्ज दिए गए हैं। हमने यह निर्णय लिया है कि उनको फ्री किताबें दी जायेंगी, फ्री यूनिफार्म दी जायेंगी और फ्री मिड-डे-मिल दिया जयेगा। इसके अलावा हमारी सरकार द्वारा विशेष तौर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए 10 डिस्ट्रिक्ट्स में 30 बलॉक्स में शिक्षा संस्थान खोले गये हैं उनमें वोके इनल एजुकेशन भी दी जा रही है औरअग उनके लिए कोई रैंजीडेंसियल या कोई दूसरी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी प्रबंध किया जायेगा। इसके साथ ही हर बच्चे को जो किसी गांव से आता है, उसके लिए साईकिल वगैरह प्रदान करने का भी प्रावधान सरकार ने किया है। इसके अतिरिक्त गरीब बच्चों को मैडीकल सुविधा और कोचिंग क्लासिज की सुविधा भी सरकार की तरफ से

प्रदान की जा रही है। गरीब बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा भी प्रदान की जा रही है और खेलों के प्रति उनके मन में रूचि पैदा करने के लिए खेलों से संबंधित सभी सुविधायें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सरकार द्वारा सभी वांछित प्रयास किये जा रहे हैं ताकि बच्चा स्कूल में आकर घर जाने के बारे में और स्कूल छोड़ने के बारे में सोच भी न सके। अच्छे टीचर्स लगाये जा रहे हैं। कुल मिला कर मैं यह कह सकता हूँ कि सरकार द्वारा गरीब बच्चों के लिए इतनी सुविधायें और ऐसा माहौल प्रदान किया जा रहा है कि भविष्य में कोई भी गरीब बच्चा स्कूल में आने से हिचकिचायेगा नहीं। इसमें हमें बहुत भारी सफलता भी मिली है। स्पीकर सर, इस बारे में कल भी हाउस में चर्चा हुई थी कि हमारी सरकार द्वारा एक ऐसी अनोखी स्कीम राज्य में बी०पी०एल० के बच्चों के लिए चलाई गई है जो कि सारे देश में सबसे पहले सिर्फ हरियाणा में ही चलाई गई है। इस स्कीम के तहत बी०पी०एल० के बच्चों और विशेषकर गैडयूल्ड कास्टस के बच्चों को पहली क्लास से पांचवीं क्लास तक लड़के को 100/- रुपये और लड़की को 150/- रुपये प्रति मास मिलेंगे, छठी से नौवीं तक लड़के को 150/- रुपये और लड़की को 200/- रुपये प्रति मास मिलेंगे, दसवीं में दाखिला लेने पर लड़के को 200/- रुपये और लड़की को 300/- रुपये प्रति मास मिलेंगे और हायर क्लासिज में जाने पर लड़के को 300/- रुपये और लड़की को 400/- रुपये प्रति मास मिलेंगे। इससे बड़ा इंसेंटिव और क्या हो सकता है। अब अगर एक बच्चा एक बार स्कूल में दाखिला ले लेगा तो वह किस कारण से ड्राप

करेगा क्योंकि हमारी सरकार ने ड्राप करने के कोई चांसिज नहीं छोड़े हैं।

**डॉ० सीता राम:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो प्राईमरी स्कूलों में मिड-डे-मिल स्कीम है उसके अन्दर क्या किसी प्रकार की कोई अनिवार्यतायें पाई गई हैं? क्या खरीद के मामले में भी कोई अनियमितताएं पाई गई हैं और अगर पाई गई हैं तो उसमें सरकार के स्तर पर दोशियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

**श्री मांगे राम गुप्ता:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि उनकी यह चिंता वाजिब है। कुछ जगहों पर मिड-डे-मिल की परचेजिंग में अनियमिततायें हुई हैं। जब यह बात हमारे नोटिस में आई तो हमने उसकी इंकवायरी करवाई है। दोशियों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड किये गये हैं। कई केसिज में विजीलेंस इंकवायरी भी चल रही है और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह हुई है कि सरकार ने फैसला लिया कि जो सबसे बड़ा लकूना था, जिसके कारण ये परचेज में गड़बड़ी हो रही थी, हमने उस गड़बड़ी की जड़ को समझा है और हमने चोर को नहीं चोर की मौसी को ही मारा है। पहले एक अप्रूव्ड सोर्स के माध्यम से फील्ड में परचेज करने का काम चल रहा था। अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा सोर्स बना हुआ था कि चाहे कितने ही उंचे भाव में कोई चीज खरीद ली जाती

और उस अप्रूव्ड सोर्स का ठप्पा लगवा कर बिल जमा करवा दिये जाते थे और उस पर कोई ऑब्जेक्टिव नही होता था। हमने उसको स्टडी किया और उस मामले को कैबिनेट में रखवा कर खत्म कर दिया। भविष्य में हमारे विभाग में ही नहीं किसी भी विभाग में ऐसा कोई अप्रूव्ड सोर्स नहीं रहेगा जो खुद माल नहीं बनाता हो। अप्रूव्ड सोर्स के माध्यम से परचेजिंग नहीं होगी। ऐसी जो डुप्लीकेसी बनी हुई थी कागजी कार्यवाही करके अप्रूव्ड सोर्सिज का ठप्पा लगा दिया करते थे अब वह सारे हरियाणा में बैन करवा दी गई है। अध्यक्ष महोदय, अब चिन्ता करने की जरूरत नहीं है, भविष्य में इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी।

**डॉ० सीता राम:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि मिड-डे-मिल बनाने के लिए स्कूलों में जो कर्मचारी रखे जाते हैं क्या उनको कोई तनखाह दी जाती है? क्या मिड-डे-मिल के कारण स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और क्या मिड-डे-मिल बनाने के लिए स्कूलों में पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है?

**श्री मांगे राम गुप्ता:** अध्यक्ष महोदय, मिड-डे-मिल से बच्चों की पढ़ाई के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि इसको बच्चे तैयार नहीं करते। रात के लिए और दूसरा सामान रखने के लिए अलग से स्टोर बने हुए हैं और इस काम के लिए अलग से आदमी रखे गये हैं। खाना बनाने के लिए अलग जगह है



और छुट्टी के समय ही खाना दिया जाता है। इससे बच्चों की पढ़ाई के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।

**श्री भूपेंद्र चौधरी:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि स्कूलों में 5-5 हजार रुपये गैस कनेक्टान खरीदने के लिए दिए गये थे। उसमें से 1700 रुपये प्रिंसिपल को दिये गये थे बाकी 300 रुपये की गैस चूल्हे की परचेजिंग हुई थी। उस परचेजिंग में बहुत गड़बड़ी हुई थी। जब बाजार में जाकर उस गैस चूल्हे की कीमत असैस की गई तो वह 400 रुपये पाई गई। इस परचेजिंग में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इस मामले में क्या कोई कार्रवाई की गई है?

**श्री मांगे राम गुप्ता:** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जहाँ इस बात की चिन्ता है उसके साथ ही साथ इस बात की खुशी भी होनी चाहिए कि इस घोटाले को भी हमने ही पकड़ा था। जब हमारे नोटिस में यह आया कि गैस चूल्हों की खरीद में गड़बड़ी हुई है तो हमने उस माल को जब्त किया और इन्क्वायरी करवाई। जिस-जिस जिले में ऑफिसर ने गड़बड़ी की थी, उन अधिकारियों को हमने सस्पेंड किया है और विजिलेंस को इन्क्वायरी दी है तथा दोशियों को खिलापफ केस रजिस्टर करने का फैसला लिया जा रहा है। भविष्य में इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। जिस अधिकारियों ने गड़बड़ की है वे भी अब पछता रहे हैं।

**श्री कर्ण सिंह दलाल:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने के लिए कुछ साईंस टीचरों और साईंस लैक्चररज को भी सर्व शिक्षा अभियान में शामिल किया गया था उससे बड़ी क्लासिज की पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। क्या मंत्री जी साईंस के टीचरज और लैक्सरज को वापिस स्कूलों में भेजने का कोई आवासन देंगे ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारु रूप से चल सके।

**श्री मांगे राम गुप्ता:** अध्यक्ष महोदय, ऐसा हो सकता है कि किसी एक-आध स्कूल में कोई साईंस टीचर सर्व शिक्षा अभियान में लगा हो लेकिन हमारी प्राथमिकता तो साईंस को बढ़ावा देना है। अगर कोई साईंस टीचर प्राईमरी क्लासिज में लगा होगा तो हम उसको वापिस स्कूल में भेज देंगे।

**श्री कर्ण सिंह दलाल:** अध्यक्ष महोदय, एक-आध नहीं बल्कि यह संख्या बहुत ज्यादा है और कुछ लैक्सररज भी सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े हुए हैं जिससे बड़ी क्लासिज के बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है।

**श्री मांगे राम गुप्ता:** अध्यक्ष महोदय, हम साईंस के टीचर्स को भी और लैक्चररज को भी स्कूल और कॉलेजों में वापिस भेजेंगे ताकि बड़ी क्लासिज के बच्चों की पढ़ाई सुचारु रूप से चल सके।

**श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान:** अध्यक्ष महोदय, दादरी का डायट ब्लॉक है उसमें सर्व शिक्षा अभियान के तहत कमरे बने हुए हैं जिनमें सामान ठूस-ठूस कर भरा हुआ है। पीछे हम पी0ए0सी0 के साथ वहां पर गये थे। पिछली सरकार के समय में वहां पर जरूरत से ज्यादा सामान खरीद कर रख दिया गया है जो कि लम्बे अरसे तक इस्तेमाल नहीं हो सकता तथा सामान रखा होने के कारण उन कमरों का भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्या माननीय मंत्री महोदय, इस बारे में जांच करवा कर जो भी दोषी व्यक्ति अथवा अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करवाएंगे?

**श्री मांगे राम गुप्ता:** अध्यक्ष महोदय, पहली बार इस प्रकार की शिकायत किसी ने मेरे सामने लाने का प्रयास किया है। पी0ए0सी0 की रिपोर्ट की कोई सूचना अभी तक मेरे सामने नहीं आई है। हमारा प्रयास है कि ऐसे मामलों में तुरन्त कार्यवाही की जाए। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय में इस प्रकार का सामान जरूरत से ज्यादा खरीदा गया। हम इस बारे में इन्क्वायरी करवाएंगे और चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी है जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सजा देंगे। वैसे तो पिछली सरकार के बारे में राम कुमार गौतम जी ने आपके सामने ही फैसला कर दिया था कि जब तक ऐसे लोगों को सजा देकर जेलों में नहीं डालेंगे और उनका सामान नीलाम नहीं करवाएंगे तब तक इसका समाधान नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में ऐसी बात तो नहीं कहता लेकिन मैं विवास के साथ कहता हूं कि हम

मामले की पूरी इन्क्वायरी करवाएंगे और चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो हम किसी को भी बर्खास्त नहीं। हमने पहले भी प्रयास किया है कि हम किसी भी दोषी को नहीं छोड़ें और गलत काम करने वालों को सजा दें।

**श्री भाकुन्तला भगवाड़िया:** अध्यक्ष महोदय, मिड-डे-मिल स्कीम के तहत गांवों में जो स्कूल हैं उनमें बच्चों का खाना बनाने के लिए किसी महिला को रखा जाता है। जब यह स्कीम परमानेंट स्कीम है तो मिड-डे-मिल खाना बनाने के लिए परमानेंट तौर पर किसी लड़की को रखा जाना चाहिए क्योंकि इसके लिए सारे लोग कहते रहते हैं कि बहिन जी वहां पर हमें लगवा दें वे कभी किसी को कहते हैं कि मुझे लगवा दो इस प्रकार से ये पोस्टें लड़ाई का माध्यम बनी रहती हैं। स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसी स्कीम में परमानेंट नौकरी नहीं बनाई जा सकती है?

**श्री मांगे राम गुप्ता:** स्पीकर सर, कोशिश यह की जाती है कि मिड-डे-मिल बनाने के लिए गांव की ही किसी महिला को लगाया जाए और इसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि भगवान न करे अगर कोई महिला विडो हो जाए या कोई महिला बेसहारा हो जाए तो यह काम करने का मौका उसी को दिया जाता है। जहां तक मिड-डे-मिल बनाने के लिए परमानेंट तौर पर किसी महिला को लगाने की बात है, मैं समझता हूँ कि वह एक पार्ट टाइम काम है। दोपहर को करीब 100 बच्चों का खाना

बनाकर अपने घर चली जाती है। उसको सारा दिन अगर स्कूल में बिठा कर रखें तो उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसके जिम्मे और कोई काम नहीं है। वह स्कूल का खाना बनाने के बाद अपने घर जाकर अपना कोई और काम कर सकती है।

### **Construction of Footpath**

**\*877 Dr. Shiv Shankar Bhardwaj :** Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct footpath on both sides of road from Dinod Gate to Railway Station, Bhiwani, if so, the time by which such Footpath are likely to be constructed?

**Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav):** It is not feasible to construct Footpath on this road due to restricted right of way.

**डॉ० शिव शंकर भादवाज:** स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार टोटल सड़क पर फुटपाथ नहीं बना सकती है या कुछ ऐसा पोलिसिंग जो कन्जैस्टिड नहीं है वहां पर फुटपाथ नहीं बना सकती है। क्या माननीय मंत्री जी के संज्ञान में यह लाया गया था कि जब यह डिपार्टमेंट श्री परमवीर जी के पास था तो इसका प्रोजेक्ट एक बार पहले भी बना था और इसे प्रोजेक्ट की फाइल ऊपर तक भी आई थी। उस वक्त मैं कभी उनके दफ्तर में तथा कभी कमिशनर साहब के दफ्तर में इस फाइल को ढूँढता रहा। उस वक्त यह स्कीम

इसलिए पूरी नहीं हो पाई क्योंकि उस वक्त यह फाईल ट्रेस नहीं हो पाई थी। क्या माननीय मंत्री महोदय इसके बारे में बताएंगे?

**कैप्टन अजय सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी दिनोद गेट से रेलवे स्टे इन, भिवानी तक दोनों तरफ फुटपाथ बनवाना चाह रहे हैं। स्पीकर सर, यह सड़क टोटल 18 फुट चौड़ी है और जो average land available है वह 30 फुट है। अगर वहां पर वाटर सप्लाई, सीवर, टैलीफोन लाईन्ज और इस प्रकार की जो पब्लिक यूटिलिटी की सुविधाएं हैं जो वहां पर निकलती हैं और अगर हम वहां पर फुटपाथ बना देंगे तो उससे वहां पर चारों तरफ जाम होगा क्योंकि वह सारा बिल्ट अप एरिया है। इसमें दूसरी दिक्कत यह है कि स्टोर्म वाटर ड्रेनेज की भी वहां पर व्यवस्था नहीं है और अगर कल को कहीं इस प्रकार की सुविधा प्रदान करनी पड़ जाएगी तो उसमें समस्या रहेगी। मेरे विभाग के लोगों ने मुझे वीडियो क्लिपिंग भी दिखाई थी कि उस बाजार के अन्दर बड़ा भारी कन्जै इन है और अगर हम वहां पर फुटपाथ बना देंगे तो दिक्कत होगी क्योंकि वहां लोग अपनी गाड़ियां भी खड़ी करनी भुरू कर देंगे तथा उसके बाद वहां पर जाम लगना भी भुरू हो जाएगा। रेलवे स्टे इन एक महत्वपूर्ण पैसेज है और वहां पर यह जनहित में नहीं होगा कि हम फुटपाथ बनाएं;

**डॉ० वि भंकर भारद्वाज:** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि वह सारी की सारी सड़क

कंजैस्टीड नहीं है। कहीं थोड़ी सी जगह पर ही कंजैस्टीड होगी। जहां तक सीवर और पानी की पाईप लाइन की बात मंत्री जी ने कही है तो वह तो वहां पर बहुत पहले ही डाली जा चुकी है। अगर यह फुटपाथ बनेगा तो वहां पर जो लोग सामान सड़क पर रखते हैं वे उसको फुटपाथ पर रख लेंगे जिससे उस सड़क पर जो कंजैशन है वह भी खत्म हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, वहां पर फुटपाथ बनाने के बारे में प्रपोजल बनाकर अधिकारियों ने भेज दिया था लेकिन वह फाइल मुझे नहीं मिली जिसकी वजह से वह काम रह गया था। क्या मंत्री जी अब वहां पर उस फुटपाथ को बनाने के बारे में विचार करेंगे?

**कैप्टन अजय सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो फुटपाथ वाला परेशान है वहां पर वाटर सप्लाई विभाग की और सीवरेज की लाईन्ज डाली हुई है। अगर वहां पर फुटपाथ बना दिया गया और उसके बाद वहां पर किसी पाईप में दिक्कत आ गई तो उस फुटपाथ को दोबारा तोड़ना पड़ेगा। यह जो दिनोट गेट से रेलवे स्टेशन भिवानी की सड़क है यह 1300 मीटर लम्बी है। यह पोसीबल नहीं हो सकता है कि कहीं पर तो फुटपाथ बना दें और कहीं पर छोड़ दें। अगर ऐसा करते हैं तो उसकी स्मीटरी नहीं रहेगी। मैं अपने किसी अधिकारी को इनके साथ वहां पर भेज दूंगा और वे वहां पर मौके पर देख लें कि कंजैशन है कि नहीं है।

**श्री एस0एस0 सुरजेवाला:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि कैथल से पेहवा चौक से करनाल बाईपास तक बहुत चौड़ी सड़क है। वहां पर सड़क के दोनों तरफ एस0पी0, डी0सी0 के रैजीडेंट्स और सरकारी दफ्तर हैं। वहां पर कोई दुकानें नहीं हैं। क्या मंत्री जी उस सड़क पर डिवाइडर और फुटपाथ बनाने के बारे में विचार करेंगे, क्योंकि वहां पर सभी प्रकार के विचार कर लिए गए हैं, जो वहां पर फालतू पेड़ थे, उनको भी कटवा दिया गया है। सिर्फ इसमें पैसा सैंकान होना रह गया है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इस काम के लिए पैसा दे दें और यह बताएं कि इस काम को कब तक भुरु करवा देंगे।

**कैप्टन अजय सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय सदस्य ने जिक्र किया है। इस बारे में माननीय सदस्य सैप्रेट नोटिस दे दें। मैं इनको इस बारे में यह बताना चाहूंगा कि यह जो इन्होंने डिवाइडर और फुटपाथ बनाने की बात कही है इस बारे में हम एग्जामिन करवा लेंगे और जो कुछ भी संभव होगा, वह हम करने की कोशिश करेंगे।

**श्री सुमिता सिंह:** अध्यक्ष महोदय, ये जो हमारे साथी भारद्वाज जी ने बताया है कि भिवानी में फुटपाथ न होने की वजह से कंजैशन है। अगर वहां पर फुटपाथ बन जाएगा तो लोग सामान उस पर रख लेंगे, जिसकी वजह से वहां पर कंजैशन कम हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी



से जानना चाहती हूँ कि ये फुटपाथ सामान रखने के लिए होते हैं या पैदल चलने वालों के लिए बनाए जाते हैं।

**कैप्टन अजय सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदय, फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए बनाया जाता है। लेकिन वहाँ पर जो दुकानदार होते हैं वे अपना सारा सामान फुटपाथ पर रख लेते हैं। अगर दुकानदार सामान फुटपाथ पर रख लेंगे तो गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी होने लग जाएंगी जिससे पैदल चलने वालों के लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी। इस बारे में विभाग को चाहिए कि वे वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था पैदा न होने दें। इसमें सरकार के लोकल बॉडी के अधिकारियों को कार्यवाही करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज लोगों को यह आदत पड़ रही है कि वे सामान फुटपाथ पर रख लते हैं।

**श्री कर्ण सिंह दलाल:** अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो ये सड़कों के साथ फुटपाथ बनाए जाते हैं, उनको बचाने के लिए क्या क्राइटेरिया अपनाया जाता है कि वे कहाँ-कहाँ पर बनाए जाएंगे और क्यों बनाए जाएंगे?

**कैप्टन अजय सिंह यादव:** स्पीकर सर, मैंने पहले भी एक क्वै चन के जवाब में डिटेल में यह बताया था कि नॉर्मल सिटी के अंदर फुटपाथ बनाने का काम हमारा नहीं है बल्कि यह काम लोकल बोडीज विभाग का है। स्पीकर सर, जहाँ पर हमारे

विभाग की रोडज हैं, वहां यदि इस प्रकार की मांग आती है जैसे रैंजीडेंडि गयल एरिया हो जहां पर रोड काफी चौड़ी हो, जहां पर आसपास दुकानें न हों और जिस पाथ पर आने जाने में दिक्कत नहीं हो तथा जहां पर हम बना सकते हैं वहां पर हमने फुटपाथ बनवाये भी हैं इसलिए यह केस टू केस डिपेंड करता है। जहां पर कंजै गन होता है अगर हम वहां पर फुटपाथ बनवा दें तो इससे और ज्यादा दिक्कत हो जाती है। स्पीकर सर, फर्ज करो कि कहीं पर रैंजीडेंडि गयल एरिया है वहां पर तो हमें यह काम करने में दिक्कत नहीं है लेकिन अगर कहीं पर आमने-सामने दुकानें हैं और हमें वहा पर कंजै गन है तो वहां हमें दिक्कत आती है। वैसे ये फुटपाथ लोकल बॉडीज विभाग बनाता है हमारा यह काम नहीं है। लोकल बॉडीज विभाग इनको अगर बनवाता है तो वह ही इनको बनवाने की व्यवस्था करे। लेकिन अगर हम इनको सब जगह बनवा दें तो इससे कंजै गन और ज्यादा हो जाएगी।

**डॉ० गि गव भांकर भारद्वाज:** स्पीकर सर, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इस सड़क का आधा पो गन ही ऐसा है जहां पर यह काम होना है। दिनोद गेट से लेकर रेलवे गेट तक, कृष्णा कॉलोनी सब्जी मंडी चौक से लेकर रेलवे स्टे गन तक तो कोई कंजै गन नहीं है वहां पर वह सड़क चौड़ी है वहां पर किसी भी प्रकार गाड़ियों के खड़े होने में भी कोई दिक्कत नहीं है तो क्या मंत्री महोदय इस बारे में बताएंगे?

**कैप्टन अजय सिंह यादव:** स्पीकर सर, जैसा मैंने बताया कि हमारे अधिकारी इनसे इस बारे में बातचीत कर लेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर कंजै इन की समस्या नहीं है वहां पर फुटपाथ बनाने के बारे में हम विचार कर लेंगे लेकिन सारे मामले को ऐगजामिन करवाने के बाद ही मैं इस बारे में कोई आ वासन दे पाऊंगा।

**डॉ० विठ्ठल भांकर भारद्वाज:** स्पीकर सर, मैं कई बार अधिकारियों के साथ गया हूं। उन्होंने कहा है कि हम यह बना देंगे। उन्होंने इस बारे में फाईल बनाकर भी नीचे से ऊपर भेज दी थी। मैंने इस बारे में ई०आई०सी० से पता किया था। उनका कहना था कि यह काम तो एस०ई० ही कर सकता है क्योंकि यह पावर एस०ई० को ही है। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैंने पता किया तो पता चला कि उस समय के कमि नर श्री धर्मबीर जी के दफ्तर में यह फाईल थी, उस समय मैं उनके दफ्तर में चक्कर काटता रहा लेकिन वह फाईल नहीं मिली। अगर उस वक्त यह फाईल मिल जाती तो काम तभी हो जाता। स्पीकर सर, सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर वह काम रुका पड़ा है। इसके बन जाने के बाद गहर की सुंदरता और बढ़ेगी तथा लोगों को भी इसका फायदा होगा और इसके अनेक लाभ भी होंगे।

**कैप्टन अजय सिंह यादव:** स्पीकर सर, मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर फिजीबल होगा तभी मैं इस बारे में कुछ बात

कह सकूंगा। जब मैंने यहां पर एक बात कही है तो फाईल मेरे पास जरूर आएगी।

**डॉ० वि भंकर भारद्वाज:** स्पीकर सर, फाईल तो डिपार्टमेंट के पास है। मैं चाहूंगा कि अगर मंत्री जी उस फाईल को ढूंढवाकर ऐग्जामिन करवा लें तो इसके बाद सारी चीजें क्लीयर हो जाएंगी।

**श्री अध्यक्ष:** डॉक्टर साहब, मंत्री जी ने ऑन दि पलोर ऑफ दी हाउस ऐ योरेंस दी है कि वे इस मामले को ऐग्जामिन करवा लेंगे और ओफिसर्ज से सारा पता करवाएंगे। यदि फिजिबिलिटी हुई तो वे इस काम को करवा देंगे। डॉक्टर साहब, क्या यह फाईल आपके दफतर में तो नहीं रखी है?

**डॉ० वि भंकर भारद्वाज:** नहीं सर, यह डिपार्टमेंट के पास है।

### **Construction of Stadium at Kaithal**

**\*841. Shri Shamsheer Singh Surjewala:** Will the Minister of State for Sports and Youth Affairs be pleased to state:-

(a) whether a stadium is under construction at Kaithal, if so, the stage of the work upto 31.01.2008; and

(b) the details of the total cost of the project together with the time by which it is likely to be completed?

**Minister of State for Forest (Smt. Kiran Choudhary):**

(a) Yes sir, The District Level Sports Stadium is being constructed at village Patti Afgan near Kaihtal Town. In the 1<sup>st</sup> phase, construction of boundary wall has already been started and as on 31.01.2008 work has been completed on three sides. The balance work on boundary wall will be completed within two months.

(b) The project is likely to cost Rs. 750.00 lacs. However, it is not possible to indicate the time frame for completion of the project at this stage.

**श्री एस0एस0 सुरजेवाला:** स्पीकर सर, हमने यह बीस एकड़ प्राईम लैंड फ्री में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को दिवायी है। इस जमीन की बाजारी कीमत तकरीबन एक करोड़ रुपए से कम नहीं होगी। बहुत हिम्मत लोगों ने की है, हौंसला दिखाया है। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि क्या इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की योजना है, इसके अंदर सरकार ने कौन-कौन से इनडोर और आउटडोर गेम्ज प्लान किए हैं।

**श्रीमती किरण चौधरी:** स्पीकर सर, आप जानते ही हैं कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को हमारी सरकार ने बहुत बढ़ावा दिया है। इसके अंदर भी बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं and by the time it is completed, it will have 6 to 8 lanes in the 4 metres grass runing tack, two indoor halls of size not less than 40×25 metres, swimming pool, room with toilet, showere etcs., cross ventilation of multigen bay, training and physical conditioning equipment, sports hostel with 150 beds, with girls wing of 50 beds, quarters for

managers and coaches, hockey ground, football ground diving pool, volleyball courts, basketball courts, field for locally popular games, which is not included in the above games, जैसे कबड्डी और खो-खो। As, I said one or two playing fields for indigenous games like Kabaddi, Kho-Kho etc. will be provided alongwith the facilities like human performance laboratories, internal roads, boundary walls, water supply, electricity, office store, toilets etc. यह पूरा का पूरा इंडीजिनस प्लान है और हमारी सारी की सारी फ़ैसिलिटीज होंगी।

**श्री एस0एस0 सुरजेवाला:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूँ कि इसके लिए जो फंड हैं उसके बारे में इन्होंने जवाब दिया है— “However, it is not possible to indicate the time frame for completion of project.” इसके लिए फंड जो हैं जो इस वक्त नहीं है। क्या अपने डिपार्टमेंट से या हुडा से इस काम के लिए फंड प्रोवाइड करवाने का प्रबन्ध करेंगे ताकि यह काम हो जाए?

**Smt. Kiran Choudhary :** Mr. Speaker Sir, I would like to tell the Hon’ble Member that we have already provided Rs. 19 lakhs for the first phase and three side boundaries have been completed only. Only one side has been left. The Chief Architect has already submitted his plan and as soon as the estimators are received from the Panchyati Raj Department, we will be completing the others.

**श्री तेजेंद्र पाल सिंह मान:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मेरा पैतक

गांव घोघड़ीपुर है जो कि निसिंग ब्लॉक में पड़ता है। इसमें स्टेडियम की प्रपोजल थी बाद में यह पास हो गया था और टैंडर भी हो गए थे, just in one day. it vanished from the total scheme of things. मैंने इस बारे में मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से रिफरेंस भी भेजा है लेकिन आज तक उसका जवाब नहीं मिला। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह पास हो गया है क्योंकि हमारे गांव में वह जमीन यूं की यूं पड़ी है क्या विभाग इस बारे में ए योर करेगा कि वहां स्टेडियम बनेगा?

**Smt. Kiran Choudhary :** Mr. Speaker Sir, I would like to tell the Hon'ble Member that we have already constructed about 155 block level stadium and as yet we have not received any of these requisitions. If we will receive, we will definitely look into it.

**श्री तेजेंद्र पाल सिंह मान :** इसके तो टैंडर हो गए हैं और किसी ब्लॉक में नहीं बना है, यहीं बनना है।

**श्रीमती किरण चौधरी :** आपके प्र न का मैं बता देती हूं। यह स्टेडियम करनाल ब्लॉक में पड़ता है।

**श्री तेजेंद्र पाल सिंह मान :** करनाल में नहीं बल्कि निसिंग ब्लॉक में पड़ता है।

**Smt. Kiran Choudhary :** All blocks have been covered in Karnal. एक स्टेडियम हर एक ब्लॉक में बनाना है that thing has already been done.

**Shri Tejinder Pal Singh Mann:** Sir, this was passed. This was totaly regularized. Tenders were called. Hon'ble Chief Minister has also made the reference about this.

**श्रीमती किरण चौधरी :** इसको दिखवा लेंगे। अगर पास हो गया होगा तो दिखवा लेंगे। वैसे सारे ब्लॉक्स में हम कर चुके हैं लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो हम जरूर दिखवा लेंगे और इसकी इजाजत लेकर इस काम को करवाएंगे।

**श्रीमती सुमिता सिंह:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो हमारे सरकारी कोच हैं वे स्टेडियम में बच्चों की टीम तैयार नहीं कराते और न ही सरकारी स्कूलों में जाते हैं। जो बड़े-बड़े स्कूलज हैं जो एफोर्ड कर सकते हैं वहां पर जाकर वहां से ही पैसे लेते हैं और सरकार से भी पैसे लेते हैं और वहां जाकर के बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं जबकि इनको स्टेडियम में या सरकारी स्कूलों में जाकर ट्रेनिंग देनी चाहिए। इस बारे में सरकार का एक सर्कुलर है उसको मैंने पढ़ा है उसमें लिखा है कि जहां बड़ी टीम उपलब्ध हो वहां हमारे कोच जाकर ट्रेनिंग दे सकते हैं उसी सर्कुलर का वे मिसयूज करते हैं। मेरे घर के पास एक सरकारी स्कूल है वहां पर ये कोच बहुत ही कम जाते हैं। क्या मंत्री महोदया इस बात से वाकिफ हैं?

**श्रीमती किरण चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, मैं मँबर साहिबा को बताना चाहूंगी कि इस बारे में इन्होंने मुझसे पहले भी बात की



थी और हमने जांच पड़ताल भी की है। आप जहां पर बताएंगी कि ऐसा कहीं हो रहा है तो उस पर भी नजर रखेंगे।

**श्रीमती सुमिता सिंह :** अध्यक्ष महोदय, करनाल में किसी भी स्पोर्ट्स स्टेडियम में न तो योगा का और न ही बास्केट बाल और न ही किसी दूसरे खेल के कोचिज स्टेडियम में जाते हैं।

**श्रीमती किरण चौधरी:** माननीय सदस्या इस बारे में लिखित में भिजवा दें हम उनके खिलाफ एक्शन जरूर लेंगे।

**श्री रामकिशन फौजी :** अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने प्रत्येक गांव में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाये हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि स्टेडियम तो हर गांव में तैयार हो गये हैं लेकिन न तो किसी कोच की नियुक्ति की है, न ही किसी माली की नियुक्ति की है जो उन स्टेडियमों की देखरेख कर सकें। इसलिए उन स्टेडियमों की हालत खराब होती जा रही है। क्या कोचिज और माली की नियुक्ति का प्रबन्ध इन स्टेडियमों में करने का काम किया जायेगा ताकि बच्चों को सुविधा मिल सके।

**श्रीमती किरण चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह अलग प्रश्न है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि हमारे पास इस समय 21 कोचिज की वैकेन्सिज हैं इनको भरने के लिए हम एडवर्टाईजमेंट करने जा रहे हैं। जहां तक इन स्टेडियमों की

देखरेख के लिए माली, चौकीदार और स्वीपर का सवाल है, इनके लिए जल्द ही पोलिसी डिजीजन लिया जा रहा है।

**श्री अमीर चन्द मक्कड़ :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जैसा कि हर ब्लॉक में एक-एक स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव सरकार ने किया है। हांसी के दो ब्लॉक हैं, क्या वहां पर कोई स्टेडियम बनाने के लिए कोई मामला सरकार के विचाराधीन है, अगर है तो वह कब तक बनकर तैयार हो जाएगा। हांसी भाहर में भी स्टेडियम की जरूरत है।

**श्रीमती किरण चौधरी :** स्पीकर महोदय, सरकार ने हर ब्लॉक में एक स्टेडियम बनाने का काम किया है। अगर किसी जगह जरूरत पड़ी तो अगली प्लान में इसके बारे में विचार कर लिया जायेगा।

**आई0जी0 भोर सिंह :** स्पीकर महोदय, मेरे हल्के जुलाना ब्लॉक में एक स्टेडियम सैंकान हुआ था और लगभग दो साल हो गये हैं लेकिन वह अब तक आधा ही बना है और बीच में ही रुका पड़ा है। 50 लाख रुपये सरकार द्वारा स्टेडियम बनाने के लिए मंजूर किये गये थे। मैं मंत्री महोदया से यह पूछना चाहता हूँ कि यह स्टेडियम कब तक कम्प्लीट हो जायेगा ? क्या मंत्री महोदया इस बारे में एकान लेंगी ?

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि जुलाना हलके में नन्दगढ़ में स्टेडियम बन रहा है उसको हम जल्दी ही कम्प्लीट करवा देंगे।

### **Selection of Environment Engineer**

**\*886. Shri Karan Singh Dalal :** Will the Minister of State for Environment be pleased to state :

(a) whether any case of fraudulent selection and appointment of Environment Engineers in the Haryana State Pollution Control Board has been detected during the period 2004 to 2007; and

(b) If so, the action taken against the delinquents?

**Minister of State for Forest (Smt. Kiran Choudhary) :**

(a) Yes, Sir

(b) FIR No. 12 dated 04-09-2007 was lodged at Police Station, State Vigilance Bureau, Panchkula against all the accused numbering eight.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूँ कि यह जो एन्वायर्नमेंट इंजीनियरिंग विभाग ने लिये हैं इसके लिए कितनी एप्लीकेटिंस आई थी, उनमें से कितने कंडीडेट्स इलीजिबल भाँट लिस्ट किये और जो इन्टरव्यू लिया वह कितने कंडीडेट्स का लिया ?

**श्रीमती किरण चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, 4 एन्वायर्नमेंट इंजीनियर्स की नियुक्ति के लिए रिक्विजी अन भेजी गई थी जिसके लिए 132 एप्लीके ांज प्राप्त हुई थी उसके बाद इन पोस्टों को फिल अप किया गया।

**श्री कर्ण सिंह दलाल :** अध्यक्ष महोदय, ऐसा तो नहीं था कि भारत लिस्ट 120 किए हों और इंटरव्यू के लिए 121 कैंडीडेट्स को बुलाया हो। मंत्री महोदया अपने नोट फोर पैड को चैक कर लें।

**श्रीमती किरण चौधरी :** अध्यक्ष महोदया, इस बारे में मैं चैक करके माननीय सदस्य को बता दूंगी, I don't have the information right now.

**श्री कर्ण सिंह दलाल :** अध्यक्ष महोदय, जो एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई है क्या यह सही है कि चौटाला जी के राज में प्रदे ा के पर्यावरण को खराब करने के लिए जान-बूझकर के अयोग्य उम्मीदवारों का रि वत लेकर के, पैसा लेकर के जिनकी उम्र ज्यादा थी, उनको इस विभाग में भर्ती किया गया था ? अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 4.9.2007 को यह एफ0आई0आर0 दर्ज कराई हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से आ वासन चाहूंगा कि एफ0आई0आर0 दर्ज कराने से काम नहीं चलेगा जो लोग वक्त इस भर्ती में भुमार थे। इन भर्तियों को करने में जो शामिल थे वे हैं उस वक्त के मुख्यमंत्री श्री ओम प्रका ा चौटाला जी। जिनको ये नियुक्तियां दी गई हैं आज

उनकी क्या स्थिति है क्योंकि एफ0आई0आर0 दर्ज करने से काम नहीं चलता ? क्या मंत्री जी बताएंगे कि संविधान की धारा 311 या किसी भी सरकार के विभाग के कानून के मार्फत जो ऐसी धोखे से नौकरियां ली गई हैं उनको तुरन्त प्रभाव से नौकरियों से बाहर निकाला जाएगा और जो सैलरीज इन्होंने ली हैं उनको उनसे वापस वसूला जाएगा ? मंत्री जी इस बारे में बताने की कृपा करें ।

**श्रीमती किरण चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि इस केस में विजीलेंस इन्कवायरी इंस्टीच्यूटिड है और तीन आदमी जिनके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज की गई है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। इन्कवायरी में आगे जो भी निकलेगा उसके अनुसार सख्ती से कार्यवाही की जाएगी क्योंकि जो गलत काम किया गया है, उसमें किसी को कतई माफ नहीं किया जाएगा।

**श्री कर्ण सिंह दलाल:** अध्यक्ष महोदय, विभाग ने एक तरफ तो इनके खिलाफ मुकदमें दर्ज करा दिए हैं लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जब विभाग के नोटिस में आ चुका है कि ये नियुक्तियां ही गलत हैं तो इसमें विजीलेंस इन्कवायर क्या करेगी। यह तो लटकाने वाली बात है। क्या मंत्री महोदय इस बात के लिए आ वस्तु करेंगी कि जब ये नियुक्तियां ही गलत हैं तो न केवल उनको नौकरियों से हटायेंगे बल्कि जिन्होंने नौकरियों के लिए उनको नियुक्ति पत्र जारी किए हैं क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही होगी क्योंकि जो उस वक्त के अधिकारी थे और जो

जानते थे कि उनकी उम्र ज्यादा है या ये अयोग्य हैं फिर भी उनको नियुक्ति पत्र दे दिए तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

**श्रीमती किरण चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बता चुकी हूँ कि यह विजीलेंस इन्क्वायरी पूरी तरह से इंस्टीच्यूटिड है और इस इन्क्वायरी में जिनका भी नाम आएगा उनके खिलाफ पूरी कार्यवाही की जाएगी। जहां तक विभाग का सवाल है, उन तीनों को हम सस्पेंड कर चुके हैं और जिन्होंने इस बात को प्वायंट आउट नहीं किया उनको भी भागे काज नोटिस जारी कर दिए गए हैं और उनको चार्ज फिट कर दिया गया है।

**श्री कर्ण सिंह दलाल :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि इन नियुक्तियों में जो एस0एसी0-ए और एस0सी0-बी कैटेगिरी के लिए स्थान थे क्या उन स्थानों की नियुक्तियां और उनको सिलैव इन इन कैटेगिरीज के मुताबिक हुए हैं और अगर नहीं हुए तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी ?

**श्रीमती किरण चौधरी :** अध्यक्ष महोदय जो एस0सी0-ए कैटेगिरी है one genettleman Sh. Kapoor Singh who was belong to S.C. उसको छोड़ दिया गया है क्योंकि 5 साल का एज रिलेक्से इन का प्रावधान सरकार के सर्विस रूलज में है।

**श्री कर्ण सिंह दलाल :** अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने दलित और गरीब व्यक्ति जो योग्यता रखते हैं उनके साथ अन्याय किए हैं और यह बात मंत्री महोदया ने बताई भी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूँ कि जो ये नियुक्तियां इन्होंने की हैं और इसमें अयोग्यता पाई और जैसा एस0सी0-ए कैटेगिरी के बारे में बताया गया है कि इन्होंने 8 ऑफिसर्स के खिलाफ मुकद्दमें दर्ज किए हैं तो ये क्या फाउ मानते हैं और जो एफ0आई0आर0 दर्ज हुई है उसमें क्या फाउ है ?

**श्रीमती किरण चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, फाउ यह है कि जब एक्वीजि इन नोटिस भेजा गया तो जो उम्र थी that was between 17 years to 40 years. लेकिन जब उनकी भर्ती की गई उस समय उनकी उम्र 40 साल से उपर थी, उस समय सरकार ने लिखित में पोल्यू इन कंट्रोल बोर्ड को भेजा कि इनकी नियुक्तियां कराई जाएं, अमरजैसी लेवल पर कराई जाएं। आप जानते हैं और हम भी जानते हैं कि यह गलत काम हुए हैं इसलिए विजीजैस इन्क्वायरी इंस्टीच्यूटिड हुई है। जो गलत काम हुए हैं उनके उपर सखी से कार्यवाही हो रही है। रिक्रूटमेंट्स जिनकी की गई है उनकी सस्पें इन कर दी गई है और इन्क्वायरी में जो भी निकलेगा उस हिसाब से कार्यवाही की जाएगी ताकि आने वाले समय में यह काम दोबारा न हो पाए और इस केस पर हमारी पूरी नजर है।

**श्री फूल चन्द मुलाना :** अध्यक्ष महोदय, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन की सिलैबन हो और चाहे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की सिलैबन हो इनमें से जो तथ्य सदन के सामने आए हैं इन सब में हरिजनों के साथ ज्यादती की गई है तो क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि वह सरकार और उस वक्त के मुखिया एंटी हरिजन थे ?

**श्रीमती किरण चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, मुलाना जी ने जो सवाल किया है उसका मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। But it is very obvious otherwise these things could not have been done.

**वित्त मंत्री (श्री बीरेंद्र सिंह) :** अध्यक्ष महोदय, मुलाना जी यदि उनकी पार्टी में होते तो इनको स्वयं ही पता लग जाता कि वे कैसे लोग हैं।

**श्री कर्ण सिंह दलाल :** अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने यह मान लिया है कि जिनकी भर्ती की गई थी उनकी उम्र ज्यादा थी और एस0सी0 कैटेगरी को भी इग्नोर किया गया। क्या मंत्री जी सदन में आवासन देंगी कि तुरंत प्रभाव से पहले उनकी नौकरी खत्म की जायेगा और बाद में विजीलेंस इन्क्वायरी चलती रहेगी ?

**तारांकित प्रश्न संख्या – 842**

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री एस0एस0 सुरजेवाला सदन में उपस्थित नहीं थे।)



## **Damage Caused Due to Severe Cold**

**\*859. Dr. Sita Ram @**

**Shri Radhey Shayam Sharma**

**Shri Somvir Singh**

**Shri Naresh Yadav** : will the Minister of State for Revenue and Disaster Management be pleased to state whether it is a fact that mustard and different vegetabel crops in the State have been damaged due to severe cold/frost during financial year 2007-2008; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to provide financial assistance to the affected farmers ?

**राजस्व राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री जिंदल)** : जी हां। तथापि वित्तीय सहायता दिए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि सर्दी/पाले के कारण हुआ नुकसान आपका राहत कोश के प्रावधान के अधीन कवर नहीं होता।

**डॉ० सीता राम** : अध्यक्ष महोदय, इस बार बहुत भारी ठंड पड़ी है जिसकी वजह से किसानों की फसलों को विेशकर सरसों, गेहूं और सब्जियों को भारी नुकसान हुआ है तथा किसानों को काफी वित्तीय घाटा हुआ है। क्या सरकार उन किसानों को कम्पन्सेट करने के लिए विचार कर रही है जिनकी फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान ठंड की वजह से हुआ है ?

**श्रीमती सावित्री जिंदल** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि बारहवें

वित्त आयोग की सिफारिशों पर जो आपदा राहत कोश की स्कीम कार्यान्वित की गई है उसमें केवल चक्रवात, सूखा, भूकम्प, आग, बाढ़, सूनामी, ओलावृष्टि, भू-स्खलन, हिम-स्खलन, बादल फटना तथा महामारी से फसलों के हुए नुकसान से प्रभावित व्यक्तियों को ही भीष्म राहत प्रदान करने का प्रावधान है। भीत लहर तथा पाले से हुआ नुकसान इस स्कीम के अधीन कवर नहीं होता। लेकिन जनवरी व फरवरी, 2008 में फसलों को भीत लहर से काफी मात्रा में नुकसान के मध्यनजर दिनांक 27.2.2008 को हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने केन्द्रीय कृषि मंत्री जी को भीत लहर को आपदा राहत कोश स्कीम के अधीन प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल करने का अनुरोध किया है। इसके साथ-साथ यह भी अनुरोध किया गया है कि हरियाणा राज्य को कम से कम 125 करोड़ रुपये की तत्काल सहायता प्रदान की जाए ताकि प्रभावित किसानों को आपदा राहत कोश स्कीम के अनुसार राहत दी जा सके।

**श्री फूल चंद मुलाना :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जैसे मौजूदा सरकार ने प्रयास किया है कि भीत लहर और पाले से फसलों को होने वाले नुकसान को भी प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किया जाये। इस बारे में हमारे एम0पी., चौधरी दीपेन्द्र हुड्डा जी भी प्रधान मंत्री जी से मिले हैं। क्या पिछली सरकार के एम0पीज0 ने उस समय की केन्द्र की एन0डी0ए0 सरकार से मिलकर

कोि । । की थी कि भीत लहर तथा पाले से जो फसलों को नुकसान होता है उसे प्राकृतिक राहत कोश में भामिल किया जाये ? (विघ्न)

**श्री सोमवीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में और हमारे एरिया में जो बागवानी के पौधे थे उनको और सरसों आदि की फसलों को ठंड से भारी नुकसान हुआ है। क्या मंत्री महोदया ठंड से हुए फसलों के इस नुकसान को प्राकृतिक आपदा में भामिल करने का आवासन देंगी ?

**श्रीमती सावित्री जिंदल :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहती हूं कि जैसा मैंने अभी बताया है कि हरियाणा सरकार द्वारा केंद्र सरकार को भीत लहर और पाले को आपदा राहत कोश स्कीम में भामिल करने का अनुरोध किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा भीत लहर और पाले को आपदा राहत कोश में भामिल करने का अनुरोध किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा भीत लहर और पाले को आपदा कोश में भामिल कर लिये जाने के बाद ही प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकेगी।

**Mr. Speaker :** Hon'ble members now the Question Hour is over.

**सदन की एक समिति का गठन**

**सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :** स्पीकर सर, मैंने 18.03.2008 को एक क्वै चन के जवाब में बताया था कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान इरीगे इन डिपार्टमेंट की बहुत सारी बे तक़ीमती जमीन अपने खास और चहेते लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए गलत तरीके से बेची गई थी। इस बारे में मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि यह टोटल 27 कैनल रेस्ट हाउसिंग की जमीन बेची गई थी जो कि तक़रीबन 127.16 एकड़ जमीन थी और जिसको मात्र 3.83 करोड़ रुपये में बेच दिया गया था। इसके साथ-साथ इरीगे इन डिपार्टमेंट की 776.78 एकड़ जमीन थी जिसमें कैनल रेस्ट हाउसिंग भी इंकलूड हैं ये टोटल 145 साइट्स थी जोकि मात्र 30.78 करोड़ रुपये बेच दी गई। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के आते ही जब मैंने सिंचाई मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला और तत्पश्चात् जब 05 अप्रैल, 2005 को मैं सिंचाई भवन में अपने अधिकारियों की रिव्यू मीटिंग ले रहा था तो मीटिंग के दौरान जब सोनीपत और कैथल के 8 रैस्ट हाउसिंग की ऑक्शन की बात मेरे नोटिस में आई तो मैंने उसी वक्त तुरंत प्रभाव से इन तथाकथित 8 रैस्ट हाउसिंग की ऑक्शन पर रोक लगा दी थी। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें कई ऐसे लकूनाज हैं जिसके तहत इसमें ऐसे बहुत से रैस्ट हाउसिंग थे जिनको लगभग रिजर्व प्राईस पर ही बचे दिया गया। इनमें मलिकपुर कैनल रैस्ट हाउस, करनाल की रिजर्व प्राईस रखी गई 2.20 लाख रुपये प्रति एकड़ और उसे 2.53 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से बेच दिया। इस प्रकार से पोपड़ा कैनल रेस्ट

हाउस, करनाल की रिजर्व प्राईस थी। 3.07 लाख रुपये प्रति एकड़ और उसे 3.44 लाख रुपये प्रति एकड़ में ऑक इन कर दिया, ज्ञानी भट्टा, करनाल की रिजर्व प्राईस रखी गई 2.83 लाख रुपये प्रति एकड़ और उसे 3.14 लाख रुपये प्रति एकड़ में ऑक इन कर दिया गया, डाटा रैस्ट हाउस, हिसार की रिजर्व प्राईस रखी गई 1.90 लाख रुपये प्रति एकड़ और दो 2.30 लाख रुपये प्रति एकड़ में ऑक इन कर दिया गया, इसी प्रकार से थुराना रैस्ट हाउस, हिसार की रिजर्व प्राईस रखी गई 1.70 लाख रुपये प्रति एकड़ और उसे 1.73 लाख रुपये प्रति एकड़ में ऑक इन कर दिया गया, इसी प्रकार से हिसार के अन्दर जीवड़ा का कैनल रैस्ट हाउस है उसकी रिजर्व प्राईस 1.75 लाख रुपये प्रति एकड़ रखी गई और उसको 1.78 लाख रुपये प्रति एकड़ में बेच दिया गया। इसी प्रकार से झज्जर में धांधलान है उसकी रिजर्व प्राईस 1.35 लाख रुपये प्रति एकड़ रखी गई थी और उसे 1.53 लाख रुपये प्रति एकड़ में पिछली सरकार ने ऑक इन करवा दिया, इसी प्रकार से जींद के अंदर खरल रैस्ट हाउस की रिजर्व ऑक इन रखी गई 2.25 लाख रुपये प्रति एकड़ और उसको 2.29 लाख रुपये प्रति एकड़ में ऑक इन कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, इससे साफ जाहिर होता है कि जो 27 रैस्ट हाउसिज थे उनको इन्होंने अपने फायदे के लिए कौड़ियों के भाव बेच दिया। वैसे तो इन्होंने 35 रैस्ट हाउसिज एवं कैनल रैस्ट हाउसिज को बेचने का लक्ष्य रखा था लेकिन उनमें से हमारी सरकार ने आते ही 8 रैस्ट हाउसिज की ऑक इन को समाप्त कर दिया था। यह मैं विशेष तौर पर

आपको बताना चाहता हूँ। बाकी इसमें आगे निर्णय आपको लेना है कि ऐसा करके जिन लोगों द्वारा इस प्रकार की अनियमिततायें की गईं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाये। ऐसा करके पिछली सरकार में यह हुआ था कि इन्होंने कौड़ियों के भाव में जमीनें बेच दी थी जो कि स्टेट के लिए असैट्स होती हैं और यह बात भी मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि उस समय प्रदे 1 के उपर ऐसा क्या वित्तीय संकट आ गया था कि इस प्रकार से इन्होंने रैस्ट हाउसिज और सरकार की जो बहुत ही कीमती जमीन थी उसको मात्र थोड़े से पैसों में अपने चहेतों को और इंडीविजुअल लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए रिजर्व प्राईस से थोड़े-थोड़े से पैसे बढ़ाकर बेच दिया। मैं इससे संबंधित सारा रिकार्ड आपके समक्ष पे 1 करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, इसमें यमुनानगर और करनाल के अन्दर दो साईट्स थी जिनकी रिजर्व प्राईस 1.05 लाख रुपये प्रति एकड़ रखी गई थी और रिजर्व प्राईस पर ही यानि 1.05 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ही बचे दिया। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से इन्होंने जो अनियमिततायें की उसके हमारे पास सारे आंकड़े हैं मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ी भारी कमियां रही हैं। सर, यह मामला जब हमारे पास आया उसी वक्त हमने इसके उपर रोक लगा दी थी। सरकार के असैट्स इन्होंने इस प्रकार से औने-पौने दामों में अपने चहेतों को बेचे हैं। कहीं पर तो रिजर्व प्राईस पर ही बेच दिये गये और कहीं पर दो-चार हजार रुपये उपर करके बेच दिये गये। अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत बड़ा घोटाला सिंचाई विभाग में किया गया है। इसी प्रकार

से बी० एण्ड आर० विभाग में भी कुल 28.65 एकड़ जमीन सरप्लस दिखा कर ऑक्शन द्वारा मात्र 87.94 लाख रुपये में बेच दी गई। उसमें से कुछ जमीन एन०जी०ओ० को दी भी गई है। 6 साइट्स ऐसी हैं जो 10.80 एकड़ की हैं उसको भी इन्होंने ऑक्शन दिखा कर बेच दिया है। एक जमीन 0.35 एकड़ हांसी में एक एन०जी०ओ० जाट सभा को दी है। अध्यक्ष महोदय, ये सारे आंकड़े बताते हैं कि किस प्रकार की गड़बड़ियां पिछली सरकार ने की हैं। ये तो सिर्फ थोड़ी सी बातें सामने आई हैं अगर हम इसकी तह तक जायेंगे तो और विभागों में भी इसी प्रकार से घपले उजागर होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने तो ये सारे तथ्य आपके सामने रख दिये हैं जब निर्णय आपको करना है कि आप कोई हाउस की कमेटी गठित करेंगे या कोई और निर्णय लेंगे।

**श्री अध्यक्ष :** इसमें सरकार क्या एक ऑक्शन लेना चाहती है ?

**कैप्टन अजय सिंह यादव :** अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो एक डिप्टी कमीशनर और एम०डी०एम० की कमेटी बनाकर देने की कोशिश की थी। मैंने तो आपके सामने तथ्य रख दिये हैं। अब आपको निर्णय करना है कि हाउस कमेटी बनाई जाये या कोई और निर्णय करना है। मेरे ख्याल से तो हाउस कमेटी बनाना ही बेहतर रहेगा।

**श्री अध्यक्ष :** यह एक एग्जिक्यूटिव मामला है। आप अपने लेवल पर ही कोई कमेटी बनाकर यह निर्णय करें कि जितनी

ऑक् इन हुई हैं क्या उनमें ओपन ऑक् इन हुई है, क्या कोई कंसीलमेंट उसमें हुई है, क्या उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई तथा क्या-क्या कारण थे, कौन-कौन आदमी किससे जुड़े हुए थे तथा क्या आपकी लीगलिटी में ये ऑक् इन कैंसिल हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं ?

**कैप्टन अजय सिंह यादव :** अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इनके सारे केसिज की इन्क्वायरी सी0बी0आई0 कर ही रही है।

**श्री अध्यक्ष :** स्टेट की इनवैस्टीगे इन ऐजेन्सीज हैं, उससे आप यह इन्क्वायरी करवा सकते हैं। जो आपकी स्टेट ऐजेन्सीज हैं उनसे करवायें।

**श्री कर्ण सिंह दलाल :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर लगी है कि रेवाड़ी जिले में मुकन्दरपुर बसई एक गांव है।

**श्री अध्यक्ष :** दलाल साहब, माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ कह रहे हैं पहले उनकी बात सुन लें।

**बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :** अध्यक्ष महोदय, एक और विशय पर चर्चा चल रही थी और श्री मांगे राम गुप्ता जी ने तथा कैप्टन अजय सिंह यादव जी ने उस समय कहा था कि हम पूरी जानकारी एकत्रित करेंगे। कैप्टन अजय सिंह यादव जी ने तो पूरी जानकारी एकत्र करके सदन के सामने रखी दी है।



अध्यक्ष महोदय, because the issue was raised in the House श्री मुलाना, साहब ने, स्थानीय मंत्री जी ने और दूसरे कई साथियों ने भी यह मुद्दा उठाया था। यह पूरे हाउस का ही संकर्न था। अध्यक्ष महोदय, इसमें दो प्र न उठाये गये थे। पहला तो यह था कि कौन-कौन सी वे जमीनें हैं जिनको इन्होंने औने-पौने दामों पर अपने चहेतों को ऑक् ान करवाया है ? चाहे वह सिंचाई विभाग की थी, चाहे बी० एण्ड आर० विभाग की थी, चाहे स्थानीय निकाय की थी या पंचायती राज संस्थानों की जो चौधरी देवीलाल इंस्टीच्यू ांस को फी में दे दी गई या औने-पौने दामों में ऑक् ान कर दी गई। इसलिए sir, this was concern of the House and for that reason Minister has also made a statement thereon. I will request you that हाउस कमेटी बना दें तथा डिपार्टमेंट को सम्मन भेज दें, पूरी रिपोर्ट आ जायेगी और उसके बाद जो हाउस निर्णय करेगा, सरकार उसके उपर कार्यवाही करेगी। पहले सभी विभागों की रिपोर्ट आ जाएगी और हाउस की एक कमेटी आप बना दें। स्पीकर सर, वह सारी जानकारी उसके अन्दर आ जाएगी। आदरणीय मुलाना साहब यहां पर बैठे हुए हैं, इनके नेतृत्व में हाउस की एक कमेटी का गठन हो जाए। जो सदस्य आप उचित समझें उनको इस कमेटी के सदस्य बना दें। अध्यक्ष महोदय, दलाल साहब ने यह मुद्दा रेज किया था वे इस कमेटी के अन्दर एक मेंबर हो जाएं और दूसरे माननीय साथी इस कमेटी में आ जाएं। भारीय जनता पार्टी के साथी आ जाएं और लोक दल से भी साथी इस कमेटी में आ जाएं। अध्यक्ष महोदय,

आप इस कमेटी में इन्दौरा साहब को ले लें या श्री ओम प्रकाश चौटाला जी को ले लें ताकि वे अपना पक्ष भी कमेटी के अन्दर रख सकें।

**श्री अध्यक्ष :** चौटाला साहब जिन कमेटियों के सदस्य हैं उनकी मीटिंगों में भी नहीं आते हैं। बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की किसी भी मीटिंग में वे आज तक नहीं आए। हाउस की ही एक और कमेटी बनी थी वे उस कमेटी की मीटिंग में भी कभी नहीं आए। चाहे कितनी भी कमेटियों में उन्हें ले लें अगर उन्होंने मीटिंग में नहीं आना है तो कमेटी में लेने का क्या फायदा है ?

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला :** अध्यक्ष महोदय, कल भी वे हाजिरी लगा कर चले गए और उस कमेटी में भी नहीं आए जो लोन वेवरज के लिए आपने आदरणीय श्री मांगे राम गुप्ता जी की अध्यक्षता में बनाई थी।

**श्री नरेन्द्र मलिक :** अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा ईशू है और इसके बारे में सभी को पता है। आम पब्लिक को भी पता है कि किस प्रकार से अपनी सरकार के वक्त में इन लोगों ने अपने चहेतों या रिश्तेदारों या उन लोगों के द्वारा जो इनसे मिलते-जुलते रहते थे, सरकारी प्रापर्टी को खुर्द-बुर्द किया है। मेरा निवेदन यह है कि आप कमेटी तो बना दें लेकिन उस कमेटी का रिजल्ट दिखाना चाहिए। अगले हाउस के सेशन से पहले इस कमेटी की रिपोर्ट आ जानी चाहिए और डिपार्टमेंट से भी पूरी

रिपोर्ट आ जानी चाहिए और उस पर कोई न कोई लीगल ऐक्टान भी होना चाहिए।

**डॉ० सु गील इन्दौरा** : स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री जी से एक मुद्दे की बात कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के हिसाब से विभाग अपनी जरूरत के अनुसार जमीन खरीदता भी है और बेचता भी है। विभागों में इस तरह की परम्पराएं और नियम भी हैं कि विभाग अपनी आवश्यकता के मद्देनजर अगर कहीं पर किसी जमीन की यूटीलिटी नहीं है तो उस जमीन को बेच देता है। अगर जमीन की जरूरत है तो वह जमीन खरीद लेता है। अगर मंत्री जी को ऐसा लगता है कि कहीं पर ऐसी कोई अनियमितता हुई है तो वे इसकी विभागीय जांच करवा लें। वे अपने आप को इतना असहाय क्यों मान रहे हैं ? वे स्वयं मंत्री हैं, इरीगे टन विभाग के मंत्री यह बताएं कि वे इतने असहाय क्यों हैं, वे इस बारे में विभागीय जांच करवा कर सारे मामले का पता करवा सकते हैं। (विघ्न) स्पीकर सर, इसमें विभागीय जांच हो जाए तो सारा मामला सामने आ जाएगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय इन्दौरा साहब से यह जानना चाहता हूँ कि ये हाउस की कमेटी से घबराते क्यों हैं, ये हाउस की कमेटी से डरते क्यों हैं ? ये इस कमेटी के सदस्य बनें तो सारी बात सामने आ जाएगी।

अगर हाउस की कमेटी बन जाती है तो लोक दल के साथी और इन्दौरा जी को इतनी घबराहट क्यों हो रही है ?

**कैप्टन अजय सिंह यादव :** अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो बात रखी है कि सरकार जमीन बेचती भी है। मैं इनसे यह जानना चाहता हूँ कि सरकार के ऊपर क्या ऐसी वित्तीय संकट आ गया या सरकार को इतना भारी घाटा हो गया कि सरकार ने जमीन बेचने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जमीनें दी भी हैं। कई दफा धर्मशाला बनाने के लिए, कॉम्यूनिटी सेंटर बनाने के लिए सरकार जमीन देती है लेकिन प्राईवेट लोगों को जमीन देना और वह भी रिजर्व प्राईस पर ऑक् इन करके जमीन देना ठीक नहीं था। रिजर्व प्राईस से ऑक् इन की राशि में कुछ न कुछ तो फर्क होना चाहिए लेकिन जमीन को रिजर्व प्राईस पर ऑक् इन में बेच देना या रिजर्व प्राईस से 3-4 हजार रुपये ऊपर ऑक् इन कर देना भाक जाहिर करता है। स्पीकर सर, सही बात तो यह है कि इनकी नीयत में खोट है। कोई भी आदमी पब्लिक यूटिलिटी के लिए किसी संस्था को जमीन देता है, पंचायत भी जमीन देती है और धर्म शाला वगैरा बनाने के लिए गवर्नमेंट भी जमीन दे देती है। कई सभाओं को भवन के लिए भी सरकार जमीन दे देती है लेकिन यह जमीन पब्लिक परपज के लिए होती है लेकिन इन्होंने तो इन्डिविजुअल जमीनें दी हैं। इसके बारे में जो बात माननीय सुरजेवाला जी ने रखी है कि हाउस की एक कमेटी आप गठित कर दें ताकि जो सही बात है वह सामने आ सके। आप इस

कमेटी को टाईम बाउंड कर दें कि इतने पीरियड में यह अपनी रिपोर्ट दे देंगी।

**श्री अध्यक्ष :** ऑनरेबल सदस्यगण, जैसे मलिक साहब का सुझाव था कि नैक्सट सै इन तक इस कमेटी की रिपोर्ट आ जाए इसमें मुलाना साहब की चेयरमैनशिप में कमेटी का गठन कर देते हैं जो अगले सै इन तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

**कैप्टन अजय सिंह यादव :** अध्यक्ष महोदय, नैक्सट सै इन तक तो बहुत समय हो जाएगा। यदि यह रिपोर्ट थोड़ा जल्दी पे टा हो तो ठीक रहेगा।

**श्री अध्यक्ष :** नैक्सट सै इन ही ठीक है। श्री फूलचंद मुलाना जी इस कमेटी के चेयरमैन होंगे, कर्ण सिंह दलाल, श्रीमती सुमिता सिंह, श्री ओम प्रकाश चौटाला, श्री राधे याम भार्मा अमर इसके मैम्बरज होंगे।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला :** अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि श्री तेजेंद्र पाल सिंह मान, श्री नरेण्डा मलिक या श्री राम कुमार गौतम जी में से किसी एक को इस कमेटी में ले लिया जाए।

**श्री अध्यक्ष :** ठीक है, श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान तथा श्री नरेण्डा मलिक जी के नाम भी इस हाउस कमेटी में शामिल कर दिये जाएं।

**डॉ० सु गील इन्दौरा :** स्पीकर साहब, इस बारे में विभाग अपने आप में सक्षम है, तो फिर कमेटी के गठन की क्या जरूरत है। (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष :** क्या आप इस बारे में हाउस में वोटिंग करवाना चाहते हैं कि कमेटी का गठन न किया जाए ? ( गोर एवं व्यवधान) Keeping the sense of the House, I constituted the Committee. (Noise & interruption)

**मुख्यमंत्री (श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा) :** अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी इन्दौरा जी कमेटी के बनने से क्यों घबराते हैं ? इन्दौरा जी, हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। डैमोक्रेसी का मतलब यह है कि हम आप लोगों को मौका देंगे। (विघ्न) हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी से काम हो इसलिए हम जल्दबाजी में कोई ऐकान नहीं लेना चाहते हैं। हमारी बायस्ड ओपीनियन नहीं है। हम सब की सलाह से काम करना चाहते हैं और हाउस की कमेटी बनने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ( गोर एवं व्यवधान)

**डॉ० सु गील इन्दौरा :** अध्यक्ष महोदय, जब यह सरकार कार्यवाही करने के लिए सक्षम है तो ये कमेटी क्यों बना रहे हैं। मैं इस कमेटी के बनने का विरोध करता हूँ। ( गोर एवं व्यवधान)

**Mr. Speaker :** I was the man of this opinion that जब यह बात आई थी कि स्टेट एजेंसी नहीं है तो इस बारे में मैंने यह कहा था कि स्टेट की इन्वैस्टीगेशन एजेंसी है और उनसे ही इन्वैस्टीगेशन करवा लें। But after keeping the sense of the

House because so many members have expressed their views  
कि उसमें हाउस की कमेटी हो, I constituted the Committee.  
अगर आप इस बारे में वोटिंग चाहते हैं तो हम वोटिंग करवा देते  
हैं। ( गोर एवं व्यवधान) इस कमेटी में रामकिान फौजी जी और  
आई0जी0 भोर सिंह जी भी मैम्बरज होंगे।

**डॉ० सु गील इन्दौरा** : .....। ( गोर एवं  
व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : इनका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाए।  
( गोर एवं व्यवधान)

**श्री रामकुमार गौतम** : अध्यक्ष महोदय, असल में जो  
प्रोब्लम इन भाइयों की है, वह आप भी, हुड्डा साहब भी और  
सारा हाउस भी समझता है। अध्यक्ष महोदय, ये सारे भाई जानते  
हैं कि जहां खड़े हैं, वहां पर खड़ा होना इनकी मजबूरी है। ( गोर  
एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप इनको इ यारेंस दिलवाकर  
इनका कल्याण करवाएं। ( गोर एवं व्यवधान) इनको भी पता है कि  
जिस वर्ग से ये हैं उनकी तो भावल के ही वह खिलाफ हैं। उसने  
तो इनके उस वर्ग का बहुत बुरा कर रखा है। ( गोर एवं  
व्यवधान) इस सब के बावजूद भी उनके साथ खड़ा होना इनकी  
मजबूरी है। ( गोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप इनको  
इ यारेंस दिलवा दो तो आगे के लिए इनका खाका ही कट  
जाएगा। ( गोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : .....

श्री अध्यक्ष : यह रिकॉर्ड नहीं किया जाए।

श्री राम कुमार गौतम : हम इनको बहुत प्यार करते हैं।

I love you all people. ( तोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह सभी भाई बहुत ही अच्छे हैं। ( तोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सीता राम जी आप बैठें। ( तोर एवं व्यवधान) पण्डित जी आप बोलें। ( तोर एवं व्यवधान)

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, ये जो हमारे भाई हैं बेसिकली ये बहुत ही अच्छे लोग हैं। मैं इनको बहुत प्यार करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, सारा हाउस जानता है, सारी दुनिया जानती है और हरियाणा का बच्चा-बच्चा जानता है कि सैटिंग का जो समय था that time is over. पहले जो सैटिंग का सिलसिला था वह इनकी पार्टी का जो मुखिया है वह सदन में आता नहीं है, उनकी और आपकी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष चौधरी भजन लाल के बीच में एक सैटिंग थी। यह भाई उसको टिकट दिला लाया, कहां बैठा है धर्मबीर ? अध्यक्ष महोदय, आदमपुर कांस्टीच्यूएंसी में 70 हजार वोट इन्होंने उसके खिलाफ दिवला दिए थे। अध्यक्ष महोदय, वे वोट अभय चौटाला को दिलवा दिए थे। अध्यक्ष महोदय, जितने भी कैंडिडेट्स हुड्डा साहब के ग्रुप के थे, इनकी आपस में लागबाजी के कारण उन सभी को हटा दिया गया और



उसकी वजह से हमारे यहां पर कुछ अच्छे भाई आ गए हैं, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। ( गोर एवं व्यवधान)

**डॉ० सीता राम :** अध्यक्ष महोदय, वोट तो लोगों का अधिकार है और वोट उन्हीं ने डाले हैं वोट कैसे कोई डलवा सकता है। क्या हरियाणा की जनता समझदार नहीं है ? हरियाणा की जनता जागरुक है। यह तो इन्होंने लोगों को इमोशनल किया है और लोगों से झूठे वायदे करके यहां पर आए हैं।

**श्री राम कुमार गौतम :** कोई बात नहीं वे अगली दफा निकाल देंगे।

**डॉ० सु गील इन्दौरा :** स्पीकर सर, इनको आप चैम्बर में बुला लें और वहां पर इनके टोटके सुन लें।

**Mr. Speaker :** Every Hon'ble Member has the right to speak but it is my duty to maintain the decorum and dignity in the House. (interruption) डॉक्टर साहब, आप सुनते तो हैं नहीं।

**श्री राम कुमार गौतम :** स्पीकर सर, जो आदमी महज एम०एल०ए० बनने के लिए ऐसी जगह चला जाए जो इनके जाने के लायक नहीं थी तो वह इनके लिए सही नहीं है। ( गोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** कल जो तवा चढ़ा रहा था अगर उसको आप लोग सुन लेते तो फिर आपको पता चलता। ( गोर एवं व्यवधान)

**श्री राम कुमार गौतम :** स्पीकर साहब, सारी हरियाणा की जनता जानती है कि जो यह सैटिंग का हिसाब किताब था that time is over. स्पीकर साहब, जिस तरह से सांप की मुंडी पर अगर लट्ठ मार दो या उसको बीच बिचाले में से तोड़ दो तो उसका मरना जो डैफनेट है लेकिन उससे पहले उसका जहर धूलेगा और वह पूंझड़ी मारेगा। स्पीकर सर, अब तो चौटाला साहब पूंझड़ी मार रहे हैं और अब ये बैकवर्ड सम्मेलन कर रहे हैं जिनका इन्होंने बीज मार रखा है, हरिजन सम्मेलन भी ये कर रहे हैं जिनकी भाक्ल देखकर ये राजी नहीं हैं। इसी तरह से इनके चेले व्यापारियों से फिरौतियां लेते थे, उनकी दुकानें लूटते थे लेकिन अब ये उनके भी सम्मेलन कर रहे हैं। स्पीकर साहब, उनका नाम सीधा था। चौधरी भजनलाल का समय आया तो चौटाला जी सीधा कहते थे कि अरे भाई मोडियों को मारेंगे, हमारे जाट भाई भोले भाले किसानों को बहकाकर वे वोट ले जाते थे और जातिवाद का नारा लगाते थे।

**श्री अध्यक्ष :** गौतम साहब, मोडिया क्या हैं ?

**श्री राम कुमार गौतम :** स्पीकर सर, उस भाशा में बि नोई भाइयों को मोडिया कहते हैं but that time is over.

**डॉ० सीता राम :** अध्यक्ष महोदय, ये किस मुद्दे पर बोले रहे हैं ?

**श्री अध्यक्ष :** डॉक्टर साहब, मैं उनसे खुद पूछ रहा हूँ कि पण्डित जी, आप किस मुद्दे पर बोले रहे हैं। ( गोर एवं व्यवधान) आप बैठो तो सही, मैं उनसे पूछ रहा हूँ।

**श्री राम कुमार गौतम :** स्पीकर सर, मैं मुद्दा बताऊंगा। ( गोर एवं व्यवधान)

**डॉ० सीता राम :** स्पीकर सर, इनका कोई मुद्दा नहीं है।

### सदस्यों का नाम लेना

**श्री अध्यक्ष :** डॉक्टर साहब, गौतम साहब जीरो ऑवर में अपनी बात कह रहे हैं। ( गोर एवं व्यवधान) Nothing is to be recorded.

**श्री बलवन्त सिंह सढौरा :** स्पीकर साहब, \*\*\*\*\*

**श्री अध्यक्ष :** बलवन्त जी, आप ऐसे नहीं बोल सकते। वे अपना मुद्दा बता रहे हैं इसलिए आप अपनी सीट पर बैठ जाइये। ( गोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन ने नल लोकदल के माननीय सदस्य श्री साहिदा खान हाउस की वैल के नजदीक आकर जोर जोर से बोलने लगे।)

श्री अध्यक्ष : साहिदा खान, आप अपनी सीट पर जाइये।  
( तोर एवं व्यवधान) Sahida Khan, I warn you.

श्री साहिदा खान : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुनिए।

**Mr. Speaker** : Sahida KEn, I warn you. साहिदा खान, आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए। ( तोर एवं व्यवधान) I again warn you.

श्री साहिदा खान : स्पीकर साहब \*\*\*\*\*

**Mr. Speaker** : Sahida KEn, I name you. अगर कोई अपनी चेयर छोड़कर हाउस की वैल के नजदीक आएगा तो he will be named.

(इस समय इंडियन ने नल लोकदल के सदस्य श्री साहिदा खान सदन से बाहर चले गए।)

डॉ० सीता राम : स्पीकर साहब, \*\*\*\*\*

श्री अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर जाकर बैठें। Nothing to be recorded.

श्री बलवन्त सिंह : स्पीकर साहब, \*\*\*\*\* ( तोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरे को पता है कि जीरो ऑवर में कोई भी मैम्बर कोई भी बात बोल सकते हैं। ( तोर एवं व्यवधान) बलवन्त सिंह, आप बैठिए।

श्री राम कुमार गौतम : स्पीकर सर, मैं मुद्दे पर ही बोल रहा हूँ। I am coming to the point. ( तोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, इनको सुनने की क्षमता रखनी चाहिए, अरे भाई आपका हुड्डा साहब से क्षमादान करवा देंगे। आप चिन्ता क्यों करते हो ? ( तोर एवं व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, \*\*\*\*\*

**Mr. Speaker** : Balwant Singh Sadhaura, I again warn you. I name you.

(इस समय इंडियन ने नल लोकदल के सदस्य श्री बलवन्त सिंह सढौरा सदन से बाहर चले गए।)

डॉ० सीता राम : स्पीकर साहब, \*\*\*\*\* ( तोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन ने नल लोकदल के सदस्य डॉ० सु गील इन्दौरा हाउस की वैल में आ गए और जोर जोर से बोलने लगे।)

डॉ० सु गील इंदौरा : स्पीकर साहब, \*\*\*\*\*

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आप अपनी सीट पर बैठिए।  
( गोर एवं व्यवधान) Indora ji I warn you.

डॉ० सु गील इन्दौरा : स्पीकर साहब, \*\*\*\*\*

**Mr. Speaker** : Mr. Indora, I warn you.

डॉ० सु गील इन्दौरा : स्पीकर साहब, \*\*\*\*\*

**Mr. Speaker** : Mr. Indora, I again warn you.  
(Interruption) I name you.

(इस समय इंडियन ने गनल लोकदल के सदस्य डॉ० सु गील इन्दौरा सदन से बाहर चले गए।)

श्री अध्यक्ष : जो भी ये बोल रहे हैं इनका रिकॉर्ड न किया जाए। जीरो ऑवर में कोई भी आनरेबल मैम्बर कोई भी मुद्दा उठा सकता है।

(इस समय इंडियन ने गनल लोकदल के सदस्य डॉक्टर सीता राम और रामफल चिढ़ाना हाउस की वैल में आकर जोर जोर से नारेबाजी करने लगे।)

श्री राम कुमार गौतम : स्पीकर सर, इनको सुनने की ताकत होनी चाहिए। जो भी ये मुझे सुनाना चाहते हैं वह मुझे सुना दें, हम इनके सामने कोई रोड़ा नहीं अटकाएंगे। आप कुछ भी कह लेना मुझे ऐतराज नहीं है। हम सारी बात सुनेंगे। ( गोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** जीरो ऑवर में कोई भी सदस्य किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए स्वतंत्र है। ( गोर एवं व्यवधान) 10:55 बजे

**सदस्यों को नेम करने के फैसले को रद्द करना**

**श्री ई वर सिंह पलाका :** अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथियों को सदन में वापस बुला लें ताकि वे भी यहां पर अपनी बात कह सकें।

**श्री अध्यक्ष :** आप अपनी चेयर पर जाकर रिक्वैस्ट करें। आप चेयर पर जाओ और वहां से रिक्वैस्ट करो। आप अपनी चेयर पर जाकर रिक्वैस्ट करें।

**डॉ० सीता राम :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने जो हमारे साथी बाहर किए हैं उनको आप वापस बुला लें। यदि वे हाउस की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे तो यह कोई अच्छी परम्परा नहीं होगी।

**मुख्यमंत्री (श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा) :** अध्यक्ष महोदय, ये साथी यदि अनुरोध कर रहे हैं मेरा आपसे निवेदन है कि इनके साथियों को सदन में बुला लिया जाए।

**श्री अध्यक्ष :** मैंने तीन-तीन बार वार्न किया था। What is the meaning of warning? वार्निंग के क्या मीनिंग हैं ?

**डॉ० सीता राम :** पहले आपने मुझे निकाला। आपने मुझे एक बार देखा और आपने कह दिया कि I name you. आप कह रहे हैं कि तीन बार वार्न किया।

**श्री अध्यक्ष :** चेयर को छोड़ने से पहले आपको सोचना चाहिए।

**डॉ० सीता राम :** मुझे पता है कि यह चेयर का सम्मान नहीं है लेकिन जिस सदस्य को पता ही नहीं है कि वह क्या बोल रहा है उसे आप बोलने की इजाजत दे रहे हैं। इनको सिर्फ ओम प्रकाश चौटाला ही नजर आते हैं। ये लोगों को इमोशनली प्रभावित कर रहे हैं। (गौर एवं व्यवधान)

**श्री राम कुमार गौतम :** अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बारे में यह कहना है। (विघ्न)

**डॉ० सीता राम :** अध्यक्ष महोदय, जब आपने मुझे मौका दिया है तो फिर ये बोलने के लिए क्यों खड़े हैं। सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करूंगा कि हम अपनी बात उसी समय रखेंगे जब आप हमारे बाकी के सदस्यों को यहां वापस बुला लेंगे। जब हमारे साथियों को यहां वापस बुला लेंगे तभी यहां सदन की कार्यवाही चलेगी।

**श्री अध्यक्ष :** उनको तभी बुलाने पर विचार किया जा सकता है जब आप गारंटी लोगे कि they will behave properly. अगर खबरें छपवाने के लिए और अखबारों की सुर्खियों में आने



के लिए आप वाक आउट करते हैं तो यह ठीक बात नहीं है। ऑनरेबल मैबर जीरो ऑवर में बोल रहे हैं। माननीय कैप्टन अजय सिंह यादव जी ने घोटाले का मुद्दा उठाया था उस पर ये बोल रहे थे। ( गोर एवं व्यवधान) वे क्या गलत बात कह रहे थे।

**डॉ० सीता राम :** अगर ऐसा कोई मुद्दा है तो सरकार उसको देखकर कार्यवाही कर ले। गालियां निकालना और भद्दी भाशा का इस्तेमाल करना यह कहां की परंपरा है हमारे साथियों को जो हाउस से निकाले गए हैं उनको वापिस बुलाइये। सर, मैंने आपनी बात कह दी है। (विघ्न)

**श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा :** डॉक्टर सीता राम जी आप अपनी सीट पर बैठिये, आपके साथियों को बुला लेंगे। (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष :** ठीक है, बुला लेंगे। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि आगे ऐसी बात न हो।

**डॉ० सीता राम :** अध्यक्ष महोदय, अनकंडी इनल बुलाइये। (विघ्न)

**बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला)** अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर सीता राम इस सदन में दूसरी बार चुनकर आये हैं। इन्हें इस बात की जानकारी है कि चेयर का सम्मान किस प्रकार से किया जाता है। हम चेयर के साथ भाव नहीं रख सकते। चेयर ने उदार हृदयता दिखाई है। सदन के नेता ने भी अभी अनुरोध किया है कि आप इनकी रिक्वेस्ट को कंसीडर करें।

सभी सदस्य आ जाये। माननीय पण्डित जी भी अपनी बात कहें। ये माननीय साथी भी अपनी बात कहें और इस सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलने दें। मैं आपसे अपने साथियों की तरफ से अनुरोध करूंगा कि आप उन साथियों को बुला लें। हम सदन की कार्यवाही में व्यवधान नहीं डालने देंगे। सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलायेंगे। चेयर का हम सभी सदस्य आदर करते हैं। विपक्ष के साथी, बीजेपी के साथी और इण्डिपेंडेंट साथी सभी साथी चेयर का सम्मान करते हैं। इस प्रकार का सौहार्द हम बनाये रखेंगे।

**श्री फूलचन्द मुलाना :** अध्यक्ष महोदय, इस सदन के भी नियम हैं कि इस सदन के सदस्यों को लाखों लोगों ने चुनकर भेजा है। आपने नियमों की पुस्तिका छपवाई है उसमें सभी व्यवस्था दी गई है। हर मैम्बर को सदन में बोलने का पूरा अधिकार है, प्रैक्टिस कोई भी है जब कोई मैम्बर अपनी बात कहे तो किसी दूसरे सदस्यों को अगर उसके बारे में कोई आपत्ति है तो वह खड़ा होकर उस बात का जवाब दे। लेकिन बीच में इन्ट्रूट करने से न उसकी बात सुनी जाती है न दूसरे की। मेरा निवेदन है कि हमारे संसदीय मंत्री ने जो बात कही है मैं उनसे सहमत हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि इनके साथियों को बुला लिया जाए लेकिन जो सदन की प्रणाली है उसका वे पालन करें।

**श्री अध्यक्ष :** ठीक है, गौतम जी आप जीरो ऑवर में क्या बोल रहे थे उसको कन्टीन्यू करें।

डॉ० सीता राम : सर, गौतम साहब किस मुद्दे पर बोल रहे हैं। \*\*\*\*\*

**Mr. Speaker** : Nothing is to be recorded. गौतम जी, आप जीरो ऑवर में क्या बोल रहे थे।

डॉ० सीता राम : सर, \*\*\*\*\*

श्री अध्यक्ष : डॉ० सीता राम जी, प्लीज आप बैठें। आपकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं की जा रही है। (विघ्न) मुद्दा यह था कि पिछले सरकार ने ऑक्शन में जो लूट-खसोट मचाई थी, जमीन बेची गई थी उसके बारे में गौतम जी बोल रहे थे।

डॉ० सीता राम : सर, \*\*\*\*\*

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं 100 प्रतिशत उसी के बारे में अपनी बात कह रहा हूँ इनको मेरी बात पहले सुननी चाहिए, उसके बाद में ये अपना जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर जाकर अपनी बात कहें। पण्डित जी इस बारे में कमेटी बना दी है जब कमेटी की रिपोर्ट आ जायेगी उसके बाद आप बोल लेना।

श्री विनोद कुमार भार्मा : अध्यक्ष महोदय, कमेटी बनाने से किसी सदस्य का बोलने का अधिकार खत्म हो जाता है क्या ? कमेटी बनाई हुई तो क्या हुआ। कोई भी माननीय सदस्य अपनी बात सदन में कह सकता है यह उसका अधिकार है और उसे

उसका अधिकार मिलना चाहिए। आप इनके कहने से क्यों किसी माननीय सदस्य को बोलने से रोक रहे हो। ये तो रोकेंगे ही। आप बोलने दीजिए। (विघ्न)

**डॉ० सीता राम :** अध्यक्ष महोदय, ऐसे गौतम जी के पास क्या तथ्य हैं अगर कोई तथ्य है तो उसे कमेटी देख लेगी।

**श्री राम कुमार गौतम :** अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य मेरी बात सुनेंगे। मैं सचवाई की बात कहता हूँ, मैं झूठ नहीं कहता। अगर मेरी बात झूठ हो तो यह हाउस जो सजा देगा वह भी मुझे मंजूर है। (विघ्न) मैं आपको मिसाल के तौर पर बताता हूँ कि जब ओम प्रकाश चौटाला ने टेक ओवर किया था उस समय रेत के भाव क्या थे ? उसने एक भाई को ठेकेदार बना दिया और उससे कहने लगा कि देख भाई बात सुन तू है ठेकेदार, तू कितने पैसे की नौकरी की उम्मीद करता था। वह कहने लगा कि चौधरी साहब, 10 हजार की मिल जाती तो बहुत थी। कहने लगा चल तेरे को 20 हजार की नौकरी दे दी और रेत के भाव पता कर लो जितने भाव उस दिन थे उससे दो गुना, ढाई गुना तेज कर दिए और वह बेचरा नौकरी पर ही था। इसी तरह जो जमीनें थीं उसमें पहले कह दिया होगा कि 4 लाख ले आइए और एक लाख मैं तेरे नाम कर दूंगा। ( गौर एवं व्यवधान) 100 परसेंट यही बात मिलेगी, या तो उससे पहले पैसे खा लिए होंगे।

**डॉ० सीता राम :** अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। ये कहते हैं कि कह दिया होगा तो मैं कहना चाहूंगा कि ये कह दिया होगा नहीं कहें बल्कि जो सत्य है वह कहें। आज जो महंगाई बढ़ी है, रेत के रेट बढ़े हैं, कार्ज के रेट बढ़े हैं क्या उनमें भी कमी लान लिया गया है। जो स्टील के रेट बढ़े हैं क्या इसमें भी कांग्रेस पार्टी ने कमी लान लिया है। ( गोर एवं व्यवधान) ये खुद छोड़ कर जाने वाले हैं। इनको अपने ठिकाने का तो पता नहीं और दूसरों को नसीहत देते हैं। ( गोर एवं व्यवधान)

**श्री कर्ण सिंह दलाल :** अध्यक्ष महोदय, मैं आज जो टाइम्स ऑफ इंडिया में रिवाड़ी जिले के मुकंदपुर गांव के बारे में खबर है, उसकी तरफ मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। रिवाड़ी जिले का एक गांव मुकंदपुर बसई है। पुराने रजवाड़ों की व्यवस्था के अनुसार पहले वहां पर भरतपुर रियायत का रजवाड़ा हुआ करता था अब फिर न जाने किस तरह से वहां के लोगों ने उस आधे मुकंदपुर गांव की खरीदने का काम किया है। वैसे तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रशासन सजग है क्योंकि डी०सी० ने एस०डी०एम० से इस बारे में रिपोर्ट भी मांगी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर वे स्वयं निगरानी रखें और अगर इस गांव को एक्वायर करने की भी नौबत आए तो सरकार को एक्वायर करना चाहिए। यदि इस गांव को फिर से बसाने की कोई व्यवस्था करने की भी बात आए तो सरकार को इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए।

## गैर-सरकारी संकल्प

कुटीर उद्योगों, विशेषकर पारंपरिक उद्योगों की  
अवनति के संबंध में

**Mr. Speaker :** Hon'ble Members, now Dr. Sushil Indora, MLA, will move a resolution.

डॉ० सु गील इन्दौरा (ऐलनाबाद, अनुसूचित जाति) :  
अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि—

“यह सदन प्रदेश में कुटीर उद्योगों, विशेषकर पारंपरिक उद्योगों की निरंतर अवनति पर गहरी चिन्ता व्यक्त करता है, क्योंकि कुटीर उद्योग ही प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के कुशल तथा अकुशल श्रमिक वर्ग के रोजगार उपलब्ध करवाने में सक्षम हैं।”

अध्यक्ष महोदय, जो गैर सरकारी संकल्प मेरे नाम के सामने आया है और उसको कार्यवाही में सम्मिलित किया गया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपका आभार प्रकट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इस कमेंट के साथ हमें दबड़काया जाता है या हम दबड़क कर चले जाते हैं। हमें धक्के मारकर बाहर निकाला जाता है इसका फैसला तो उच्च आसन पर बैठे लोग ही कर सकते हैं या फिर सदन के नेता कर सकते हैं। मुख्यमंत्री महोदय जी, हमारे आचरण पर भाक किया जाता है यह आपके सामने है। (विघ्न) मैं सदन की गरिमा का पूरा ध्यान रखते हुए

अपने गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा करना चाहूंगा। मैं सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस महत्वपूर्ण विषय पर मेरा साथ दें। अध्यक्ष महोदय, भारत दे 1 गांव का दे 1 है और हमारे दे 1 में 70 से 80 प्रति 100 जनसंख्या गांवों में रहती है। पुराने समय से ही गांवों के अपने पारम्परिक उद्योग रहे हैं और गांव में रहने वाले लोग उन पारंपरिक उद्योगों के जरिये अपना-अपना रोजगार चलाते रहे हैं। यही कारण है कि उनकी उन्नति से भारत का विकास हुआ है। आप सभी जानते हैं कि एक समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि पहले गांव के आधार पर ही विकास का आधार होता था। यही कारण है कि गांवों के विकास के कारण ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अध्यक्ष महोदय, पहले सुई से लेकर ओखली-मूसली जिनसे खाद्य पदार्थों को कूटकर खाने लायक बनाया जाता है आदि का काम गांव के स्तर पर ही हो जाता था। हर चीज गांव में मिल जाती थी यानि कि गांव में रहने लोगों की मूलभूत जरूरतें गांव में ही पूरी हो जाती थी। गांव में ही गांव के लोगों को रोजगार मिल जाता था। जो किसान भाई थे वे अपनी सीमित साधनों से जहां अपने लिए आजीविका का काम चलाते थे वहीं अपने सहयोगी दस्तकार भाइयों की आजीविका भी चलाते थे। चाहे कोई हथकरघा के दस्तकार थे, चाहे कोल्हू चलाने वाले भाई थे, चाहे चक्की चलाने वाले भाई थे हर किसी की जरूरतें गांव के लैवल पर पूरी हो जाती थी। अध्यक्ष महोदय, पुराने समय में जो तेली का कोल्हू था वह पारम्परिक उद्योगों का एक हिस्सा था।

इसी तरह से कुम्हार भाई जो बर्तन बनाते थे उनसे भी लोगों को रोजगार मिलता था। लुहार भाई की कुल्हाड़ी और कस्सी से किसानों को रास्ता मिलता था। इसी तरह पिंजाई से रजाई बनाने वाले भी उस समय समाज में महत्वपूर्ण योगदान देते थे। इसी तरह से चाले कोई जूती बनाने वाला था, खादी के कपड़े बनाने वाला था या आटे की चक्की चलाने वाला था ये सभी एक दूसरे के लिए जरूरतें पैदा करते थे और सबकी जरूरतें गांव के लैवल पर ही पूरी हो जाती थी तथा सभी गांवों के लैवल पर ही रोजगार मिल जाता था। अध्यक्ष महोदय, उस समय कु आल और अकु आल सभी को उनके काम के मुताबिक रोजगार मिलता था और सभी लोग गांव के स्तर पर अपना गुजारा कर लेते थे तथा सभी में सामाजिक प्रेम प्यार भी बना रहता था। हालांकि उस समय गांव सामाजिक वर्णता के आधार पर बंटे हुए थे और लोगों के काम भी सामाजिक वर्णता के आधार पर बंटे हुए थे लेकिन सभी सामाजिक प्रेम की भावना बनी रहती थी। किसान भाई खेती करके अनाज पैदा करते थे और दूसरे भाई भी अपने-अपने रोजगार से एक-दूसरे की जरूरतें पूरी करते थे तथा आपस में मिल बांटकर खाते थे। उस समय जो भी सामाजिक काम होता था उसको सभी लोग मिलकर करते थे। चाहे गउ आला बनाने की बात हो, चाहे धर्म आला बनाने की बात हो, चाहे विवाह- आदी में भागुन के आधार पर मदद करने की बात हो या किसी और प्रकार से सामाजिक सेवाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, गांव के लैवल पर ही सभी एक-दूसरे की मदद करते थे जिससे सभी में बहुत



ज्यादा प्रेम प्यार बना रहता था। इसके अतिरिक्त गांव के स्तर पर ही व्यावहारिक ज्ञान रखने वाले वैद्य उस समय जड़ी-बूटियों से काढ़ा बनाते थे और लोगों की बीमारियों का इलाज करके उनकी मदद करते थे तथा अपनी जीविका भी चलाते थे और साथ ही साथ वे वहां पर अपने उस ट्रेडी इनल पारम्परिक ज्ञान का प्रयोग करके समाज के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते थे। ऐसे में खाद्यान्न सामग्री से जुड़े बहुत से अनेक संसाधन थे जैसे हमारे लोग पापड़, बड़ियां और सेवियां बनाते थे। ऐसे ही सांगर जो जांटी से लगता था उसको सुखाकर घड़े में भर लेते थे। इसको आज भी फाईव स्टार होटलों में बड़े चाव के साथ खाया जाता है। इसी तरह फोफली और फोगला को भी हम सुखाकर इकट्ठा कर लेते थे ताकि जरूरत के हिसाब से हम आपस में मिल बांट कर प्रयोग कर लें इस प्रकार हम एक-दूसरे की जरूरतों को भी पूरा करते थे। (इस समय सभापतियों की सूची में एक सदस्य श्री आनंद सिंह दांगी चेयर पर पदासीन हुए।) चेयरमैन साहब, ये सभी रियायतें थी, ऐसा प्रेम और प्यार था कि हम एक दूसरे की जरूरतों को भी पूरा करते थे और इससे बेरोजगार लोगों को भी रोजगार के साधन मुहैया होते थे। इससे सामाजिक ढांचा को भी बढ़ावा मिलता था। समय बदला और समय बदलने के साथ-साथ हर चीज बदलती गई, जरूरतें भी बढ़ती और बदलती चली गई। जरूरतों के बढ़ने के कारण छोटी-छोटी मीनिंगें आईं। हरकरघा उद्योग भुर्रु हुआ, होजरी के उद्योग भुर्रु हुए। खेस, दरी व चादरें मीनिंगों पर बनने लगी, जूते, कपड़े मीनिंगों से बनने लगे, रस्से,

जाल वगैरह भी मीनों से बनने लगे, खेलों का जो सामान था वह मीनों से बनने के साथ-साथ गांवों में हाथों में भी बनता था इससे लोगों को रोजगार मिलता था और चीजें भी मीनें बनाने लगी लेकिन इस सबके बावजूद भी हमारे कुटीर और लघु उद्योगों का जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। कुटीर और लघु उद्योगों की बात हो और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम न आये तो यह एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे कि ग्रामीण विकास के लिए पारम्परिक कुटीर उद्योगों की जरूरत है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और दे आ का विकास हो सके क्योंकि इस गांव के विकास में ही दे आ का विकास निहित है। ऐसे ही महात्मा गांधी जी के साथ-साथ चलते दे आ के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर नेहरू जी थे जो कि ज्यादा समय विदेशों में भी रहे। मैं यह नहीं कहता कि उनका लगाव कुटीर उद्योगों की तरफ नहीं था।

**श्री विनोद कुमार भार्मा :** सभापति महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। सभापति महोदय, पण्डित जवाहर लाल नेहरू तो दे आ की आजादी के लिए बहुत बार जेलों में गये थे। क्या इन्दौरा जी बतायेंगे कि इनकी पार्टी के कितने नेता आजादी के लिए जेलों में गये।

**श्री सु गील इन्दौरा :** चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ये इस बारे में हमारे नेताओं से ही जाकर पूछ लें क्योंकि इनके हमारे नेताओं के साथ

व्यक्तिगत सम्बन्ध हैं। ये मुझे क्यों बीच में लाना चाहते हैं। इसमें मुझे कोई एतराज नहीं होगा। चेयरमैन सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने अपने जीवन का काफी समय विदेशों में गुजारा और मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि ऐसी बात भी नहीं थी कि वे कुटीर उद्योगों के खिलाफ थे लेकिन उनकी विदेशों के हिसाब से विकास की एक सोच थी। यह बात भी ठीक है कि आदमी जहाँ रहता है उसकी सोच पर भी वहाँ का असर होता है कि वहाँ के विकासात्मक ढाँचे को फोलो किया जाये। क्योंकि उन्होंने विदेशी सभ्यता को काफी देखा था, अच्छी-अच्छी बिल्डिंग देखी थी, बड़े-बड़े कारखाने देखे थे और मैं खुद भी ऐसी जगहों पर गया हूँ जहाँ पर मुझे स्वयं लोगों ने इस बारे में बताया। मैं यह भी नहीं कहता कि यह विकास की सोच अच्छी नहीं थी। यह सोच अच्छी थी क्योंकि वक्त के साथ बदलने की सोच अच्छी है लेकिन पुरानी परम्पराओं को भुलाना भी नाइंसाफी है। हम अगर बड़ी इकाइयों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो अच्छी बात है लेकिन इसके लिए हम छोटी इकाइयों को नुकसान नहीं पहुंचाये इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इससे देश का विकास होगा। लाखों लोगों को छोटी-छोटी इकाइयों के माध्यम से रोजगार मिलता है और उनकी आजीविका का साधन बनता है। लेकिन धीरे-धीरे वक्त बदला है। आज के वक्त की बात कहें तो पहले जहाँ कुटीर उद्योग आम आदमी के हाथ में थे जहाँ किसान अपने सीमित साधनों के बावजूद भी अपनी खेती की रखवाली कर लेता था वहीं ये वक्त के साथ

बदलते चले गये और विकास और उद्योग पूंजीपतियों के हाथों में आते गये। सभापति महोदय, भुरुआत यहां से हुई कि हमने विकास की उंची दर हासिल करने के लिए चमक-दमक वाली नीतियां बनाईं और पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में हमने अपने कुटीर उद्योगों को भुला दिया। उनकी तरफ हमने कोई ध्यान नहीं दिया और विकास के पहिए कुटीर उद्योगों को रौंदते चले गये। इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से सरकारों का हाथ रहा। चाहे वह प्रदेश की सरकार थी, चाहे केंद्र की सरकार थी। मैं सरकारों का हाथ इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि सरकारों ने बदलाव लाने के लिए ऐसी नीतियां बनाईं जिससे सब कुछ बदल गया और कुटीर उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिसके कारण वे पूंजीपतियों के हाथों में खेलते चले गये। जहां पहले हर हाथ को काम मिलता था, हर आदमी अपनी आजीविका कमा सकता था, वहीं विकास की अंधी दौड़ में वह विकास एक विकास ही रह गया और 100 खाली हो गये। सभापति महोदय, छोटी से छोटी सुई से लेकर उखली-मूसली बनाने तक का काम आज किसी टाटा ने ले लिया, किसी बिड़ला ने ले लिया या किसी मोदी ने ले लिया है। आज जूते बनाने के बड़े-बड़े कारखाने लग गये, स्पनिंग के बड़े-बड़े मिल लग गये और आर्थिक नीति निर्धारण का काम इन पूंजीपतियों ने अपने हाथ में ले लिया कि हम इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। मनीषी युग में तो कुछ लोगों के हाथों में ही काम चला गया और बहुत से लोग बेरोजगार होते चले गये क्योंकि जितने पास सीमित साधन थे वे

अपनी आजीविका तो कमा सकते थे लेकिन पूंजीपतियों की दौड़ को कम्पीट नहीं कर सकते थे, उनके साथ नहीं चल सकते थे। उनका नतीजा यह हुआ कि वे पिछड़ते चले गये। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए था। आर्थिक विकास की दर का लाभ कुछेक पूंजीपतियों के हाथों में चला गया है जबकि होना यह चाहिए था कि सरकार इन कुटीर उद्योगों के बारे में विशेष ध्यान देती, उनको आर्थिक लाभ देती। उनको विशेष ट्रेनिंग देने का प्रावधान करना चाहिए था। सभापति महोदय, मैं कौशल की बात भी करना चाहता हूँ। वैद्य का बेटा होगा तो वह वैद्य का कौशल सीखेगा, लुहार का बेटा लुहार का काम सीखेगा लेकिन कौशल के काम को अनदेखा कर दिया गया, इसलिए लोग अपने परम्परागत धंधे को छोड़ रहे हैं। सभापति महोदय, शिक्षा का अभाव रहा। जहाँ उसको शिक्षा देकर उसको प्रोत्साहित करना चाहिए था वहाँ उसका अभाव रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव रहा जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ती गई। जब बेरोजगारी बढ़ती गई तो गरीब श्रमिक और गरीब किसानों ने आहिस्ता-आहिस्ता भाहरों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। भाहरों में आकर भी उनकी दिक्कतें कम नहीं हुईं। उन लोगों ने कॉलोनियां बना लीं। कल-परसों यहाँ हाउस में अवैध कॉलोनियों का जिक्र हो रहा था। उन लोगों के भाहरों में आने से अवैध कॉलोनियों का निर्माण शुरू हो गया क्योंकि उनको कहीं न कहीं रहना ही था। आहिस्ता-आहिस्ता गरीब आदमी काम की तलाश में

भाहरों की तरफ बढ़ गये और जो गांवों में रह गये वे बेरोजगारी की तरफ बढ़ गये।

**श्री सभापित :** आज के दिन सरकार गरीबों की मदद के लिए 100-100 गज के प्लॉट कालोनी की तरह डिवलप करके दे रही है। (विधन) डॉ० साहब, आप लोग किसी पर विवास नहीं करते हो। प्रदेश की जनता की भलाई के लिए सरकार जो काम कर रही है आप लोगों को उनकी सराहना तो करनी चाहिए।

**डॉ० सु गील इन्दौरा :** सभापति महोदय, इस तरह से बेरोजगारी आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती चली गई और कुटीर उद्योग ठप्प होते चले गये। महात्मा गांधी जी का स्वदे ही का नारा क्षीण हो गया और उसके अक्स ढीले पड़ गए। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वदे ही बनो, स्वदे ही पहनो और स्वदे ही खीण हो गया लेकिन ये सारे के सारे नारे क्षीण हो गये हैं। इनके साथ ही साथ इस सरकार ने पूंजीपतियों के साथ मिल कर आर्थिक नीतियों के निर्धारण का प्रोग्राम बनाया है। सरकार ने अपनी नीतियों में पूंजीपतियों को रियायतें देकर विकास की दर को नीचा करने का कार्य किया है। हम विकास चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि विकास हो, सारा देश विकास चाहता है कि विकास हो लेकिन उसके लिए नीति निर्धारण पूंजीपतियों के हाथ में न हो कर सरकार अपने हाथ में ले और इस प्रकार की नीतियां निर्धारण करे जिससे आम आदमी को चाहे श्रमिक हो, चाहे वह मजदूर हो, विकास के लाभ में उसका उतना ही हिस्सा होना चाहिए जितना

कि उसमें उसके सहयोग का हिस्सा है। लेकिन जो नीतियां निर्धारित की गई हैं उनसे उसका हिस्सा पूंजीपतियों के हाथ में चला जाता है। रोजगार के नाम पर पूंजीपतियों ने कहा कि हम रोजगार देंगे, इसके लिए हम मॉल बनाएंगे, एस0ई0जैड0 बनाएंगे, बड़ी-बड़ी दुकानें खुलवाएंगे, बड़े-बड़े रिटेल आउटलैट खोलेंगे या डिपार्टमेंटल स्टोर खोलेंगे। उन्होंने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नारे दिये लेकिन उनकी आर्थिक नीतियों का लाभ किसको मिला ? उस व्यापार का आर्थिक लाभ पूंजीपतियों को मिला है जो पिछड़ा और गरीब आदमी है वह उनके मुंह की तरफ देखता रह गया है। सभापति महोदय, इस मामले में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिसकी जरूरत सारे देश में है और वह है स्पैशल इकनॉमिक जोन। मैं एस0ई0जैड0 की बात कहना चाहता हूं। एस0ई0जैड0 के आधार पर माननीय वित्त मंत्री जी ने भी अपने बजट भाषण में कहा है कि हम 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, यह अच्छी बात है। यह बात वे सदन में जरूर रखें कि रोजगार किस को देंगे तो इस बात से हमें बहुत खुशी होगी। हम चाहते हैं कि कृषि और अकृषि क्षेत्रों में चाहे कोई भी श्रमिक हो, मजदूर हो उसको रोजगार मिले। सभापति महोदय, अब मैं इसमें एस0ई0जैड0 की नियमावली का जिक्र करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि 25 प्रतिशत भूमि पर उद्योग लगेंगे। सभापति महोदय, मेरे ख्याल से जो आंकड़े मैं पेश कर रहा हूं यह सही हैं और अगर कहीं पर कोई गलत बात होगी तो सरकार उसको करैक्ट करके मुझे भिजवा दे। नियमावली के मुताबिक 20 प्रतिशत भूमि कमिश्नरियल

एक्टिविटीज के लिए होगी जिसमें दुकानें और मॉल बनेंगे, 16 प्रति 100 भूमि पर रैजिडेंसियल एक्टिविटीज होगी यानि इस भूमि पर रहने के लिए घर बनेंगे, 5 परसेंट भूमि पर ऐण्टरटेनमेंट एक्टिविटीज होंगी, 5 प्रति 100 भूमि पर संस्थाएं यानि इन्स्टीच्यूट्स होंगे जिनमें स्टेडियम्ज, पार्कस, अस्पताल, धर्म मालाएं, स्कूल आदि बनाए जाएंगे और 30 प्रति 100 भूमि पर व्यापारिक स्थल बनाए जाएंगे जिनमें रिटेल आउटलैट, जैसे छोटे-मोटे बूथ, व्यापारिक स्थल आदि हो जाएंगे। सभापति महोदय, मैं एक बात बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूं कि मेरी मं ग में कोई खोट नहीं है, मैं अपनी मं ग में कोई खोट नहीं देखता लेकिन मुझे सरकार की मं ग में खोट लगता है जो किसान है उसके पास अपने गुजारा करने योग्य भूमि नहीं है जितनी जमीन उसके पास है उससे न तो उसका अपना पेट भरता है, न ही उसका अपना खर्चा पूरा होता है। जो मजदूर है उसको जो मजदूरी मिलती है उससे उसका पेट नहीं भरता। जो मजदूरी उनको मिलती है वह इतनी थोड़ी है कि उससे उनका गुजारा नहीं हो सकता। सभापति महोदय, यह बात मुझे समझ में नहीं आई कि इतनी थोड़ी सी भूमि है उस पर 20 लाख लोगों को रोजगार कैसे देंगे।

**श्री सभापति :** इन्दौरा साहब, आपकी सोच भी थोड़ी छोटी नजर आ रही है।

**डॉ० सु वील इन्दौरा :** चेयरमैन सर, मैंने पहले ही कहा है कि मेरी मं ग में कोई खोट नहीं है लेकिन अगर कहीं कोई



सवाल उठता है तो उस सवाल के बारे में क्लैरिफिके इन लेना हमारा अधिकार है, हमारा फर्ज है।

**बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :** चेयरमैन सर, यह प्राइवेट मैम्बर रैजोल्यू इन है। चेयरमैन सर, गैर-सरकारी संकल्प पर माननीय सदस्य बोल रहे हैं और इसमें मेरा कोई दखल अंदाजी करने का मकसद नहीं है लेकिन माननीय सदस्य इस बारे में बोलते हुए रास्ता भटक गए हैं इसलिए मैं इनको इनका रैजोल्यू इन पढ़कर सुनाना चाहता हूँ कि इनका जो रैजोल्यू इन है वह इस प्रकार से है—

“यह सदन प्रदेश में कुटीर उद्योगों, विशेषकर पारंपरिक उद्योगों की निरंतर अवनति पर गहरी चिन्ता व्यक्त करता है क्योंकि कुटीर उद्योग ही प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के कुशल तथा अकुशल श्रमिक वर्ग को रोजगार उपलब्ध करवाने में सक्षम है।”

सर, स्पष्ट रूप से कुटीर उद्योग नही है। इनका इससे कोई संबंध नहीं है। अगर इनका आईडिया सिर्फ यह है कि प्राइवेट मैम्बर रैजोल्यू इन के माध्यम से आलोचना करना चाहते हैं तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसका जवाब दे देंगे। इन्हें तो सरकार को नीतिगत निर्णय लेने के लिए सकारात्मक सुझाव देने चाहिए। मैं तो यह कहता हूँ कि आलोचना केवल आलोचना के लिए नहीं की जाए। इन्होंने बोलते हुए

कई अच्छे सुझाव दिए हैं और मैं उनको नोट भी कर रहा हूँ। मैं इनसे यह कहना चाहता हूँ कि ये इस गैर सरकारी संकल्प पर हैल्दी सुझाव दें। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आप बबलिंग न करें, आप बोलते हुए रास्ते में भटक गए थे।

**डॉ० सु गील इन्दौरा :** सभापति महोदय, यह सवाल जवाब का समय नहीं है। मुझे पहले अपनी बात कहने दें और फिर मंत्री जी इस बारे में जवाब दे दें। सभापति महोदय, सदन में सिर्फ एक ही वरिष्ठ मंत्री जी बैठे हुए हैं।

**श्री सभापित :** मांगे राम जी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। आप एस०ई०जैड० के बारे में इनसे पूछ लें।

**शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) :** सभापति महोदय, आपने मुझे जो इण्डस्ट्रीलिस्ट का दर्जा दिया है, इस बारे में मैं माफी चाहूंगा कि मेरे पास एक छोटी सी भी इण्डस्ट्री नहीं है। सभापति महोदय, यह जो इन्दौरा जी एस०ई०जैड० के बारे में कह रहे हैं कि वहां पर कहां से नौकरियां दी जाएंगी। इसके बारे में मैं इनको बताना चाहता हूँ कि जिस 25 प्रति ात भूमि पर उद्योग लगेंगे उस पर कौन काम करेगा, उस पर लोग काम करेंगे। 20 प्रति ात भूमि पर जो कमर्शियल स्टोर और भाँप्स बनेंगी उसमें भी लोग काम करेंगे। 5 प्रति ात भूमि पर एजुके ान इंस्टीच्यूट खुलेंगे उसमें भी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं इनको बताना

चाहूंगा कि वहां पर हरियाणा के लोगों को प्रायरिटी दी जायेगी और हरियाणा के लोगों को ही काम मिलेगा।

**श्री सभापति :** मंत्री जी, यह टोटल एरिया के एक प्रति ात भूमि पर ही बनेगा।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला :** सभापति महोदय, मैं एक बात और आपके माध्यम से माननीय साथी जी से कहना चाहूंगा कि अगर ये एस0ई0जैड0 पर डिस्क ान करना चाहते हैं तो करें। हमें इस बारे में कोई एतराज नहीं है। मैं आपके माध्यम से इनसे कहना चाहूंगा कि ये इस बारे में रैजोल्यू ान ले आएँ और इस पर आधा घंटा, एक घंटा या दो घंटा चाहे तो डिस्क ान कर लें। हमें कोई एतराज नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि इनके नेता जब मुख्यमंत्री थे, उनके समय में ही यह अधिग्रहण किया गया था। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको कागज निकाल कर दिखा देता हूँ। उस समय उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री होते हुए साईन किए हुए हैं। यह कागज आप देख सकते हैं।

**श्री सभापति :** इस एस0ई0जैड0 के मुद्दे पर भी रैजोल्यू ान आना चाहिए। ये इस बारे में गलत बातें कहकर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। (विध्न)

**श्री राम कुमार गौतम :** चेयरमैन सर, मैं भी इस बारे में बोलना चाहता हूँ।

**श्री सभापति :** गौतम जी बोलें, आप क्या बोलना चाहते हैं। (विघ्न)

**डॉ० सु गील इन्दौरा :** सभापति महोदय, इनको जो भी बोलना है वह मेरे बाद बोल लें, मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन पहले मुझे मेरी बात खत्म करने दी जाए। (विघ्न)

**श्री सभापति :** ठीक है, गौतम साहब आप बाद में बोल लेना।

**डॉ० गिाव भांकर भारद्वाज :** सभापति महोदय, इन्दौरा जी इस रैजोल्यूशन के माध्यम से सरकार में खोट ढूँढना चाहते हैं, जो कि इनको मिलेगा नहीं। (विघ्न)

**डॉ० सु गील इन्दौरा :** मैं किसी भी सरकार के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं अपने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ। (विघ्न)

**श्री सभापति :** इन्दौरा जी, आप कोई हैल्दी सुझाव दें।

**डॉ० सु गील इन्दौरा :** चेयरमैन सर, मेरे गैर सरकारी संकल्प में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कुटीर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों के कुशल तथा अकुशल श्रमिक वर्ग को रोजगार उपलब्ध करवाने में सक्षम हैं। मैं एस०ई०जैड० के बारे में यह नहीं कह रहा हूँ कि उनसे रोजगार नहीं मिलेगा, अगर उनसे रोजगार मिलता है तो अच्छी बात है। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो इतना

कहना है कि इस बारे में स्पष्ट किया जाए क्योंकि एस0ई0जैड0 को यह सरकार बड़े जोर— जोर से बढ़ावा दे रही है। चेयरमैन सर, मेरा तो विनम्र अनुरोध यही था कि इस के साथ—साथ सरकार कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा दे क्योंकि अगर एस0ई0जैड0 ही बनते चले गए तो गांवों के जो परम्परागत उद्योग हैं वह खत्म होते जाएंगे। इन हैरीटेज को बचाने का काम हमारा है। अगर एस0ई0जैड0 बनते चले गये तो कल को गांवों के अंदर कोई काम नहीं मिलेगा। मजदूर पिस कर रह जाएगा। मेरा पार्लियामेंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर से यही कहना है कि आपको भी अपनी बात कहने का पूरा वक्त मिलेगा। आप दो घंटे, चार घंटे या अगले हफ्ते तक इसको कैरी कर लिजिए। चेयरमैन सर, मेरा यही कहना था। आप मेरी मांग पर भाक न करें। मुझे एक भांका हुई तो मैंने उसको सदन के सामने रख दिया। चेयरमैन सर, सरकार बड़े दबंग दावे कर रही थी कि एस0ई0जैड0 से बीस लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

**श्री सभापति :** इन्दौरा जी, यह तो सरकार कई बार बता चुकी है भायद आपने ध्यान नहीं दिया।

**डॉ० सु गील इन्दौरा :** कोई बात नहीं सर, सरकार आज भी बता देगी। हम तो जनता की बात कर रहे हैं। अगर ये इस बारे में जनता को बता दें तो ठीक रहेगा। चेयरमैन सर, इस तरह की सारी बातें ही गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से कही जाती हैं।

श्री सभापति : आप कोई सुझाव तो दें।

डॉ० सु गील इन्दौरा : चेयरमैन सर, मैं अपना वाक्य तो पूरा कर लूं। मैं एस०ई०जैड० के बारे में कह रहा था कि इससे व्यापारी वर्ग को लाभ होगा। लेकिन अगर इन एस०ई०जैड० को किसानों की खेती योग्य जमीन पर बना देंगे तो इससे किसानों को बहुत नुकसान होगा। इतने सारे एस०ई०जैड० एन०सी०आर० के नजदीक बनेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। एन०सी०आर० के नजदीक तो बड़े-बड़े उद्योगपति या मल्टी नैशनल कम्पनीज अपने-अपने एस०ई०जैड० बनाने का लालच देंगी क्योंकि वहां पर उनका व्यापार बढ़ेगा। लेकिन चेयरमैन सर, एन०सी०आर० के नजदीक तो वैसे ही बहुत डिवलपमेंट हो जाती है सरकार को वहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। चेयरमैन साहब, जैसा मांगे राम जी ने कहा कि कृषि योग्य भूमि पर एस०ई०जैड० नहीं बनाए जाएंगे लेकिन मुझे याद है जब मैंने एक सवाल के जवाब में श्री लछमन दास अरोड़ा जी से पूछा था कि क्या हरियाणा प्रदेश में वेस्ट लैंड है तो उन्होंने बताया था कि ऐसी भूमि न के बराबर ही है। इसका मतलब तो यह है कि एस०ई०जैड० जो बनेंगे वह कृषि योग्य भूमि पर ही बनेंगे। अब जो एस०ई०जैड० के ढेरों प्रस्ताव लाए जा रहे हैं इनका मकसद हमें समझ में नहीं आ रहा है। चेयरमैन सर, जो कुटीर उद्योग हैं वे ग्रामीण अंचल को विकास दे सकते हैं। अगर गांवों के विकास पर कुठाराघात होगा तथा यदि गांवों के मजदूरों

का, किसानों का भोशण करते हुए एस0ई0जैड0 बनाए जाएंगे तो इससे ये और ज्यादा गरीब हो जाएंगे।

**श्री सभापति :** इन्दौरा जी, डिज्नीलैंड का क्या मतलब है ?

**श्री सु गील इन्दौरा :** चेयरमैन सर, आपके पास रिकार्ड है मैंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। चेयरमैन सर, मैं कहना चाहता हूँ कि बड़े-बड़े कारखाने लगाकर चाहे सूई का कारखाना हो, चाहे जूति बनाने का कारखाना हो, चाहे कपड़े बनाने का कारखाना हो, इनसे गरीबों का कोई भला होने वाला नहीं है। चेयरमैन सर, मैं यह नहीं कहता कि दे 1 को विकास को टाटा, बिड़ला और मोदी उंचाईयों पर न ले गए हों लेकिन दे 1 को थोड़ा बहुत नुकसान जरूर पहुंचाया है। अब तो हालात ऐसे हो गए कि इनके भी बड़े-बड़े बाप आ गये। जैसे रिलायंस आ गया, टी0डी0आई आ गया, जरूला आ गया, डी0एल0एफ0 आ गया। सट्टे के बाजार में व्यापारी रातों-रात करोड़पति और अरबपति बन जाते हैं और बिना खून पसीना बहाये ही अरबपति बन जाते हैं और मजदूर वर्ग के लोग उनकी तरफ देखते ही रह जाते हैं। (विधन) इस तरह के सट्टे के व्यापारी कुटीर उद्योग के लोगों का हक मार रहे हैं। सभापति महोदय, हमें उनको रोकना होगा। हमें ऐसी नीतियां अपनानी होंगी जो कि श्रमिक वर्ग की तरफ आंख उठाकर देखती हों और श्रमिक वर्ग सरकार की तरफ देखे और

सोचे कि उसको इस सरकार के माध्यम से रोजगार मिलेगा, उसकी आजीविका का साधन चलेगा।

**श्री मांगे राम गुप्ता :** सभापति महोदय, इनकी सरकार के वक्त में सिरसा में बड़े स्तर पर सट्टे का व्यापार चलता था जिसको श्री ओम प्रकाश चौटाला का आविर्भाव प्राप्त था। उस समय इन्होंने कितने व्यापारी मारे। बहुत सी सट्टे की दुकानें खुलवा रखी थी।

**श्री सभापति :** ये कह रहे हैं कि उस बात को छोड़ो।

**डॉ० सु गिल इन्दौरा :** सभापति महोदय, इस सरकार ने तो यहां तक कर दिया कि खुदरा व्यापारी को भी छुट्टी दे दी। छोटे दुकानदार कहां जाएंगे, जो छोटी-छोटी सी दुकानें खोलकर बैठे हैं, वे कहां जाएंगे। वर्तमान सरकार तो सिर्फ बड़े औद्योगिक घरानों को ही प्राथमिकता दे रही है जो किसान सुबह सब्जी लेकर मंडी में बेचने के लिए निकलता था और भाम तक उस सब्जी को बेचकर अपना गुजारा चलाता था, वह तो असहाय हो गया। जो दुकानदार छोटे से मकान में 200-400 रुपये लगाकर छोटी सी दुकान खोल लेता था वह अब कहां जाएगा, ऐसी कोई नीति सरकार को अपनानी चाहिए जिससे गरीब लोगों का कामकाज चलता रहे। अगर औद्योगिक घराने मोटा पैसा लगाकर एक व्यापार में आएंगे तो क्या उन छोटे दुकानदारों पर बुरा असर



नहीं पड़ेगा, जिनका सीधा संबंध कुटीर उद्योग से हैं, क्या वे अपना सामान बेच सकेंगे ? (विघ्न)

**डॉ० वि० भांकर भारद्वाज :** सभापति महोदय, जिस बात का ये जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। (विघ्न)

**श्री सभापति :** डॉ० साहब आपको इस बारे में बाद में बोलने का मौका दिया जाएगा।

**Dr. Sushil Indora :** Speaker Sir, Hon'ble member is disturbing me. (interruption) O.K. I continue my speech. सभापति महोदय, मेरी जो भांका थी, मैं जो बात कहना चाहता था वह यह है कि हरियाणा की सरकार को उस गरीब का, उस दुकानदार का हितैशी होना चाहिए और गरीब की परवाह करनी चाहिए। खुदरा व्यापारी जो काम करता है और छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों से सामान लेकर बेचता है, उनको बढ़ावा देने की स्कीम होनी चाहिए। बड़े व्यापारी मॉल खोलेंगे तो मॉल में तो समृद्धि पाली लोग ही आ सकते हैं। चेयरमैन सर, प्रदेश की सरकार विकास की उच्च दर होने का दावा करती है और वार्षिक विकास की दर को कीर्तिमान बताया गया है। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह इनकी सोच हो सकती है लेकिन सच्चाई यह है कि वास्तव में बेरोजगारी बढ़ी है। हौजरी के व्यापारी और पानीपत में हथकरघा उद्योग के लोग जो हैं। ये उस आर्थिक विकास की वजह से बर्बाद हुए हैं, न कि अपने कार्यक्रम से।

क्योंकि ऊंची विकास दर पाने के लिए पूंजीपतियों ने सारी अर्थ-व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया है। गरीब आदमी जो हथरघा, हौजरी, कुटीर उद्योग के लोग हैं वे पिछड़ते चले गये और उन्हें अपनी आजीविका चलाने में दिक्कत आ रही है। सर, मैं समझता हूँ कि पिछले दशक में देश में जो बेरोजगारी की प्रतिशतता थी वह तकरीबन 6 प्रतिशत थी जो वर्तमान हालात में 8 प्रतिशत से ऊपर चली गई है। मेरे पास राष्ट्रीय असंगठित उद्योग निगम की रिपोर्ट है जो हाल ही में आई थी जिसमें कहा गया है कि देश के राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की हालत यह है कि 77 प्रतिशत लोग सिर्फ 20 रुपये दैनिक पर अपना जीवन यापन करते हैं। एक गरीब आदमी अपना गुजारा कैसे करेगा और सरकार कह रही है कि श्रमिकों को काम मिला है। मेरे पास इस बारे में आंकड़े हैं, उनमें कहा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि देश विकास की ओर जा रहा है। (विधन) सर, मैं कुटीर उद्योगों के बारे में देश और प्रदेश की बात कर रहा हूँ आंकड़े जो छांटने होंगे तो सरकार छांटे। मैं छांट लूंगा तो फिर सरकार क्या करेगी ? (विधन)

**श्री सभापति :** इन्दौरा साहब, हरियाणा में कुटीर उद्योगों की क्या पोजीशन है आप इसके बारे में सदन को बतायें। (विधन)

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला :** चेयरमैन सर, मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूँ ये फिर भटक गये हैं इनका जो

प्राईवेट मैम्बर रैजोल्यूशन है वह कुटीर उद्योगों विशेषकर पारंपरिक उद्योगों के बारे में हैं जिनके बारे में इन्होंने सदन में प्रस्ताव दिया है।

**डॉ० सुशिल इन्दौरा :** चेयरमैन सर, क्या यह प्रदेश में कुटीर उद्योगों का हिस्सा नहीं है ?

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला :** सभापति महोदय, डॉक्टर साहब को सदन में यह बताना चाहिए कि हरियाणा में कुटीर उद्योगों की हालत कैसी है ? ये आसाम, तमिलनाडू के फिगर कोट करेंगे और कहेंगे कि हरियाणा में कुटीर उद्योग कम हो गये हैं।

**श्री सभापति :** इन्दौरा साहब, आप यह बतायें कि एस०ई०जैड० गुड़गांव में बन रहे हैं या चौटाला गांव में बन रहे हैं। आपने जो रैजोल्यूशन दिया है उस पर बोलिये। हाउस को मिसलीड मत कीजिए।

**डॉ० सुशिल इन्दौरा :** सभापति महोदय, मैं मिसलीड नहीं कर रहा हूँ यह तो सरकार बतायेंगी। मेरे पास जो आंकड़े हैं मैं तो उनके आधार पर ही बता रहा हूँ।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला :** चेयरमैन सर, माननीय सदस्य का गैर सरकारी संकल्प है वह प्रदेश में कुटीर उद्योगों विशेषकर पारंपरिक उद्योगों के बारे में हैं जिनके बारे में इन्होंने सदन में प्रस्ताव दिया है। इस बारे में इन्हें बताना चाहिए। इनके पास अगर हरियाणा के कुटीर उद्योगों के बारे में आंकड़े नहीं हैं

तो कोई बात नहीं मैं इनको ये आंकड़े दे दूंगा। आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए तब तक सुन लीजिए।

**श्री सभापति :** इन्दौरा साहब, आप सुझाव दीजिए। आप उन्हीं बातों को बार-बार रिपीट कर रहे हैं इससे ज्यादा आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है।

**डॉ० सु गील इन्दौरा :** सर, हाउस में टीका-टिप्पणी करने की परम्परा हो गई है यह कोई प्रक्रिया नहीं है। (विघ्न) This is not the way. मैं दे 1 और प्रदे 1 का जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ कि यह आर्थिक मुद्दे से जुड़ा है। मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा।

**श्री सभापति :** इन्दौरा साहब, आपने यू०पी० और राजस्थान में कहा था उसका क्या रिजल्ट निकला। आप प्रस्ताव पर बोलिये।

**डॉ० सु गील इन्दौरा :** सभापति महोदय, मुझे बोलने नहीं देना चाहते तो मैं बैठ जाता हूँ। मैं रैजोल्यू 111 पर ही बोल रहा हूँ आपको यह लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप रुलिंग दे दीजिए। (विघ्न)

**श्री सभापति :** बोलिये, आप क्या कहना चाहते हैं ?

**डॉ० सु गील इन्दौरा :** सभापति महोदय, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सरकार अच्छे सुझाव दे। हम भी सुझाव देंगे।

(विघ्न) मुझे नेम करके धक्के देकर बाहर निकाला गया और फिर मेरे पास प्रार्थना आई कि आप वापिस आ जाओ और मैं वापिस आ गया। मैं तो नारे लगाते हुए हाउस से बाहर चला गया था।

(विघ्न) सभापति महोदय, अब भी अगर आप कहें तो मैं चला जाऊंगा। मुझे चेयर की तरफ से जो आदे 1 होगा मैं उसको सिर माथे करूंगा। सभापति महोदय, अब मैं दे 1 की कुछ बातें कहना चाहूंगा। गत वर्षों में सरकार ने ऐसे कई उद्योगों में विकास किया जिन्होंने दे 1 को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है लेकिन इससे गरीब श्रमिक का और गांव में रहने वाले का कोई खास लेना देना नहीं है। इससे गरीब आदमी को कहीं उम्मीद नहीं है कि इन उद्योगों से मिलने वाली रोजी-रोटी से उसका काम चलेगा। आज के दिन आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के लिए जो काम किए गए हैं उसमें कई उद्योग हैं जैसे दवा निर्माण, ऑटो निर्माण आदि। आटो निर्माण में जैसे अभी पिछले दिनों टाटा कम्पनी ने सवा लाख रुपये में लखटकिया कार की बात की थी। सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, मनोरंजन और बैंकिंग ये आज के युग में ऐसे-ऐसे उद्योग आ रहे हैं जिनका दे 1 में असर पड़ने के साथ-साथ उनका असर हमारे प्रदेश में भी पड़ेगा और ये दे 1 की आर्थिक वृद्धि दर को निर्धारित करने का काम करते हैं।

(विघ्न) हमने इन्फर्मे 1न एण्ड टैक्नोलोजी में भी बहुत उन्नति की है और अभी पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी चंडीगढ़ में आए थे और उन्होंने चंडीगढ़ में भी आई0टी0 पार्क बनाने की बात की थी। सभापति महोदय, मैं यह नहीं कहता कि हमने प्रगति नहीं की,

इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने प्रगति की है। प्रतिस्पर्धा के दौर में आज पूरी दुनिया छोटी हो गई है। पहले अमेरिका जाना हमारे लिए एक सपना होता था। आज ग्लोबलाइजे इन होने की वजह से व्यापार के लिए आने-जाने के रास्ते बढ़े हैं। हमने हर तरफ विकास किया है। ऑटो मार्केट में हमने बहुत उन्नति की है। सभापति महोदय, इन क्षेत्रों में उन्नति करते-करते हम कृषक को भूल गए हैं। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है इसलिए हमें कृषक की तरफ भी ध्यान देना होगा और उसकी लागत मूल्य को हम कम करते और उसके साथी दस्तकारों का भी हम ध्यान रखते तो ज्यादा अच्छा होता। पहले जिस आदमी को खेत में मजदूरी मिल जाती थी वह अपनी आजीविका चला लेता था लेकिन आज उसको बाहर में भी मजदूरी नहीं मिलती और वह रोजगार ढूँढता रह जाता है तथा बेचारा भूख से तड़पता रह जाता है। सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात जो औद्योगिक आधार पर देश के व्यापार के लिए मापदंड बने हैं इससे केवल मुट्ठी भर लोगों को फायदा होगा। हमारे वित्त मंत्री महोदय ने स्पष्ट कहा है कि अर्थ व्यवस्था के विकास को सार्थक बनाने के लिए आवश्यक है कि उसका लाभ कुछ व्यक्तियों तक सीमित न रहकर समाज के सभी व्यक्तियों को बराबर रूप से मिले। यह अच्छी बात है, मैं नहीं कहता कि गलत बात है लेकिन उसका कियान्वयन कैसे होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ? जो लाभ मुट्ठी भर लोगों के पास जाना है वह लाभ गांव के गरीब आदमी के पास पहुंचे, गांव के आम आदमी के पास रोजगार पहुंचे। सभापति महोदय, मेरी राय

है कि वर्तमान अर्थनीति दे 1 को विकास के रास्ते पर नहीं ले जा रही है इसलिए मेरा कहना है कि दे 1 का वास्तविक विकास उसके संसाधनों में है। हमारे दे 1 के संसाधन उसके कुटीर उद्योग हैं जिनसे आम आदमी को रोजगार मिलता है। सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान सरकार की एक रोजगार योजना की तरफ दिलाना चाहूंगा कि ग्रामीण रोजगार योजना के तहत गांव के गरीब लोगों को रोजगार देने की एक असफल चेश्टा सरकार की तरफ से की गई है। इसमें सरकार को देखना चाहिए कि वास्तव में कितने लोगों को फायदा पहुंचा है। इसमें जो नियम निर्धारित किए गए थे उनकी पालना भी प्रोपर तरीके से नहीं हुई है। मेरे सिरसा जिले में यह स्कीम चल रही हैं। जहां पर किसान के खेत होते थे वहां पर जोहड़ खोद दिए गए। यह योजना प्रदे 1 में पहले दो जिलों में चल रही थी अब इसको चार जिलों में किया जा रहा है। क्या बाकी जिलों में गरीब आदमियों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए ?

**श्री फूलचंद मुलाना :** सभापति महोदय, ये बजट पढ़कर देखें। अब यह स्कीम पूरे प्रदे 1 में लागू की जा रही है।

**डॉ० सु लिल इन्दौरा :** सभापति महोदय, यही बात मैं इनसे कहलवाना चाहता हूं लेकिन जिस समय इनको कहनी चाहिए उस समय कहें लेकिन पता नहीं इनको किस बात की जल्दी है। ये पहले ही बोल पड़ते हैं, इनको धैर्य रखना चाहिए। सभापति महोदय, इस बारे में सी०ए०जी० की रिपोर्ट क्या कहती है उसकी

तरफ भी सरकार ध्यान दे। इस स्कीम का क्रियान्वयन कैसे हुआ है, उसको दो साल के करीब हो गये हैं। उसमें सच्चाई कितनी है यह तो सरकार अपने जवाब में बता दे। लेकिन सी0ए0जी0 की रिपोर्ट में लिखा है कि इस स्कीम के लिए 12 हजार करोड़ रुपये की निर्धारित राशि थी उसमें से 3 प्रतिशत लोगों को 18 दिन के लिए रोजगार मिला। जिसके हिसाब से तकरीबन 100 करोड़ रुपये खर्च किया गया है। इसके अलावा जो पैसा गरीबों को मिलना चाहिए था वह पैसा कहां गया, कौन खा गया है। इसके अलावा जो पैसा गरीबों को मिलना चाहिए था वह पैसा कहां गया, कौन खा गया यानि कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। इसलिए सरकार इस तरफ ध्यान दे। सभापति महोदय, मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि पारम्परिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मेरे कुछ सुझाव हैं उनकी तरफ सरकार ध्यान दे। सरकार को पारम्परिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी का नारा देना चाहिए। कुछ आईटम ऐसे हैं जिनको कुटीर उद्योगों की मार्केटिंग को बढ़ावा देने के साथ-साथ आर्थिक मदद को भी बढ़ावा होगा। सभापति महोदय, पिछले तीन साल से सरकार कह रही है कि वे गांवों में 24 घंटे बिजली देंगे लेकिन आज के दिन गांवों में पांच-पांच, सात-सात घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है। अगर कुटीर उद्योगों को बिजली नहीं मिलेगी तो वे कैसे चलेंगे। सरकार तीन साल से कोशिश कर रही है लेकिन किसी को भी बिजली नहीं मिल रही है। सभापति महोदय, आप सभी जानते हैं कि कहीं भी विकास के लिए पानी चाहिए होता है लेकिन आज के दिन



प्रदेशों में बहुत सी जगहों पर पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है तो विकास कहां से होगा। जो गांव नहरों की टेल पर बसे हैं वहां भी नहरों में पानी नहीं पहुंच रहा है तो लोग वहां कैसे रहेंगे ? सरकार का दायित्व है कि वह इन्फ्रास्ट्रक्चर को पूरा करे। आज के दिन प्रदेशों में न पीने के लिए पानी है, न सिंचाई के लिए पानी है, न बिजली है और न सड़कें हैं। इसलिए सरकार को इनकी तरफ ध्यान देना होगा और आधारभूत ढांचे को सुधारना होगा तभी जाकर गांवों में कुटीर उद्योग लगेंगे और उनको बढ़ावा भी मिलेगा। इसके अतिरिक्त कच्चा माल सस्ते में उपलब्ध करवाना होगा और जो तैयार माल होगा उसको बेचने की भी व्यवस्था करना होगी। सभापति महोदय, एक तरफ हम एजूसैट की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ओवरसीज इम्प्लोयमेंट स्कीम के तहत मजदूरों को विदेशों में भेजने की बात भी करते हैं। इसके बजाय सरकार कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उनमें तैयार माल को एक्सपोर्ट करने के बारे में क्यों नहीं सोचती ? अपने कुटीर कारीगरों को विदेशों में भेजने के बजाय अगर हम उनको यहीं कुटीर उद्योगों में काम देकर उनमें बने माल को एक्सपोर्ट करके उनसे यहां लाभ लेना चाहें तो उन द्वारा बनाये गये माल को विदेशों में निर्यात करके उनको अच्छे आमदनी के साधन और मुनाफा दिला सकते हैं और इससे उनको रोजगार भी मुहैया कराया जा सकता है। इससे कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा मिल सकता है सर, मेरा सुझाव है कि कुटीर और लघु उद्योगों को भी बढ़ावा मिल सकता है। सर, मेरा सुझाव है कि कुटीर और लघु उद्योगों के लिए सस्ते

और सुलभ कच्चे माल की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। वि. 1 तौर पर आर्थिक सहायता के साथ-साथ संसाधनों की भी जरूरत है। मेरा सरकार से विनम्र अनुरोध है कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाये जिसमें इस पर चर्चा हो कि किस प्रकार से कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाये। डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर एक कमेटी बनाई जाये जिसमें वहां बैठकर लोग चर्चा करें कि कैसे इन लोगों को लाभ हो सकता है, कैसे हथकरघा उद्योग बढ़ सकता है और कैसे पारम्परिक उद्योगों को बढ़ावा मिल सकता है ?

**श्री सभापति :** डॉ० साहब आप अपने सुझाव भी तो दो।

**डॉ० सु गील इन्दौरा :** सभापति महोदय, मैंने अपना सुझाव दे दिया है कि इस विषय पर एक कमेटी बनाई जाए। मैंने यह भी कहना है कि कुछ आईट्म को तो कुटीर उद्योगों में ही मिलना चाहिए। उसकी परिभाषा ही कुटीर उद्योग के साथ जोड़कर कर दी जाये। इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। सभापति महोदय, इस प्रकार से अनेक प्रयास होने चाहिए। चेयरमैन सर, इसी अनुरोध के साथ मैं यह बता कहना चाहूंगा कि यह एक बहुत ही लोक महत्व का विषय है। मेरा अपने साथियों से अनुरोध है कि वे इस बारे में अपने विचार रखें। इसके साथ ही मैं सदन का और आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का पूरा मौका दिया और इसी के साथ सरकार से अनुरोध करूंगा कि यह जो गैर सरकारी प्रस्ताव है वह इसको

अडॉट करे और इस पर कार्यवाही करें। इसी के साथ मैं यह प्रस्ताव मूव करता हूँ। धन्यवाद सर।

**Mr. Chairperson :** Motion moved –

“This House expresses its great concern over the continuous demotion of the cottage industries, particularly traditional industries in the State as the cottage industry is only capable to provide employment to the skilled and unskilled labourer class of the rural areas of the State.”

श्री भादी लाल बतरा (रोहतक) : सभापति महोदय, डॉ० इन्दौरा ने आज इस सदन में जो प्रस्ताव रखा कि हरियाणा में कुटीर उद्योग खत्म हो रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है इसमें भायद इन्होंने सारे वाक्यात का जायजा नहीं लिया। पूरे हालात का जायजा नहीं लिया और किस साल की बात ये कर रहे थे और आज हम कौन से साल में हैं इसका भी इन्होंने जिक्र नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, 1966 में हरियाणा बना उस वक्त हरियाणा की कुल आबादी 91 लाख थी और आज हरियाणा की आबादी 2.35 करोड़ हो चुकी है। उस वक्त हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय क्या थी और आज मौजूदा सरकार के कार्यकाल में प्रति व्यक्ति आय क्या है ? इन सब बातों का भी जिक्र नहीं किया गया है। उस वक्त हमारी प्रति व्यक्ति न्यूनतम मजदूरी क्या थी और आज प्रति व्यक्ति न्यूनतम मजदूरी क्या है इसका भी जिक्र नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, यह सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी किसी चीज का फैसला करना होता है तो उससे पहले वाले समय

के साथ उसका मुकाबला किया जाता है कि पहले क्या था और आज क्या है और अगर कमी आई है तो क्यों आई है और अगर बढ़ौतरी हुई है तो क्यों हुई है। सबसे पहले आज अगर हम शिक्षा के क्षेत्र को लें तो शिक्षा के क्षेत्र में जब श्री राजीव गांधी ने कम्प्यूटर का प्रबंध करने के आदेश दिए और यह कहा है कि कम्प्यूटर का प्रयोग बड़े पैमाने पर होना चाहिए तो कुछ विपक्षी नेताओं ने यह कहा था कि अगर हिन्दुस्तान में कम्प्यूटर आ गया तो कितनी आबादी बेरोजगार हो जायेगी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता और जैसे हिन्दुस्तान में पहले ही बहुत ज्यादा बेरोजगारी है कम्प्यूटर के आ जाने से बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ जायेगा। उनका कहना था कि कम्प्यूटर के आ जाने से बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ जायेगी और जब कम्प्यूटराईजेशन हुआ तो उससे हमारा लाईफ स्टैण्डर्ड क्या हो गया और इससे कितनी एम्पलायमेंट बढ़ी इसके लिए इन्दौरा साहब ने कोई जिक्र नहीं किया। इसके बाद उन्होंने यह कहा है कि प्रदेश में एस0ई0जैड0 आ रहे हैं। एस0ई0जैड0 की जो भारुआत हुई थी वह मौजूदा सरकार के समय में न होकर पिछली सरकार के समय में हुई थी। उन्होंने ही एस0ई0जैड0 के लिए भूमि का अधिग्रहण भी किया था और आज की मौजूदा सरकार ने कहा कि नहीं हम एस0ई0जैड0 के लिए कोई जमीन अधिग्रहण नहीं करेंगे। अगर कोई भी एस0ई0जैड0 आता है तो वह किसानों से बात करके सीधे जमीन ले सकता है। इसके लिए वह अपने स्तर पर बात कर ले। यह उनके व्यापार की बात है। डॉ० इन्दौरा यह कह रहे थे कि एस0ई0जैड0 आ गये

लेकिन इन्होंने एक बात और नहीं सुनी कि हिन्दुस्तान की आजादी के समय हमारे पास किसानों के पास जमीन कितनी थी और उस आजादी के बाद जब सिक्क्योरिटी ऑफ लैंड टैन्थोर एक्ट आ गया और सीलिंग लग गई और सीलिंग लगने के बाद आज किसानों के पास जमीन बहुत कम रह गई है। किसी के पास आधा एकड़ किसी के पास एक एकड़ और किसी के पास दो एकड़ जमीन बची है। इतनी थोड़ी जमीन में खेती नहीं हो सकती। लेकिन उसको साधन देने होंगे ताकि वह आगे बढ़ सके और अपने परिवार का गुजारा कर सके तथा समाज की मुख्य धारा में रह सके। चौटाला सरकार तो यह चाहती थी कि मुख्य धारा से कितने लोग कटें। कितने लोग चाकू से, पिस्तौल से और कट्टे से गुजारा करके आयेँ और हमें भी खिलाएं। इन्होंने ग्रामीण अंचल का सहारा लिया। ग्रामीण अंचल में शिक्षा कम थी और वे लोग जल्दी भटक जाते थे। हरके नौजवान को कहते थे कि यह लो पिस्तौल और लूटकर लाओ, खुद भी खाओ और हमें भी खिलाओ। इनका ध्यान कुटीर उद्योग की तरफ था ही नहीं। इनका ध्यान तो एक ही तरफ था कि इस स्वर्ग को इस समाज को नेस्तनाबूद करना है। पहले कुटीर उद्योग क्या था ? ये कहते हैं कि जूती बनती थी और उसके बाद क्या होता था, कुछ भी नहीं। आज किसान की बात की जाये तो कुटीर उद्योग के रूप में मारूम की खेती होती है। भाहद का उत्पादन भुरू हो गया है। उसके बाद अगर उनकी पैकिंग करके भाहरों में भेजते हैं तो यह कम्पीटी उन कहा जाता है। इन्दौरा जी, हकीम की बात कर रहे थे लेकिन अब लैटेस्ट

टैक्नोलॉजी आ गई है, बाईपास सर्जरी आ गई है। अगर आप पहले की नवजात बच्चों की मृत्यु दर देखें तो पायेंगे कि पहले बहुत ज्यादा थी लेकिन आज एक लाख पर 222 रह गई है। उसी प्रकार प्रसव के दौरान माताओं की मृत्यु दर देखी जाये जो पहले एक लाख पर 300 थी लेकिन अब एक लाख पर 145 रह गई है। हकीम के पास जायें लेकिन हकीम के पास वह टैक्नोलॉजी नहीं है। एक बार एक आदमी एक हकीम के पास अपनी भैंस को लेकर गया। उसका गला सूजा हुआ था। हकीम ने देख लिया कि इसके गले में खरबूजा फंसा हुआ है। उसने एक ईंट उठाई और भैंस की गर्दन पर मार कर उस खरबूजे को फोड़ दिया और भैंस ठीक हो गई। उस आदमी ने सोचा कि हकीम बनना तो बहुत आसान है। कुछ दिन बाद दुर्भाग्य से उस आदमी की मां बीमार हो गई। उस आदमी ने सोचा कि इस काम के लिए हकीम के पास जाने की क्या जरूरत है, उसने एक ईंट उठाई और अपनी मां की गर्दन पर मार दी उसकी मां की मौत हो गई। अब आप ही बताइये कि हकीम के पास जायें या लेटेस्ट टैक्नोलॉजी के पास जायें। मेरे विचार में जो बीमारी है पहले उसके कारण का पता लगाना चाहिए तब ही बीमारी का इलाज किया जा सकेगा। पहले कहते थे कि फलां आदमी बैठे-बैठे मर गया बेचारे की किस्मत अच्छी थी। यह कोई नहीं जानता था कि हर्ट-अटैक से मौत हुई है। आज वह जमाना नहीं रहा, आज हमें जमाने के साथ बदलने की जरूरत है। इसी तरह से शिक्षा के बारे में कहा गया। इन्दौरा जी कैसी शिक्षा चाहते हैं ? ये 20वीं सदी की बात कर रहे हैं या 21वीं

सदा की बात कर रहे हैं या आने वाले समय की बात कर रहे हैं। हम आने वाली पीढ़ियों को क्या देने वाले हैं। आने वाली पीढ़िया क्या कहेंगी कि आने वाले समय में अपनी आजीविका कैसे कमाएं? आज कम्प्यूटर का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। अगर हमें दुनिया के मुकाबले में ऊपर जाना है तो उसके लिए कुछ न कुछ अव्यय करना होगा। ऐसी शिक्षा देनी होगी जो हमें आगे ले जाये। एक बात इन्दौरा जी ने अव्यय ठीक कही है कि दुनिया छोटी हो गई है, ग्लोबलाईजेसन आ चुका है तो क्या ग्लोबलाईजेसन में हम अपने आपको फिर आईसोलेट कर दें, अपने आपको रोक लें कि हम एक गांव में बैठे हैं और हमें कुटीर उद्योग से आगे नहीं जाना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो सिर्फ हरियाणा ही नहीं पूरा हिन्दुस्तान पीछे आ जायेगा और दुनिया में इसका कोई स्थान नहीं रहेगा। अध्यक्ष महोदय, अगर हमें कोई भी निर्णय लेना है तो हमें देखना होगा कि मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है और यह देश क्या कर रहा है और हम अपने देश को कहां पर ले जाना चाहते हैं। यहां पर विशेष आर्थिक जोन की बात चल रही थी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री के साथ मुझे भी चीन जाने का मौका मिला था। वहां सेज को देखने के बाद उनके जो कमेंट्स थे, मैं आपको वे कमेंट्स भी कहना चाहता हूं। उनके कमेंट्स थे कि आज इंडिया में इतनी शिक्षा आ गई है, आज इंडिया का नौजवान इतना सक्षम हो चुका है कि वह अपने घर में बैठकर अपना काम चला रहा है। उन्होंने कहा था कि अगर आज इन्डस्ट्री चाईना में है तो ऑफिस इण्डिया में है और वह अपना

बिजनैस इण्डिया से ही कंट्रोल कर रहा है। सभापति महोदय, चाईना में अंग्रेजी की कोई शिक्षा नहीं थी, कम्प्यूटर की शिक्षा नहीं थी और उसने जितना भी इम्प्लॉयमेंट लेना था वह वहां पर बिना अंग्रेजी या कम्प्यूटर शिक्षा के ही लिया था। यही कारण है कि आज गुड़गांव में कितने ही कॉल सेंटरज हैं कि वहां पर आज बच्चे देहली से काम करने के लिए जा रहे हैं। क्या हम यह न सोचें कि दिल्ली की जो शिक्षा है उसी तर्ज पर हम अपने भाहरों में भी शिक्षा को इम्प्रूव करें। अगर हम अपने बच्चों को टैक्नीकल एजुकेशन दें तो हमारे हरियाणा के जो बच्चे हैं वे वहां पर काम कर सकेंगे। अगर कॉल सेंटर गुड़गांव में है तो वहां पर काम करने के लिए देहली के बच्चे आते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि चाहे गांव हो या भाहर हो हम अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाएं। इस मौजूदा सरकार ने शिक्षा तथा टैक्नीकल एजुकेशन से पहले से तीन गुणा बजट कर दिया है। इस बजट को तीन गुणा करने के पीछे अभिप्राय एक ही है कि ग्रामीण नौजवान को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वे अपना रोजगार हासिल कर सकें। यही वजह थी कि पहली क्लास से इंग्लिश में पढ़ाई शुरू कर दी ताकि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि आगे चलकर वे अपने आपको अच्छा नागरिक साबित करें और अपनी आजीविका के लिए बाहर निकल कर काम करने में पारंगत हो जाएं। आज डॉक्टर इन्दौरा साहब यह प्रस्ताव लाए हैं –

“This House expresses its great concern over the continuous demotion of the cottage industries, particularly



traditional industries in the State as the cottage industry is only capable to provide employment to the skilled and unskilled labourer class of the rural areas of the State.”

अब मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। आज के युग में सिर्फ कॉटेज इन्डस्ट्रीज इम्प्लॉयमेंट नहीं देगी। कॉटेज इन्डस्ट्रीज से आगे बढ़ना सम्भव होगा। सभापति महोदय, मौजूदा सरकार ने आदर्श गांव बनाने का निर्णय लिया था। जब आदर्श गांव बनाने का निर्णय लिया था तो उस वक्त एक सोच आई थी कि क्या गांव में गलियां पक्की कर देने से आदर्श गांव बन जाएगा। वहां पर सीवर और पानी दे दें तो क्या गांव आदर्श गांव बन जाएगा लेकिन उसके साथ ही साथ एक सोच यह भी थी कि गांव में रहने वाले हर व्यक्ति को चाहे वह किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी हो उसकी आय के साधन बढ़ने चाहिए। जब आय के साधन बढ़ाने की स्टडी की गई तो फिर यह बात सामने आई कि अगर हम ऐसा कर भी दें तो हम गांव में कम्पीट नहीं कर पाएंगे इसलिए उसको आगे बढ़ाना होगा। गांव में जो भी सामान बनेगा वहां गांव में उसकी कम्पैटिशन नहीं होगी और उसके लिए बाहर में आना होगा। बाहर में आ कर दूसरी जगहों पर भी अपना उत्पादन बेचना होगा। एक सवाल यह भी था कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी और बाहर वालों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी। अगर बाहर वाले गांव में जाकर सामान बनाते हैं तो उनको ज्यादा लाभ मिलता है क्योंकि उनके पास अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर होता है। मौजूदा सरकार इस बात को

बड़ा ऐन्क्वेज कर रही है कि कोई भी आदमी वहां पर अपना काम करे। क्योंकि वहां पर गांव में कोई व्यवस्था नहीं है और जो नई पीढ़ी आई है जो नई पीढ़ी चली है उसकी सोच बदली है और वे कहते हैं कि हमें काम करना है और काम करके आगे बढ़ना है। यह जो हमारी जमीन थी पहले वे उस जमीन के साथ जुड़े हुए थे क्योंकि जमीन की होल्डिंग इतनी थी कि जमीन बची ही नहीं इसलिए हमें बाहर निकलना ही होगा। आज हमें बच्चों को आगे शिक्षा भी देनी है ताकि वह बाहर में जाकर वहां पर अपना काम कर सकें। आज हरियाणा में देखें तो चाहे कोई भी गांव ले लीजिए हर गांव में वह सुविधा उपलब्ध होगी जिसके चलते हम अपना जीवन सुविधा से बिता सकेंगे और यह ठीक भी है। मैं मौजूदा सरकार का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने यह सोचा कि आदर्श गांव हों एल0ए0डी0टी0 के साथ 10-10 लाख रुपये हों। जिस जिले में वाटर वर्क्स का पानी न हो वहां पर पानी की सप्लाई हो, सड़कें और स्कूल बन गए हैं। अब कितने स्कूल अपग्रेड हो गये ? उसके लिए वहां पर टैक्नीकल ऐजुकेशन के लिए ग्रामीण अंचल में काफी संख्या में स्कूल और कॉलेज खोले गए हैं उनके पीछे एक ही कारण था कि अगर हमें हरियाणा का विकास करना है तो गांव का विकास करना होगा। अगर हमने हर व्यक्ति को आगे ले जाना है तो पहले हमें गांव के किसान और मजदूर को आगे ले जाना होगा क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए हमें जमाने के साथ तबदील भी होना होगा। जमाने के साथ हमें तबदील होना पड़ेगा लेकिन हम अपने आप को यहीं तक

सीमित न करें। आज एक ही कमरे में बैठकर जूती नहीं बन सकती। जूती बनाने के लिए अगर हमें काम करना है और अगर जूती बनानी है तो उसके काम की पूरी स्टडी करनी होगी। आज जूती बनाने के भी कई पॉइन्ट्स और कई प्वायंट्स होते हैं। कोई सोल बना रहा है, कोई जूती सियेगा, कोई आगे का काम करेगा और उस जूती को आगे ऐम्ब्रॉयडरी भी हो रही है; उसी जूती पर अलग-अलग कलर भी हो रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कीमत बाजार से मिल सके और बाजार में कीमत भी मिलती है; जब उसका काम करते हैं तो सारे मामले पर सोच-विचार कर यह देखना होता है कि उस पर आगामी प्रभाव क्या पड़ेगा उसकी कीमत क्या हो, यह सोच कर ही इस बारे में कोई निर्णय लेना पड़ेगा तभी वह काम आगे बढ़ेगा। सभापति महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि डॉ० इन्दौरा साहब ने जो प्रस्ताव पेश किया है वह प्रस्ताव आज की जरूरत के मुताबिक ठीक नहीं है, उनको भी अपने आपको तबदील करना होगा और मुकाबले के लिए आगे आना होगा। अगर हम यह कहें कि यह ठीक है और हमें यहां पर जूती बनानी है तो जूती में आगे जितना डिवलपमेंट हुआ है जितना रिसर्च कार्य हुआ है उस सारी रिसर्च का प्रयोग करके कम्पीटीटिव प्राइस पर जूती भी बनेगी और उसको बाहर भी भेजेंगे ताकि लोग उसको पसन्द भी करें। इसी तरह से यहां पर किसानों की बात हुई थी तो किसानों के लिए केंद्र की सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए के ऋण माफी की घोशणा की है लेकिन उससे पहले हरियाणा सरकार ने भी लैण्ड रैन्ज्यू एक्ट के तहत

कोआप्रेटिव बैंकों से ऋण माफ किए हैं। उन किसानों द्वारा कर्जा लेने के पीछे मजबूरी थी और वह मजबूरी क्या थी कि उन किसानों की इन्कम नहीं थी और उनकी पैदावार न होने की वजह से उनका गुजारा नहीं हो पाता था। अगर गुजारा नहीं होगा तो वे कर्जा ही लेंगे। सभापति महोदय, हरियाणा की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने निर्णय लिया कि अगर हमें प्रदे ा और दे ा को आगे ले जाना है तो हमें किसानों और मजदूरों को ऊपर उठाना होगा। इस वजह से इन्होंने ये कर्जे माफ करने का निर्णय लिया है। हम चाहते हैं कि हमारे किसान और मजदूर समाज की मुख्य धारा में रहें। अगर वह समाज की मुख्य धारा में रहेगा तो दे ा और प्रदे ा का काम अच्छी तरह से चल सकेगा। सभापति महोदय, यह जो किसानों और मजदूरों के लिए फैसला लिया गया है यह बहुत ही लोकप्रिय फैसला है। इसके लिए मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी का, मनमोहन सिंह जी का और हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का धन्यवाद करता हूँ। आज ि ाक्षा में भी गरीब लोगों के लड़कों और लड़कियों को 100 रुपये और 150 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जा रही है। आज सरकार की अच्छी नीतियों की वजह से गरीब आदमी मुख्य धारा में आया है। सभापति महोदय जी, यह जो गैर सरकारी संकल्प डॉ० सु िल इन्दौरा जी लेकर आए हैं इसमें इनको चेंजिज लानी चाहिए। धन्यवाद।

**श्री नरे ा मलिक (हसनगढ़) :** सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इसमें केवल एक दो सुझाव ही देना चाहता हूं। सभापति महोदय, जब मैं 2005 में चुनकर आया था उस वक्त भी मैंने यह सुझाव दिया था। आज जमीन में जो खाद डाली जा रही है उसकी रेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज जमीन में डी0ए0पी0 और यूरिया डाली जाती है। अगर हम यह खाद न डालें तो उपज कम होती है। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस खाद की वजह से हमारे नौजवानों में हार्ट-अटैक की बीमारी फैलती जा रही है। इन खादों में जहर की मात्रा है जो हमारे भारीर में जा रही है। सभापति महोदय, आजकल एक केंचुआ खाद चल रही है और जिन किसानों के पास कम भूमि है वे उसका प्रयोग करें तो उनकी फसल पहले से डयोढ़ा होगी। मेरी आपके माध्यम से सरकार से गुजारि ा है कि सरकार की तरफ से इस केंचुआ खाद की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि हम यह जो जहर आज यूरिया और डी0ए0पी0 के माध्यम से खा रहे हैं आने वाले समय में वह न खाएं। सभापति महोदय, मेरा सरकार को यही सुझाव था। धन्यवाद।

**डॉ० ि ाव भांकर भारद्वाज (भिवानी) :** सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सभापति महोदय, हमारे साथी सु िल इन्दौरा जी ने गैर सरकारी संकल्प में कुटीर उद्योग का विशय तो बहुत अच्छा

लिया है। मेरे काबिल दोस्त की मं ता इस संकल्प, कोटेज इन्डस्ट्री क्या है इस बारे में मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि the cottage industry is a term that was used prevalently during the 18<sup>th</sup> and 19<sup>th</sup> Century to describe the home-based system of manufacturing. This term is also usually, referred to goods or services that produced at home. जैसे सिलाई की, कापिटिंग की, मार्केटिंग की, टाईपिंग की, बुक कीपिंग की और रिपेयर की जितनी भी ये सारी चीजें आती हैं वे सारी की सारी कुटीर उद्योगों में आती हैं। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) अध्यक्ष महोदय, दो और टर्मज हैं जो कुटीर उद्योगों के साथ की हैं। एक को हम कहते हैं एस0एस0आई0 यानि स्मॉल इंडस्ट्रीज और दूसरी को कहते हैं टायनी यूनिट्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वह हैं जो एक करोड़ रुपये से कम कीमत की हैं और टायनी इंडस्ट्रीज वे हैं जो 25 लाख रुपये तक की हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि तीन साल के इस सरकार के कार्यकाल में सरकार की जो भी नीतियां रही हैं उनमें हर स्तर पर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया है। चाहे छोटे उद्योग हों या चाहे बड़े उद्योग हों अगर बड़ा उद्योग पनपेगा तो उनके साथ उसकी एग्जलरी यूनिट्स भी पनपेंगी। स्पीकर साहब, मेरे काबिल दोस्त ने यह भी चिन्ता व्यक्त की है कि जो बड़े-बड़े कारपोरेट सैक्टर आ रहे हैं, वे छोटे उद्योगों पर, कुटीर उद्योगों पर कुठाराघात पहुंचाएंगे। मैं उनको बताना चाहूंगा कि सरकार भी इस बारे में चिंतित है। इस बारे में प्रावधान भी है कि कानून भी बनाए गए हैं, पोलिसी भी

बनायी गयी है। मैं आपका ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहता हूँ कि the Government of India continues to provide protection to Small Sector through the policy of reserving items for exclusive manufacturing in Small Scale Industries. The industrial undertakings other than the Small Scale Industrial undertakings raised in the manufacture of the items reserve for the exclusive manufacture of Small Scale Sector for required to obtain an industrial license and undertake an export of 50% or more of them. जो दूसरे सैक्टर हैं जिनको लाइसेंस दिया जाएगा उनमें 50 प्रतिशत से ज्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, पहले स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में 1967 में 44 आईटम्ज थी लेकिन बाद में ये बढ़ते-बढ़ते 800 आईटम्ज हो गयी। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज का ध्यान हमें 11 से ही कुटीर उद्योगों का, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज का ध्यान रखा गया है। मैं आपके माध्यम से अपने मित्र के संज्ञान में यह बात भी लाना चाहूंगा कि पूरे देश में करीब 34 लाख यूनिट्स ऐसी हैं जिनको कॉटेज इंडस्ट्रीज में गिना जा सकता है और करीब 146 लाख लोगों को इनमें रोजगार मिला हुआ है। ये जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं these are second to give employment. इनका महत्व हमें 11 भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने जाना है। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे भिवान में दो उद्योग ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ कि नैशनल लैवल पर बहुत ही प्रोमीनेंट हैं। मैं अगर यह कहूँ कि ये नैशनल लैवल पर सबसे ज्यादा प्रोमीनेंट हैं तो इसमें अति योक्ति नहीं होगी। डॉ० इन्दौरा

जी जानते हैं कि वहां पर एक उद्योग तो मैडीकल साईड से ही है। इसमें ऑपरेटिव की टेबल और लाईट्स बहुत अच्छे तरीके से बनायी जाती है। आप देखेंगे कि पूरे देश में करीब-करीब भिवानी से ही इस तरह की लाईट्स एवं टेबल सप्लाई होती है। भिवानी में इस तरह के उद्योग घर-घर लगे हुए हैं। इसका रॉ मैटीरियल करीब-करीब भिवानी में ही मिलता है। जब बड़ी-बड़ी कॉन्फ्रैसिज होती हैं जैसे एसोसिएटिव सर्जिक ऑफ इंडिया या एनेसिथिजिया तो उनमें भी भिवानी के ही लोग अपने-अपने स्टॉल लगाते हैं। काग्नेट कम्पनी तो एक ऐसी कम्पनी है तो बहुत बढ़िया किस्म का माल बनाती है और मनमाने दामों पर बेचती है। इसी तरह से सर्जिडैन्ट कम्पनी है, बैको सर्जिडैन्टस कम्पनी है इस तरह से वहां पर ऐसी 150 कम्पनीज हैं जोकि वहां पर अच्छी तरह से चल रही हैं। ये पिछले बीस वर्षों से अच्छा कार्य कर रही हैं। इसी प्रकार से दाना एवं प्लास्टिक निवार बनाने की फैक्ट्रीज भी 100 से ज्यादा वहां पर हैं। इनमें बहुत से लोगों को रोजगार मिल रहा है। मेरा ख्याल है कि भावनगर और भिवानी ही दो ऐसे भाहर हैं जहां पर इस प्रकार के उद्योग हैं। इस प्रकार की भिवानी की फैक्ट्री में हमारे काफी वर्कर्स ट्रैंड हो गये हैं, स्किल्प हो गये हैं। उनको काफी इम्प्लायमेंट इनसे मिल रही है। भिवानी की फैक्ट्री डायरैक्ट अपना माल नेपाल और मलेेशिया में एक्सपोर्ट कर रही हैं। निवार का जब स्कूल के थैले बनाने में, दरी बनाने में इस्तेमाल होता है तो हमारे भाहर से ही जगह-जगह निवार जाती है। इन्दौरा जी की जैसे बात है, जो पारम्परिक बातें हैं जो आज



भी जारी हैं। आज भी लोहार के पास कस्सी, तसला, फाली आदि सामान मिलता है। उन सब चीजों में आज भी कोई कमी नहीं आई है। हां, यह जरूर है कि अब खेती के काम के लिए ट्रैक्टर आदि बहुत ज्यादा हो गए हैं इसलिए थोड़ी बहुत औजारों की संख्या में कमी अव य आई है लेकिन आज भी उनकी जरूरत है और आज भी वे बनते हैं। बड़े उपकरण आ जाने की वजह से भी नैचुरली कमी आना स्वाभाविक है। अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले में एक गांव बीरन है वहां कई वर्षों से आज भी लकड़ी के मनिए बनते हैं वे सब के सब उसी प्रकार से आज भी बन रहे हैं। (विघ्न) हमारे यहां मैडीकल इंडस्ट्री के सामान भी बनते हैं। भिवानी में हॉस्पिटल का फर्नीचर बनाने की इंडस्ट्री लग गई है और काफी अच्छे स्तर पर फर्नीचर वहां बन रहा है और बन ही नहीं रहा है वरन विदे ां में भी ऐक्सपोर्ट हो रहा है। जहां तक रोजगार मामलों का जिक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सभी को 100 दिन का रोजगार मिल रहा है। हमारे प्रदे ा के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मजदूरों को काम मिल रहा है, हर हाथ को काम मिल रहा है। मेरे काबिल साथी ने इस बात पर भांका जाहिर की है लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदे ा का नाम हैण्डलूम उद्योग में आगे रहा है। हमारे यहां हैण्डलूम का सामान बहुत विख्यात है और तमिलनाडू तक जाता है। इसके अलावा हरियाणा प्रदे ा का स्टील जहां तक हमारा विदे ां के बारे में ऐक्सपीरियेंस हैं, अमेरिका में भी देखने को मिलता है। अमेकिरा में मैसी स्टोर है यह ग्यारह-बारह मंजिल में बना हुआ है। उसमें

जाकर मैंने देखा कि कुछ इंडस्ट्री लग रही हैं, उनमें प्रौडक्शन तो भुरु नहीं हुई है लेकिन उन फैक्ट्रियों को लगाने के लिए वे लोग आए हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को आलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा मेरे काबिल साथी श्री भादी लाल बतरा जी ने बोलते हुए बताया कि कम्प्यूटर आने के साथ-साथ काफी तरक्की आई है। आप सोच के देखें कि श्री राजीव गांधी जी सैम पित्रोदा को अपने साथ न लाते और सिर्फ परम्परागत कामों में ही लगे रहते तो आज जो टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल रही है, क्या वह देखने को मिलती। आज आप कहीं भी बैठे-बैठे कार में बैठे-बैठे, ट्रेन में बैठे-बैठे और यहां तक कि हवाई जहाज में बैठे-बैठे भी फोन पर बात कर सकते हैं। यह सब संभव नहीं हो सकता था। We will have to march with the rest of the world. जो संसार की गति है, पेस है उसके साथ हम नहीं चलेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। यह मैं मानता हूँ कि परम्परागत चीजों को कायम करना चाहिए और वह रहती भी हैं। सरकार की यह मंशा भी है कि उन चीजों को प्रोत्साहन मिले। बड़े उद्योग यदि आगे चलेंगे तो छोटे उद्योग भी साथ-साथ ही चलेंगे। इन भावों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ। धन्यवाद।

**श्री राम कुमार गौतम (नारनौंद) :** स्पीकर सर, इन्दौरा जी का जो प्रस्ताव है वह वैसे ठीक है। उनका इरादा कुछ भी रहा हो और पौलिटिकल भाषण को यदि नजरअंदाज कर दिया जाए तो कुटीर उद्योग जो हैं उनका वाकई में देश में बहुत ही बुरा

हाल है। दे 1 में बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां बहुत आ गई हैं। यह जो बेचारे आर्टिजन क्लास के लोग थे बीच में कई सरकारें ऐसी भी आईं जिनकी नीतियों की वजह से आर्टिजन क्लास को बहुत झटका लगा। समय की यह मांग है कि इन लोगों को कम से कम ब्याज दर पर लिबरल लोनिंग होनी चाहिए। सरकार को इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए और सब्सिडी भी बढ़ानी चाहिए और जो बिजली के रेट हैं जैसे किसान को जिस रेट पर बिजली मिलती है उसी रेट पर इन कुटीर उद्योग मालिकों को भी 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से ही बिजली मिलनी चाहिए और सबसे जो जरूरी चीज है वह कुटीर उद्योग के भाईयों के लिए है क्योंकि by and large यह लोग ज्यादातर गरीब एस0सी0 और बी0सी0 तबके से आते हैं। इसलिए सरकार ऐसी होनी चाहिए जो इन लोगों के पीस ऑफ माईड के लिए खतरनाक न हो। कुटीर उद्योगों के लिए भ्रान्ति, अमन और भाईचारे का माहौल होना चाहिए। बीच में ऐसी सरकारें आईं जिनकी वजह से बड़े-बड़े उद्योग तो पहले ही प्लायन कर गये और छोटे जो बेचारे थे वे गांव छोड़कर कहीं भाहर में बस गये वहां भी उनकी दुर्गति हुई। ये भाई माईड न करें। झगड़ा एक आदमी का होता था लेकिन इनके चले सामाजिक बहिष्कार करा देते थे। उनका गांव से प्लायन हो जाता था। सरकार आंकड़े इकट्ठे कर ले। स्पीकर सर, by and large जो गरीब लोग हैं वे प्लायन कर गये, कुटीर उद्योग के बारे में तो वे सब सोचें जब वहां पर जिंदगी महफूज हो। वहां जो सबसे जरूरी चीज है वह इनकी पीस ऑफ माईड है,

लॉ एण्ड ऑर्डर की पोजी इन बढ़िया और भाईचारे का माहौल होना चाहिए। स्पीकर सर, मैं एक छोटी सी बात बताना हूँ। लाबी गांव में बहुत मुद्दत पुराने मुजारे थे वे चौधरी देवीलाल के परिवार के मुजारे थे। जब इनैलो की सरकार आई तो इन्होंने गुण्डे बुलाकर, पुलिस बुलाकर, तहसीलदार बुलाकर उन बेचारे मुजारों को गांव से भगा दिया। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि चण्डीगढ़ से दिल्ली जी०टी० रोड वाली सड़क बन रही थी। हमारे विपक्ष के भाई जिस पार्टी में शामिल हैं उनके नेता की सरकार थी। उन्होंने कहा कि यह सड़क कौन बना रहा है ठेकेदार को बुलाओ। ठेकेदार को बुला लिया गया। उसको कहा कि तुम मेरी सल्तनत में सड़का बना रहे हो। तूने अब तक मेरे से न मुलाकात की और न ही मुझे अब तक नजराना पे 1 किया। सड़क मेरी सल्तनत में बना रहे हो। उस ठेकेदार ने कहा कि सर, हमारे को जो कान्ट्रैक्ट मिला है वह सैन्टर से मिला है और जो हमने कमी इन देना था वह सैन्टर में दे चुके हैं। सड़क का ठेका जो छूटता है वह हमारा सैन्टर से छूटता है इसलिए स्टेट से हमारा कोई कनैक्ट इन नहीं होता। तब उसको कहा कि तू नहीं जानता यह ओम प्रका 1 चौटाला का स्टेट है। यहां अगर सड़क बनाना चाहते हो और जिन्दगी सेफ चाहते हो तो इतने करोड़ रुपये ले आना वरना सड़क को बंद कर देंगे। यह रिकार्ड की बात है उस ठेकेदार ने यह कहा कि क्योंकि आजकल कप इन का जमाना है मैंने तो जो कुछ किया है वह ऊपर से ही किया है अगर मैं आपको दे दूंगा तो मैं तो तबाह हो जाऊंगा और वह यह कह कर

उस काम को बीच में ही छोड़कर चला गया। (विघ्न) मैं जो कुछ कहता हूँ सच्चाई कहता हूँ अगर ऊपर वालों ने गड़बड़ी करी होगी तो वह भी माड़ी बात ही थी। हमारी पार्टी बी०जे०पी० ने चौटाला जैसे का राज चलाया यह ओछापन नहीं था तो क्या था ? मैं स्पष्ट बात कहता हूँ सही बात चाहे मेरे भाई की हो, चाहे और किसी की हो। उसके बाद वह ठेका मुझे एग्जैक्ट एमाउंट तो नहीं पता, पी०डब्ल्यू०डी० के भाई कैलकुलेट करके बता देंगे इन भाइयों की आंखें खुल जायेंगी कि वे जिस गिरोह में विपक्ष के भाई भामिल हैं फिर कई साल तक जी०टी० रोड बनना बंद रहा और उसके बाद कई करोड़ रुपया फालतू में लगकर बहुत साल के बाद वह रोड दोबारा बना। अध्यक्ष महोदय, कुटीर उद्योगों को चलाने के लिए जरूरत है कि उनको लिब्रल लोनिंग की व्यवस्था हो, ब्याज की प्रति ातता बिल्कुल कम हो और मैक्सीमम सब्सिडी हो। गांव में कंजीनियल माहौल हो। इन उद्योगों के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी है वह है कि लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति ठीक हो। अध्यक्ष महोदय, आप इनका ब्यौरा मंगवाएं कि 5 साल में कितने गरीब गांव से उजड़ कर चले गए थे, कितने इंडस्ट्रियल यहां से प्लायन करके चले गए। जब ये सरकार में आते हैं तो आम आदमी को ऐसे डर लगता है जैसे कोई हौवा आ गया हो। कुटीर उद्योग वाले तो इनकी भाक्ल से डरते हैं। मैं इन \*\*\*\*\* भाइयों की मजबूरी समझता हूँ क्योंकि मैं इनको पर्सनली जानता हूँ। Basically they are very nice people. I respect them. मैं इनकी

इज्जत करता हूं। ( गोर एवं व्यवधान) आप तो हमारे रि तेदार हैं, आप तो रि तेदारी निभाया करो। ( गोर और व्यवधान)

**श्री बलवंत सिंह :** अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हमें जो अनपार्लियामेंट्री भाब्द कहा है वह रिकार्ड नहीं होना चाहिए। ( गोर एवं व्यवधान) सम्मानित सदस्य केवल अपनी बात रखें।

**श्री अध्यक्ष :** गौतम जी, आप नॉन ओफिशियल रैजोल्यूशन पर ही बोलें। ( गोर एवं व्यवधान)

**श्री बलवंत सिंह :** अध्यक्ष महोदय, हम किसी के सहारे नहीं आए, हमें जनता ने चुनकर भेजा है। ( गोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** गौतम जी ने जो अनपार्लियामेंट्री भाब्द का प्रयोग किया है वह रिकॉर्ड न किया जाए। ये तो आपको nice people कह रहे हैं, पता नहीं किस हिसाब से ये आपको रिलेटिव बता रहे हैं।

**श्री राम कुमार गौतम :** अध्यक्ष महोदय, सूरजभान के ये समधी हैं और सूरजभान हमारा बड़ा भाई है। ये तो गलत महकमें में चले गए। ( गोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूं जिसको हाउस में हाजिर सभी लोग मानेंगे। कई भाई अंधेरे में डले ढोने के लिए होते हैं और उनको नोलेज नहीं होता कि इस समय घड़ी कौन सी है। मैं भी बावला था, मैं कोई सयाना आदमी नहीं हूं। मैं जब भी पोलिटिक्स में आया, मैं यूं सोचा करता था कि रामकुमार

गौतम तू तो इस स्टेट का मुख्यमंत्री बनेगा और तू फलाने को ओ०एस०डी० लगाइए। मैं सिसक-सिसक कर छटी बार एम०एल०ए० बना हूँ। 5 साल जिंदगी के मैंने सुबह से लेकर रात तक गांव में छोड़ दिए। किसी भाई के दिमाग में गलतफहमी हो कि आने वाला समय कभी भी इनका होगा तो यह कल्पना के बाहर की बात है। ये जो लोग आते थे इनकी सैटिंग का फार्मूला था, चौधरी भजनलाल के बीच में और चौटाला के बीच में, That time is over. जब इनके नारे चलते थे। ( गोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** इससे कुटीर उद्योगों को कोई सैट बैंक पहुंचा है क्या ?

**श्री रामकुमार गौतम :** अध्यक्ष महोदय, कुटीर उद्योग का नाम लेना भी इन भाइयों के महकमे के लिए माड़ा है। ये तो कुटीर उद्योग को उजाड़ने वाले महकमें हैं। कुटीर उद्योग का इनके महकमे से क्या काम है। जो सैटिंग का समय था that time is over अब इस समय इनको नोलेज नहीं है कि इनका जो मेन नारा था, जो जातवाद का नारा था, भोले-भाले किसानों को बहकाते थे वह खत्म हो चुका है। Now, Sh. Bhupinder Singh Hooda is the Chief Minister of the State. इनको पता होना चाहिए कि कई जिलों में तो इनका बीज ही मर लिया। They are no more in those districts. लेकिन कुछ रूझान हमारी तरफ भी हुआ है, अब ये जिस बात पर लग रहे हैं, उसमें कुछ नहीं निकलना। बैकवर्ड और हरिजन सम्मेलन करते हैं जो इनके नाम

के साथ अच्छा नहीं लगता। इसके अतिरिक्त व्यापारी सम्मेलन करते हैं और लोगों को कहते हैं कि बी०जे०पी० से समझौता करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आप ही बतायें एक बार जो आदमी दोस्ती में गण्डासा मरवाता है क्या वह दोबारा गण्डासा खायेगा। ये मेरे भोले-भाले साथी जो उनके पीछे लगे हैं इनको पाला बदल लेना चाहिए, नहीं तो ये भी मारे जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, आगे मुझे दोबारा समय दिया जाये मैं एजूके इन के बारे में कुछ बातें करना चाहूंगा।

**श्री नरे । कुमार प्रधान (बादली) :** अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी इन्दौरा जी ने अभी एक बात रखी कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि मोची का बेटा मोची का काम करे, लुहार का बेटा लुहार का काम करे और बढ़ई का बेटा बढ़ई का काम करे। अध्यक्ष महोदय माननीय साथी इन्दौरा जी को डॉक्टर कहा जाता है लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि माननीय साथी आदमियों के डॉक्टर हैं या पशुओं के डॉक्टर हैं। क्योंकि जो बात इन्होंने कही है यह बात बिल्कुल सरकार की व्यवस्था के खिलाफ है। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी की नीतियां उदार हैं और स्वयं हमारे मुख्यमंत्री जी दरियादिल हैं। ये प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं कि चाहे लुहार का बेटा हो, चाहे कारपेंटर का बेटा हो यानि किसी भी गरीब भाई का बेटा हो वह



इंजीनियर बनें, पायलैट बने, डॉक्टर बने या कोई बड़ा नेता बने। लेकिन इन भाइयों की सोच अनपढ़ों जैसी है मुझे समझ नहीं आ रहा इनको डॉक्टर किस आधार पर कहा जाता है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मेरे साथी इन्दौरा जी ने एस0ई0जैड0 के बारे में जिक्र किया कि बेतकीमती जमीन पर एस0ई0जैड0 सरकार लगा रही है और जहां एस0ई0जैड0 लग रहा है वहां देता के लोग क्या करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को अवगत करवाना चाहता हूं कि एस0ई0जैड0 की स्थापना मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी होने जा रही है। वहां की जो जमीन है उसमें खारा पानी है। उसको डहर की जमीन बोला जाता था जहां पर कभी बाढ़ का पानी आता था लेकिन जमीन के नीचे का पानी जहर की तरह है जिसको यदि कोई पक्षी पी ले तो वह पांच मिनट के अंदर-अंदर मर जाता है। इस तरह वह जमीन बेकार थी वहां पर कोई फसल नहीं होती थी। अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी की सरकार के समय में भी उस जमीन को एक्वायर करने के लिए दफा-4 के नोटिस दिए गए थे और मुआवजा 2.60 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाना था। इस बारे में मैंने रिकॉर्ड भी दिखलाया था। अध्यक्ष महोदय, हमारी चार एकड़ जमीन थी और जब इनके द्वारा वह जमीन एक्वायर की जानी थी जब हमने सोचा कि हम तो लुट गये, बरबाद हो गये। लेकिन परमात्मा ने मेहरबानी की और तीन महीने बाद चुनाव हो गये तथा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद उसी जमीन के 22 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पैसे दिए गए

हैं। जो पैसा हमें अपनी चार एकड़ जमीन का मिला है उस पैसे से हमने बाहर जाकर कुछ जमीन भी खरीद ली है, मकान भी अच्छे बना लिए हैं और छोटा-मोटा काम धन्धा भी भुरू कर लिया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने कुटीर उद्योग की भी बात उठाई है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि जहां पर एस0ई0जैड0 बनेगा वहां पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनेंगी तो उनमें कारपेंटर कहीं से उठाकर नहीं लाई जायेंगी, वहीं बनेंगी। जब वहां बिल्डिंग भी बनेगी तो उनमें कारपेंटर को, मिस्त्री को यानि सभी मजदूर भाइयों को रोजगार मिलेगा और जंगले लगाये जायेंगे, पर्दे लगाए जायेंगे, इनके अतिरिक्त होगा उसमें कम से कम 25 प्रति 100 रोजगार लोकल श्रमिकों को मिलेगा। लेकिन 2.60 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने वाले लोग एस0ई0जैड0 की बुराई कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश में कहीं भी कैंसीनों या जुआघर नहीं खोलने जा रहे हैं। प्रदेश में जो भी नई योजना आती है या जो भी नये उद्योग आते हैं उनमें हमारे मुख्यमंत्री जी गरीब और मजदूर भाइयों के हितों का विशेष ध्यान रखते हैं। यह जो 11 हजार सफाई कर्मचारी लगाने का फैसला सरकार ने लिया है यह ग्रामीण रोजगार योजना में शामिल है जो कि एक ऐतिहासिक काम है। यह भी मैं माननीय सदन और सभी सदस्यों को बताना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं माननीय सदन के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूँ कि जब तीन साल पहले श्री ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी तो उन्होंने जोहाराबाग, झज्जर में भाषण देते हुए

कहा था कि मैं आने वाली 31 तारीख से पहले इतनी बिजली दे दूंगा कि तुम बिजली बंद करना चाहोगे तो भी वह बंद नहीं होगी। यह तो पता नहीं चल पाया कि वे इतनी बिजली कहां से लाते कि बिजली बंद नहीं होगी। इतनी बिजली देने का वायदा वे उस समय बड़े जोर जोर से कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि एक बार वोट देकर हमारी सरकार बनवा दो तो हरेक गांव में हम नोट छापने की मशीन भिजवा देंगे। कुछ बड़े-बड़े गांवों के लोग भी यह बात सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारा तो बहुत बड़ा गांव है एक मशीन में तो पता नहीं हमारा नंबर पड़ेगा या नहीं। इस पर उन्होंने कहा कि ज्यादा बड़े गांव वालों को 2-3 नोट छापने की मशीनें दे देंगे। उन्होंने कहा कि आप चिंता न करें आप सिर्फ हमें वोट दे दें। स्पीकर सर, ऐसे-ऐसे लोग जनता की आंखों में धूल झोंककर विधान सभा में आ जाते हैं। इस पर मुझे एक मिसाल याद आ रही है कि एक बार कहीं पर झूठे लोगों की एक बहुत बड़ी सभा इकट्ठी हो रही थी। उसमें कई बड़े-बड़े ईनाम रखे गये और यह ऐलान किया गया कि सबसे बड़ा झूठ बोलने वाले को पहला ईनाम दिया जायेगा। वहां पर इकट्ठे हुए लोगों ने झूठ बोलना शुरू किया। उस दौरान किसी ने एक व्यक्ति से पूछा कि क्या बात आज इतने लेट कैसे हो गये तो उसने कहा कि हमारे यहां बहुत ज्यादा काम है। काम के बारे में पूछने पर उसने बताया कि हमारे यहां इतनी बड़ी खोर (पुआओं को चारा डालने का स्थान) है कि वहां पर सारे देश के पुआए एक साथ इकट्ठे चारा खा सकते हैं। इस पर दूसरे व्यक्ति ने कहा कि

हमारे यहां पर एक ऐसा बांस है जिससे जब हमारा दिल करता है तो राम जी (बादल) में सुराख करके बरसात करवा देते हैं। इस पर पहले व्यक्ति ने पूछा कि आप उस बांस को रखते कहां पर हो तो उसने कहा कि हम उस बांस को तुम्हारी वाली खोर में रखते हैं। स्पीकर सर, ऐसे ही ये लोग हैं। इनका नहीं पता कि ये कब और कहां किसी खोर में अपना बांस रखकर खड़े हो जायें। इस बारे में इतना कोई जवाब नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिन्द।

**श्री रमे । कुमार गुप्ता (थानेसर) :** स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया सबसे पहले तो मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। स्पीकर सर, माननीय सदस्य डॉ० सु गील इन्दौरा ने यह प्रस्ताव लाकर जो कुटीर एवं लघु उद्योगों के सम्बन्ध में अपनी चिंता जताई है इसका सरकार की लघु एवं कुटीर उद्योगों के प्रति उतरवादी दृष्टिकोण एवं कल्याणकारी नीतियों के कारण कोई औचित्य नहीं है। इसके साथ ही सरकार की तरफ से ऐसी कोई रोक नहीं लगाई गई है जिससे कि किसी को कुटीर एवं लघु उद्योगों की स्थापन एवं संचालन में कोई परेशानी हो। लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन के युग में जब सारा संसार प्रगति कइ नई ऊंचाइयां छू रहा है तो अधिकतर छोटे उद्योग पुराने होने के कारण इस समय वायबल नहीं रह गए हैं। इसी प्रकार से जैसे पानीपत में पहले खड्डियों पर काम होता था

लेकिन धीरे-धीरे उनकी वायबिलिटी खत्म हो गई तो उनकी जगह पावरलूम्स ने ले ली है। इससे रोजगार पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ा हो ऐसी बात भी नहीं है बल्कि इसके उलटे इस उद्योग के तहत पानीपत में रोजगार के अवसर कई गुणा बढ़े हैं और ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। इसी प्रकार से और भी कार्य हैं जैसे कि एस0ई0जैड0 की स्थापना का प्रस्ताव है ये भी रोजगार से संबंधित है। इससे भी रोजगार के असंख्य अवसरों का सृजन होगा। इस बारे में हमारे अनेक माननीय सदस्यों ने विस्तार से चर्चा की है। इससे हरेक प्रकार के लोगों जैसे कारपेंटर और लुहार सभी को काम मिलेगा। इसी प्रकार से सरकार ने अनेक ग्रामीण उद्योगों के लिए कल्याणकारी निर्णय लिये हैं। जैसे जो डेयरीज हैं उनको उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। इससे भी हमारे किसान भाई डेयरी का काम करके मुनाफा कमा रहे हैं। इसी प्रकार से हथकरघा उद्योग है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के और भी उद्योग हैं। इससे स्पष्ट है कि सरकार की ऐसी कोई मं ता नहीं है कि कोई लघु एवं कुटीर उद्योगों के माध्यम से अपना रोजगार न कर सके। लेकिन जहां तक ये जो कुछ उद्योगों की वायबिलिटी खत्म हो जाती है इस बात का संबंध है तो इसके लिए भी सरकारी दि ानिर्दे ां पर बैंक्स द्वारा सस्ती ब्याज दरों पर इच्छुक लोगों को लोन दिये जा रहे हैं ताकि लोग अपने उद्योगों का मार्डनाईजे ान कर सकें और प्रदे ा में उद्योगों को भरपूर प्रोत्साहन और बढ़ावा मिले। रोजगार के प्रति सरकार पूरी तरह से चिन्तित है ताकि हरियाणा प्रगति करे यह सरकार की मं ता है।

इस प्रकार से माननीय सदस्य द्वारा यह जो गैर सरकारी प्रस्ताव लाया गया है यह पूर्णतया औचित्यहीन है। इसके साथ ही स्पीकर सर, बोलने का समय देने के लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ।

**डॉ० िव भांकर भारद्वाज :** स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से इस बारे में कुछ सुझाव देना चाहूंगा। स्पीकर सर, इसमें ऐसा था कि जिन चीजों पर कुटीर उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए ध्यान देना चाहिए वे तीन-चार चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में माननीय सदस्य को बतना चाहिए था लेकिन वे सुझाव उन्होंने नहीं दिए इसलिए ये सुझाव उनकी तरफ से मैं दे देता हूँ। स्पीकर सर, सबसे पहले आज कुटीर और लघु उद्योगों को मॉडर्नाईज करने की जरूरत है।

**श्री अध्यक्ष :** देखिए डॉ० साहब आप इस विषय पर विस्तार से बोल चुके हैं फिर भी अगर आपके पास और कोई वैल्युएबल सुझाव हैं तो उनके बारे में आप लिखकर भिजवा दें उन पर विचार कर लिया जायेगा।

**श्री सुखबीर सिंह (रोहट) :** अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इन्दौरा जी ने जो कुटीर उद्योगों के बारे में विचार रखें हैं वे तो ठीक है लेकिन इनके विचारों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि हरियाणा की जनता ने इनको नकार दिया है। इनके 10 एम०एल०ए० भी नहीं

आये केवल 9 ही विधायक आये हैं। इनको तो वैसे ही भार्म आनी चाहिए। ये तो बेचारे चौटाला जी के पास अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं। हरियाणा में पहली बार ऐसी सरकार बनी है जिसने हर क्षेत्र में काम किया है। आज विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। आज फील्ड में जब पूछा जाता है कि किस पार्टी की लहर है तो जनता एक ही जवाब देती है कि किसी पार्टी की लहर नहीं है। यह पहली बार हुआ है कि एक पार्टी तीन साल से सत्ता में है और उसके बावजूद फील्ड में किसी पार्टी की लहर नहीं है। इससे पहले जितनी भी सरकारें आई 6 महीने के बाद ही दूसरी पार्टी की लहर भुरू हो जाती थी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने सड़कों का, बिजली का, पानी का और उद्योग बढ़ाने के लिए बहुत काम किये हैं। शिक्षा के बारे में तो इन्दौरा जी जानते ही नहीं हैं। आज हमारी सरकार ने बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिये हैं जिससे हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ता। बी0एड0 के लिए बहुत सारे कॉलेजों को मान्यता दे दी है। पहले हमारे बच्चों को इंजीनियरिंग और बी0एड0 की पढ़ाई करने के लिए महाराष्ट्र जाना पड़ता था और हमारा पैसा वहां पर जाता था। पिछली सरकार में भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ था। पटवारी से जमीन की फर्द लेने के लिए भी 100-200 रुपये देने पड़ते थे। नौकरियों में तो रिक्त और ज्यादा चलती थी। मास्टर लगाने के लिए डेढ़ लाख रुपये, सिपाही के 80 हजार रुपये और तहसीलदार के 5 लाख रुपये तक लिये जाते थे। भ्रष्टाचार और भयमुक्त प्रशासन का जो नारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने

दिया था वह आज उस नारे पर खरी उतरती है। उनकी करनी और कथनी में कोई अन्तर नहीं है। मैं विधायक तो एन0सी0पी0 से बना हूँ लेकिन दिल ऐसा करता है कि कांग्रेस का विधायक होना चाहिए था। सभी मंत्री बहुत ही मन लगा कर काम करते हैं। चौटाला जी का सिंगापुर में 1200 करोड़ रुपये का होटल है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़े जमींदार हो गये हैं। सिरसा में ऐसी क्या पैदावार है कि चौटाला जी इतने धनवान हो गये ? हरियाणा के दूसरे एरिया जैसे कि अम्बाला, करनाल, सोनीपत तथा पानीपत आदि तो सिरसा से कहीं आगे हैं, वहां पैदावार भी अच्छी होती है। जब हमारे पास ही इतना पैसा नहीं है कि हम दस हजार रुपये की दुकान खरीद सकें तो चौटाला के पास इतना पैसा कहां से आ गया कि उसने 1200 करोड़ रुपये का होटल बना लिया तथा ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा जमींदार बन गया ? उन्होंने जनता की राजनीति नहीं की बल्कि अपने पेट की राजनीति की है। लेकिन आज की सरकार जनता की राजनीति करती है। सारा पैसा जनता के लिए स्कूलों में, बी0एड0 कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजों के निर्माण पर लगाया जा रहा है जिससे लोग शिक्षित हो रहे हैं और रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। गरीब लोगों के लिए वजीफे का प्रावधान किया गया है। गरीबों के लिए भजन लाल और चौटाला ने कुछ काम नहीं किया। भजन लाल ने गरीबों के नाम से अपना पेट भरा है और चौटाला ने किसानों के नाम से अपना पेट भरा है। उन्होंने पैसे की इतनी बड़ी कीमत बना दी कि भाई को भाई मार देता है। चौटाला और भजन लाल के कारण आज भाई को भाई



मार रहा है इसलिए इनको कुटीर उद्योगों की बात नहीं करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात अव य ही कहना चाहूंगा, आज सेज का बहुत महत्व है। सेज के कारण ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रान्ति आई थी। लेकिन एन0सी0आर0 में जो जमीन सेज में एक्वायर की जाती है उसके रेट 75 लाख रुपये हैं हमारे यहां रेट कम हैं उसको और बढ़ाया जाना चाहिए। वह साथ लगती जमीन है उसका मुआविजा जरूर बढ़ाया जाए इसके लिए लोगों को आ ा रहेगी और लोगों को इससे बहुत खु ि होगी। वे लोग आगे अपना रोजगार भी कर लेंगे जिससे औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा और कुटीर उद्योग भी बढ़ेंगे। स्पीकर सर, आज दिल्ली में जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी बनी है। जब यह यूनिवर्सिटी महरौली में बनी थी तो यह ऐरिया वहां का बाहर कर ऐरिया था। वहां पर लोगों को कोई आमदनी नहीं थी और लोग भूखे मरते थे। कोई भी व्यक्ति महरौली ऐरिया में रि ता करने के लिए नहीं जाता था लेकिन आज महरौली ऐरिया की बहुत बड़ी कीमत है क्योंकि अब वहा पर यूनिवर्सिटी बन गई है। अब हरियाणा में भी यूनिवर्सिटी बन रही हैं और एस0ई0जैड0 भी बन रहे हैं। आगे इनसे सारी जनता को फायदा होगा। हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार का समर्थन करते हैं क्योंकि जितने विकास कार्य इस सरकार ने किये हैं उतने विकास कार्य पिछले चालीस साल की सरकारों के वक्त में भी नहीं हुए थे। लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी सड़कें, पुल और नहरें बनेंगी, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनेंगी। मेरे कहने का

मतलब यह है कि आज हर क्षेत्र में विकास हुआ है और इस सरकार को छत्तीस जाति का समर्थन प्राप्त है। आज प्रदेश में भयमुक्त भासन है जहां पर बहू-बेटी सुरक्षित हैं। कभी भी कहीं पर भी जाए रात के 12 बजे भी व्यक्ति अपनी नौकरी करके घर जाता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। स्पीकर सर, पिछले राज के दौरान तो चारों तरफ बदमाशों का बोल-बाला था। हमारे यहां एक कृष्ण बदमाश था वह आज कहां। चौटाला साहब और चौटाला साहब के लड़के उसके परममित्र थे और वे जेल में जाकर उसको मिलते थे। वह सारा अनपढ़ टोला था (विघ्न) अब पता नहीं वह कहां पर गादड़ बना छिपा बैठा है। (विघ्न) हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में बैठा हो। उस समय तो रोजाना गोलियां चला करती थी जिसके कारण हमारा हरियाणा प्रदेश सारे हिन्दुस्तान में बदनाम हो गया था। उस समय बदमाशों के जरिये, लूट-खसोट के जरिये पैसा बनाया जाता था। जब दिल्ली में जाते थे तो वहां पर हरियाणा के लोगों से दिल्ली के लोग डरते थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि दिल्ली में भी हमारे हरियाणा प्रदेश की मार्किट गिरी हुई थी। आज सेंटर से हमारी सरकार को इतनी ग्रांट मिल रही हैं कि सारे प्रदेश में विकास के कार्य हो रहे हैं। जो भी कार्य हो रहे हैं वहां पर बहुत अच्छी क्वालिटी का मैटीरियल लग रहा है जब कि चौटाला साहब की सरकार के राज के समय में जो भी सड़क बनी वह साथ ही साथ टूट भी गई। उस समय जो भी मैटीरियल लगता था उसकी क्वालिटी घटिया होती थी। मैटीरियल कम ही लगता था और उन लोगों की जेबें

ज्यादा भरी जाती थीं। उस समय काम की गुणवत्ता नहीं देखी जाती थी बल्कि यह देखा जाता था कि मुख्यमंत्री की कितनी इनकम होगी और मंत्रियों की कितनी इनकम होगी। उनका कोई भी एम०एल०ए० उनके पास किसी काम के लिए नहीं जाता था और अगर किसी काम के लिए जाता भी था तो कहता था कि बदली के लिए जा रहा हूं, नौकरी के लिए जा रहा हूं। जब वे उससे पूछते कि कहो कैसे आए तो एम०एल०ए० कहता था कि बस आपके द नि करने आया हूं और उसकी हालत यह होती थी वह काम के लिए भी नहीं कह पाते थे। उनके एम०एल०ए० इतने काबिल भी नहीं हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, एस०ई०जैड० और लघु एवं कुटीर उद्योग एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब बड़े उद्योग लगेंगे तो उनके साथ लघु और कुटीर उद्योग भी पनपेंगे। यह सरकार इसके लिए सुविधाएं दे रही है जिसक हम समर्थन करते हैं। बाकी चौटाला साहब का जो बैंडबाजा उठा रहे हैं ये साथी इसको छोड़ दें और जैसे गौतम जी कह रहे थे कि उनके वाली पार्टी में शामिल हो जाएं या फिर हुड्डा साहब वाली पार्टी में आ जाएं। स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसे लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री तेजेंद्रपाल सिंह मान (पाई) :** स्पीकर साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। स्पीकर सर, अभी थोड़ी देर पहले डॉ० इन्दौरा साहब ने कुटीर उद्योगों पर एक बहुत बड़ी भूमिका बनाई कि किस तरह से देहात के अन्दर पारम्परिक लघु उद्योग चलते थे

लेकिन वे उद्योग नहीं थे। उस वक्त जो समय था उस समय के अनुसार लोगों का सोल स्ट्रक्चर ऐसा था कि गांव से बाहर जाने के लिए बड़ी असुविधा थी। गांव के अन्दर की जरूरत की चीज तैयार होती थी और गांव के अन्दर ही प्राप्त हो जाती थी। हमारे सारे इलाकों के अन्दर बैकवर्डनेस होती थी। स्पीकर सर, समय के साथ परिवर्तन आया है। जहां पहले एक ठठेरा काम करता था वहां अब वैल्विंग सैट्स आए हैं, लेथ्स आई हैं और गांवों के अन्दर भी इस तरह की चीजें हुई हैं जिसके कारण गांवों में भी तरक्की हुई है। हरिजनों का पलायन तो हुआ ही हुआ लेकिन इसके साथ ही साथ गांवों में जो छोटे-छोटे दस्तकार थे वे भी भय के कारण शहरों में आ गये। किसी ने टंकिया बनाना शुरू की तो किसी ने कुछ और काम करना शुरू किया। किसी ने एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स की रिपेयर का काम शुरू किया लेकिन उनकी अपनी कुछ समस्याएं हैं। जो आदमी हैवी इण्डस्ट्रीज लगाएगा उसको एनसिलरीज की भी जरूरत पड़ेगी उनके साथ ही साथ एनसिलरीज की मदद के लिए हर बाहर में, हर उस कॉर्नर में जहां पर बड़े उद्योग लगे हैं छोटे-छोटे ऐसे यूनिट्स भी हैं जो पार्ट्स बना रहे हैं या छोटे-छोटे काम कर रहे हैं। कोई टर्नर का काम करता है तो उसने एक ही मशीन लगा रखी है और वह बुनियादी बनाए जा रहा है या कोई और चीज ही बनाए जा रहा है। इन लोगों की समस्या है कि समय के साथ-साथ डीजल की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि आज से पांच साल पहले तक डीजल इंजन जिसे जनरेटर सैट कहते हैं से बिजली का प्रयोग

किया जाता था। इसके द्वारा बनाई गई बिजली का दाम और सरकारी बिजली बोर्ड से प्राप्त की जाने वाली बिजली के दाम लगभग एक से होते थे। डीजल के दाम बढ़ने की वजह से उसकी वर्किंग इकनॉमी फेल हो गई जिसकी वजह से वह एक या डेढ़ मैगावाट की टरबाईन नहीं लगा सकता है वह पूरी तरह से सरकार द्वारा बनाई जाने वाली बिजली पर डिपेंडेंट हो गया। इतिहास से आज बिजली की कमी है और इण्डस्ट्रीज भी आज बिजली की कमी को झेल रही है। आज जो बड़े-बड़े ग्रुप हैं उनकी तो अपनी पावर जनरेशन है और उनको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो छोटे उद्योग हैं, छोटी इकाईयां हैं और स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज हैं उनमें प्रदेश भर में बहुत भारी समस्या है। उन सभी की वॉयबलीटी बहुत कम है, इस बारे में मैं सुझाव देना चाहता हूँ। स्पीकर सर, स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज के फाईनान्सियल लिमिट 50 लाख रुपये हैं उसको आज के समय में बढ़ा देना चाहिए। स्पीकर सर, जो चीज आज से पहले 1 लाख रुपये की थी वह बढ़कर 5 लाख रुपये और 5 लाख से बढ़कर 10 लाख रुपये हो गई है। गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया को इन्कीज करती रही है and probably today it is at 50 lacs per unit. It needs to be increased at least double the amount because an industry or the size whatever was setup in 10 years ago, now takes 10 times more money to be installed. उसकी वजह से अनलैस वे छोटी-छोटी सुविधाएं स्माल स्केल इण्डस्ट्री को गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने प्रदान कर रखी हैं। उसमें एक ब्रैकेट आ जाता है जो थोड़ा सा बढ़ने की

वजह से वह सुविधाएं जरूरतमंदों को प्रदान नहीं हो पाती हैं। आज एक गांव में एक लुहार ने वैल्डर सैट लगाया हुआ है और वह 12-12 घंटे बिजली के आने का इन्तजार करता रहता है कि कब बिजली आए तो मैं एक टांका लगाऊं। यह जो ग्रामीण इण्डस्ट्रीज हैं, छोटे दस्तकार और वैल्डर्ज हैं वे छोटी-छोटी दुकानें लगाकार गांवों में बैठे हुए हैं उनकी छोटी-छोटी बहुत सी समस्याएं हैं। उसमें एक घर के दो-दो और तीन-तीन आदमी काम करते हैं। उनकी तरफ मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह जो इन्दौरा जी गैर सरकारी संकल्प लेकर आए हैं इसमें कोई दम नहीं है क्योंकि आज समय के साथ इन सभी चीजों में परिवर्तन हो गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज में बड़ी-बड़ी चीजें बनती हैं और यहां तक कि उसमें पंखों के और कम्प्यूटर के पार्ट्स भी बनते हैं। अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद में एस्कॉर्ट कम्पनी बड़ी होती थी अब तो मध्यम हो गयी है। सर, देहातों के लोग एस्कॉर्ट के लिए काम करते थे उसके लिए पूर्ण बनाने का काम करते थे। मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यह जो एस0सीज0 को 100 गज के प्लाट देने की स्कीम बनाई है, उसी तरह से मुख्यमंत्री जी की योजना भी है कि गांवों में हुडा की तर्ज पर ग्रामीण हाऊसिंग एस्टेट बनाएंगे। इसी तरह से उन लोगों को भी इस तरह से कोई जगह देने का प्रावधान करें ताकि वे उद्योग आज जो गांवों से पलायन कर रहे हैं और वापिस आना चाहते हैं वे वापिस अपने गांवों में चले जाएं। सरकार को ऐसा कुछ करना

चाहिए कि उनके डोमैस्टिक खर्च कम हो जाएं और वे वहीं पर अपने उद्योग लगा सकें। अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा प्रावधान यह सरकार करेगी तो उन श्रमिकों के लिए, गरीब आदमियों के लिए बहुत अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :** अध्यक्ष महोदय, छोटे और कुटीर उद्योग हैं उनकी चिन्ता को लेकर एक गैर सरकारी संकल्प माननीय इन्दौरा जी इस सदन में लेकर आए हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां इनकी चिन्ता है, वह वाजिब है। मुझे और खुशी होती, सरकार को और खुशी होती अगर रचनात्मा सुझाव, नीतिगत सुझाव जो सही मायनों में हमारे ग्रामीण उद्योग में लगे व्यक्ति हैं, हथकरघा उद्योग में लगे व्यक्ति हैं, लघु उद्योग में लगे व्यक्ति हैं उनका किस प्रकार से भला हो, के बारे में आते हैं। स्पीकर साहब, इनके भले की और क्या-क्या योजना आ सकती है, इसके बारे में माननीय सदस्य अगर सुझाव देते तो बहुत अच्छा रहता। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के प्रावधान मैम्बर्ज-डे पर, प्राइवेट मैम्बर्ज रैजोल्यूशन लाने की जो परम्परा आपने दोबारा से शुरू की है इसका लक्ष्य कई बार ऐसे मुद्दे जो प्रदेश और देश की जानकारी से जुड़े हैं, जो ज्वलन्त हैं, उन पर परिचर्चा करना है। इसमें राजनीतिक विरोध की सीमाएं मिट जानी चाहिए, हमें इन मुद्दों पर चर्चा करते वक्त यह भूल जाना चाहिए कि हम सदन में किस तरफ बैठे हैं। इन पर सुझाव यह आना चाहिए कि किस प्रकार से वर्ग विशेष की जो दिक्कतें हैं उनकी जो समस्याएं हैं

उनका हल हम कैसे निकाल सकते हैं ? अध्यक्ष महोदय, Before I proceed मैं कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जी ने यह कहा कि यह दे 1 गांव में रहता है, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने यह कहा कि रोजगार सृजनात्मक उद्योग ही दे 1 की तरक्की का आधार बन सकता है, इंदिरा गांधी जी ने यह कहा था कि बैंकों में राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य गरीब व कूचले वर्गों को सही मायनों में इस दे 1 का मालिक बनाना है। अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी जी ने यह कहा था कि ग्रामीण विकास व गांव के गरीब का उत्थान छोटी इकाईयां एवं कुटीर उद्योग व रिक्लड डिवैल्पमेंट ही बेरोजगारी उन्मूलन का असली रास्ता और मूलमंत्र है। अध्यक्ष महोदय, कॉटेज इण्डस्ट्रीज या कुटीर उद्योग की परिभाषा के बारे में Oxford English Dictionary says that “a Cottage Industry is a small business or manufacturing activity carried on a people’s home.” अध्यक्ष महोदय खादी और विलेज इण्डस्ट्रीज कमी 1न ने कॉटेज इण्डस्ट्रीज की व्याख्या करने का प्रयास किया। स्पीकर सर, हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, हम किस परिधि के अन्दर बात कर रहे हैं वह भी जानना जरूरी है, I quote Sir, the Khadi and Village Industry Commissioner Government of India. Being labour intention. Cottage Industry creates employment of opportunities on a substantial scale for the people of rural area particularly for women. It also provides supplementary employments to persons below poverty line at their door-steps. Since, the manufacturing processes are light and simple the Endicapped and old people can also get employment. Those cottage industries has been creating socio-economic



significance in bringing livelihood to the people thereby preventing migration of villages to urban areas. यह भी एक लक्ष्य छोटे और कुटीर उद्योगों का है। अध्यक्ष महोदय, इस सारी बात को पहचानकर हरियाणा खादी और विलेज इण्डस्ट्रीज बोर्ड जो है उसके माध्यम से हम रूरल इम्प्लायमेंट जैनरे इन प्रोग्राम चलाते हैं। जो आर0ई0जी0पी0 है। इसके दो लक्ष्य हैं। अगर दस लाख रुपये तक का लोन है तो मार्जिन मनी के तौर पर 25 परसेंट पैसा खादी और विलेज इण्डस्ट्रीज बोर्ड देगा और यदि 25 लाख रुपये तक का लोन है तो दस परसेंट पैसा मार्जिन मनी के तौर पर खादी और विलेज इण्डस्ट्रीज बोर्ड देगा। मैं आपका और पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि खादी और विलेज इण्डस्ट्रीज बोर्ड हरियाणा की क्या डिवैल्पमेंट रही है किस प्रकार से रोजगार उत्पत्न किया क्योंकि यह भी इस परिचर्चा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि मार्च, 2005 से फरवरी, 2008 तक मौजूदा सरकार के समय में 1869 केसिज हरियाणा खादी और इण्डस्ट्रीज बोर्ड ने क्लीयर किए और इसके माध्यम से हमने 13618 लाख 79 हजार या अध्यक्ष महोदय मैं यह कहूं कि 136 करोड़ 18 लाख 79 हजार की राशि 3 साल के अन्दर हमने वितरित की है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हरियाणा खादी एवं विलेज इण्डस्ट्रीज बोर्ड की स्कीम के तहत रूरल इम्प्लायमेंट स्कीम जो है इससे पचास हजार चार लोगों को पिछले तीन वर्षों के कार्यकाल में हम रोजगार दे पाए हैं। 31 करोड़ 80 लाख 86 हजार रुपये की मार्जिन मनी जो कि सरकार का हिस्सा था, वह भी इन

इकाइयों को दी है जो कि इनके माध्यम से लगाई गई थीं। हरियाणा के गठन के बाद यह अपने आप में एक रिकार्ड भी है। सदन को यह बताते हुए मुझे हर्ष भी हो रहा है और प्रसन्नता भी हो रही है। अध्यक्ष महादय, यदि आप अनुमति दें तो मैं पिछले पांच वर्षों के आंकड़े भी रिकार्ड पर लाना चाहूंगा कि किस प्रकार से खादी और कृटीर उद्योग ने किस प्रकार से हरियाणा खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड ने हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में तरक्की की है। जब हमें सरकार मिली तब क्या स्थिति थी और इनको बढ़ावा देने में, इनको प्रमोट करने में, इनके उत्थान में और इनको आगे ले जाने में सरकार ने क्या प्रयास किए हैं। इस बारे में मैं साल 2000-2001 से फरवरी, 2005 तक के आंकड़े बताना चाहूंगा। 1538 केस पांच साल की अवधि में क्लीयर किए गए। हमने 3 साल में 1869 केस क्लीयर किए हैं और इन केसिज में पिछले पांच वर्षों के इनके भासनकाल में जो राशि दी गई वह कुल 94 करोड़ 79 लाख 92 हजार रुपये की राशि दी गई और इसके विपरीत हमारे तीन साल के कार्यकाल के दौरान इस सरकार ने 136 करोड़, 18 लाख 79 हजार रुपये दिये। ये साथी पांच साल के भासनकाल में 19205 लोगों को रोजगार दिलवा पाए जबकि हमने 50004 लोगों को रोजगार दिया है। मार्जिन मनी पिछले पांच वर्षों में 2001 से फरवरी, 2005 तक 18 करोड़ 67 लाख थी और हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने तीन साल के अंदर ही दुगने के करीब 31 करोड़ 80 लाख 86 हजार रुपये की राशि दी है। जो चौधरी भूपेंद्र सिंह

हुड्डा जी की सरकार है उनकी छोटे-छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के बारे में नीति क्या है, नीयत क्या है, लक्ष्य क्या है, रास्ता क्या है, मूलमंत्र क्या है यह जीते जागते आंकड़े उसका ज्वलंत प्रमाण हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो ग्रामीण रोजगार है और उससे जो जुड़ी समस्याएं हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना के माध्यम से गांवों में रोजगार उत्पन्न किया जाता है। जिसमें छोटे-छोटे उद्योग जैसे कोई दुकान है या कोई ऐसे व्यवसाय हैं उनके द्वारा हमारे गांव के बच्चों को और गरीब लोगों को रोजगार मिले इसके लिए हम उन बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। इस योजना के तहत 12500 रुपये की सब्सिडी की राशि भी दी जाती है। हर एक क्षेत्र में ट्रेनिंग का प्रावधान भी इसके अंदर है। हम ट्रेनिंग भी करवाते हैं ताकि गांव के गरीब और नौजवान साथी और छोटे-छोटे दुकानदार जो छोटा-मोटा धंधा करें उसमें वे स्किल डिवैल्पमेंट भी कर सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस सदन को बताना चाहूंगा कि तीन वर्ष में भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के कार्यकाल में 2005-06 से 2007-08 तक 31491 लोगों को ग्रामीण रोजगार के मामले में नौजवानों को और गरीब आदमियों को इस स्कीम के माध्यम से मदद दी गई है। इसमें हमने 177 करोड़ 98 लाख 81 हजार रुपये की राशि दी है। जिसमें से 12500 रुपये की राशि सब्सिडी के तौर पर दी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने तीन साल में 50004 लोगों को हरियाणा खादी एवं विलेज इण्डस्ट्रीज बोर्ड द्वारा और तकरीबन 31491 लोगों को हरियाणा

खादी एवं कुटीर उद्योग के माध्यम से रोजगार दिया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 81495 लोगों को मात्र इन दो मदों में लोन देकर मदद की है और रोजगार दिया है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि हमने किस प्रकार की जियोग्राफिकल प्रोग्रेस की है। मैं आपकी अनुमति से सदन को बताना चाहूंगा कि अगर उसको आज जब पिछले पांच साल के आंकड़ों से कम्पेयर करें तो पता चलता है कि वर्ष 2000-2001 से वर्ष 2004-2005 यानि पांच साल के अन्तराल के दौरान जब कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं थी माननीय इन्दौरा साहब की पार्टी की सरकार थी उस समय 38005 केस पांच साल के अन्दर किये गये और 21 करोड़ 87 लाख रुपये की राशि दी गई। इसके विपरीत तीन साल के अन्दर हमने जो राशि दी जैसा कि मैंने आंकड़े दिए हैं यह सरकार की नीतियों का आईना है कि किस प्रकार से लगातार यह संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय यह वाजिब चिन्ता जाहिर की है कि कलैक्टर डिवैल्प किये जा रहे हैं आज कोई कहीं जूती बनाने का व्यवसाय करता है कहीं कोई छाज-छलनी का व्यवसाय करता है जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा है। आज उन्हें प्रमोट करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से मिलकर कलैक्टर डिवैल्प को इस्माईलाबाद में फाईनेंशियल मदद की है। इसी प्रकार से पटसन और केन का फर्नीचर बनाने के लिए फरुखनगर, गुड़गांव में है उनको फाईनेंशियल मदद की है। लैदर और फुट वीयर बनाने के लिए ओढी गांव जो भिवानी के पास है उनको फाईनेंशियल मदद

की है। इसी प्रकार से कढ़ाई और फ्रेम मेकिंग का कलैस्टर गांव तालू, महेंद्रगढ़ में कुछ फाईनैरिगल मदद पहुंचाई है। इसलिए सरकार को इस बात का ध्यान है। यह नहीं है कि हमने उस तरफ से ध्यान छोड़ दिया है। इसी प्रकार के दूसरे छोटे कुटीर उद्योग हैं सरकार को उनकी मदद पहुंचा रही है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार की एसिसटेंस देने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाकर हरियाणा सरकार ने भारत सरकार को भेजी है। माननीय भारद्वाज ने बड़ी खूबसूरती के भावों में कहा कि इस प्रकार के कलैस्टर भिवानी में स्किल्ड डिवैल्प हो रहे हैं जो इनके यहां लकड़ी के मनके बनाते हैं। इसी प्रकार गांव मंगाली, हिसार में भी मनके बनाये जाते हैं उनको भी हमने फाईनैरिगल मदद पहुंचाने के लिए भारत सरकार को लिखा है और वह जल्द ही मंजूर हो जाएगा। आदरणीय मान साहब ने स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज की चर्चा की। मैं इस सदन का ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहूंगा कि स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज को लेकर कई इंसैटिव हमारी सरकार ने दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, स्माल स्केल यूनिट जो बैकवर्ड एरिया में लगाये जाते हैं उनके ऊपर जो वैट का टैक्स लगता है उसकी 50 प्रतिशत राशि पांच साल तक सरकार मुफ्त लोन के तौर पर देती है। पांच साल के बाद हम वापिस लेते हैं जैसे अगर 100 रुपये वैट टैक्स देना है तो 50 रुपये की राशि दें तो पांच साल के लिए वह डैफैर्ड कर दी जाती है और इन्ट्रक्ट फ्री लोन के हिसाब से ट्रीट कर लिया जाता है और पांच साल के बाद वे वापिस कर सकते हैं ताकि जो-जो हमारे प्रान्त के अन्दर पिछड़े

क्षेत्र हैं उनके अन्दर ज्यादा से ज्यादा लघु उद्योग आ सकें। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज है जैसे कोई पापड़ बनाने का कारखाना लगाना चाहता है, कोई छोटी फैक्ट्री लगाना चाहता है या अचार बनाने के लिए कोई कुटीर उद्योग लगाना चाहता है इनके लिए 75 प्रति 100 टैक्स पांच साल तक माफ किया है और इनको इन्टरस्ट फ्री लोन ट्रीट किया जाता है तथा पांच साल वे वापिस दे दें। 88 ऐसे ब्लॉक हैं जिनके अन्दर हमने ऐसी इण्डस्ट्रीज को बैकवर्ड घोषित किया गया है और उनके माध्यम से इसी प्रकार से सुविधा दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा आपकी अनुमति से कि जो छोटे उद्योग हैं, मध्यम उद्योग हैं और बड़े उद्योग हैं किसी भी प्रांत की तरफ़ी के लिए कहीं न कहीं ये उद्योग और औद्योगिक क्रांति के नये संचार होते हैं। छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग बहुत महत्वपूर्ण हैं, दूसरे भी महत्वपूर्ण हैं अगर हम आंकड़ें देखें तो मौजूदा सरकार के अन्दर जो उद्योग लेकर आये हैं पहले मैं आपको लघु, माध्यमिक उद्योग और छोटे उद्योग उनके आंकड़े देना चाहूंगा। वर्ष 2005-2006 से लेकर वर्ष 2007-2008 यानि तीन साल के अंतराल में हरियाणा के अन्दर 4275 नए लघु उद्योग लगाए गए, इससे जो इन्वैस्टमेंट कैटेलाइज हुई, जो पैसा आया वह तकरीबन 1098 करोड़ 29 लाख रुपये है। इतना पैसा निवेश के तौर पर इन लघु उद्योगों के माध्यम से आया है। इससे 60615 लोगों को रोजगार मिला है। 50004 लोगों को हरियाणा खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के माध्यम से और 31491 लोगों

को कुटीर उद्योग बोर्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना के माध्यम से रोजगार मिला है। यानि तकरीबन डेढ़ लाख लोगों को रोजगार की संख्या यही बन जाती है। आदरणीय गौतम जी ने, आदरणीय सुखबीर सिंह फरमाणा ने, आदरणीय बतरा साहब ने, तेजेंद्रपाल सिंह मान ने, भारद्वाज जी ने और गुप्ता जी ने चर्चा की कि क्या कारण थे कि मौजूदा कांग्रेस की सरकार ने आते ही लघु उद्योग यहां यकायक लगने लगे, यकायक निवे । पैदा होने भुरु हो गए, यकायक नए रोजगारों का सृजन भुरु हो गया। पिछले सालों के आंकड़े देखें उसमें 2000-01 से लेकर 2004-05 के बीच के 5 सालों में जो लघु उद्योग हरियाणा में आए हैं उनकी संख्या मात्र 3479 थी जबकि हमारे इन तीन सालों में यह संख्या 4275 आई है। पिछली सरकार के 5 सालों में जो निवे । आया है वह है 1856 करोड़ रुपये और हमारा जो 3 साल में निवे । आया है वह है 2477 करोड़ रुपये। उनके समय में 40776 लोगों को रोजगार मिला है जबकि हमारे तीन सालों में 60615 लोगों को रोजगार मिला है तो कहीं न कहीं यह सरकार की नीति और नियति को दर्शाता है। आदरणीय इन्दौरा साहब, मुलाना जी और तेजेंद्रपाल जी ने भी चर्चा की कि किस प्रकार लघु कुटीर और छोटे उद्योगों को संरक्षण दे सकते हैं। इन्दौरा जी ने एक सुझाव दिया कि एक कमेटी बना दें जो पूरी तरह से सारी बातों को देखकर इनका संरक्षण करे। इन्दौरा जी ने एक यह भी सुझाव दिया कि लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट की व्यवस्था की जाए, लोन की व्यवस्था की जाए, उन्होंने संसाधन जुटाने पर भी बल दिया।

इन्दौरा जी ने ट्रेनिंग की बात की कि जो लोग लघु और कुटीर उद्योगों में लगे हैं उनको ट्रेनिंग कैसे दी जाए ताकि वे वाकई में प्रोफिटेबल बनें। आदरणीय तेजेंद्रपाल सिंह जी ने स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की लिमिट बढ़ाने की बात कही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को बताना चाहूंगा कि जहां हम हमें रोजगार सृजन करने की बात करते थे वहीं आजाद हिन्दुस्तान में एक और क्रांतिकारी कानून श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली सरकार लेकर आई है कि कानून द्वारा 100 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। आज से पहले किसी सरकार ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं दिखाई। नेशनल रूरल इम्प्लायमेंट गारंटी एक्ट जिसे देश के 596 जिलों में एक अप्रैल से यू0पी0ए0 की सरकार ने लागू किया है। इस प्रकार एक और कानून हमारी सरकार लेकर आई है, इन्दौरा साहब यह आपकी जानकारी के लिए भी है and it is called "The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006." यह जो 2006 का कानून है इससे माइको इंडस्ट्रीज, स्माल इंडस्ट्रीज और मीडियम इंडस्ट्रीज को कानूनी संरक्षण का अमलीजामा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने क्रेडिट की बात की, लिमिट बढ़ाने की बात की। इस कानून के माध्यम से कानून की पुस्तिका में हमें रोजगार के लिए श्रीमती सोनिया गांधी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने लिख दिया कि माइको इंडस्ट्रीज को, मीडियम इंडस्ट्रीज को, स्माल इंडस्ट्रीज को किस प्रकार से किस व्यवस्था से और किस प्रणाली से संरक्षण देंगे। I would like to draw the attention of this House to two-



three provisions of this act. अगर आप इसकी ओनपिंग पढ़ें तो इसमें स्पष्ट लिखा है :-

“an act to provide for facilitating the promotion and development and enhancing the competitiveness of micro, small and medium enterprises and for matters connected therewith or incidental thereto.

and whereas it is expedient to provide for facilitating the promotion and development and enhancing the competitiveness of micro and medium enterprises and for matters connected therewith or incidental thereto.”

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं इनके दो-तीन प्रावधानों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो बात इन लोगों ने कही है उसको पहले से ही कानून अमलीजामा पहनाया हुआ है। अगर इसकी धारा-7 की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करूं जिसमें लिखा है :-

“7. (1) Not with standing anything contained in section 11B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, the Central Government may for the purposes of this Act, by notification and having regard to the provisions of sub-sections (4) and (5), classify and class or classes of enterprises, whether proprietorship, partnership firm, company or underdaking, by whatever name called, -

(a) in the case of the enterprises engaged in the manufacture or production of goods pertaining to any industry specified in the first schedule to the

industries (Development and Regulation) Act,  
1951, at

(i) a micro enterprise, where the investment in plant and machinery does not exceed twenty five lakh rupees ;

(ii) a small enterprise, where the investment in plant and machinery is more than twenty five lakh rupees but does not exceed five crore rupees; or “

जो इन्होंने कहा है वह इसमें कवर हो गया है ।

“(iii) a medium enterprise, where the investment in plant and machinery is more than five crore rupees but does not exceed ten crore rupees.”

सर, यह हमारी सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला है ।

“(b) In case of the enterprises engaged in providing or rendering of services, as

(i) a micro enterprise, where the investment in equipment does not exceed ten lakh rupees ;

(ii) a small enterprise, where the investment in equipment is more than ten lakh rupees but does not exceed two crore rupees ; or

(iii) a medium enterprise, where the investment in equipment is more than two crore rupees but does not exceed five crore rupees.”

**बैठक का समय बढ़ाना**

**Mr. Speaker :** Is it the sense of the House that the time of the House be extended for 10 minutes ?

**Voices :** Yes Sir,

**Mr. Speaker :** The time of the House is extended for ten minutes.

### गैर-सरकारी संकल्प (पुनरारम्भ)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इनके अतिरिक्त मैं इसके स्टेचुटरी प्रोविजंस भी पढ़कर सुनाता हूँ जिसके सेक्शन-9 में लिखा है:-

“9. (1) The Central Government may, from time to time, for the purposes of facilitating the promotion and development and enhancing the competitiveness of micro, small and medium enterprises, particularly of the micro and small enterprises, by way of development of skill in the employees, management and entrepreneurs, provisioning for technological upgradation, providing marketing assistance or infrastructure facilities and cluster development of such enterprises with a view to strengthening backward and forward linkages, specify, by notification, such programmes, guidelines or instructions, as it may deem fit.”

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन्होंने क्रेडिट फैसिलिटीज के बारे में कहा है। इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि इस एक्ट के सेक्शन-10 में हमने पहले ही अमलीजामा पहना रखा है जिसको मैं पढ़कर सुना देता हूँ :-

“10 The policies and practices in respect of credit to the micro, small and medium enterprises shall be progressive and such as may be specified in the guidance or instructions issued by the Reserve Bank, from time to time, to ensure timely and smooth flow of credit to such enterprises, minimize the incidence of sickness among and enhance the competitiveness of such enterprises.”

स्पीकर सर, इसके अन्दर तीसरा प्रावधान यह है कि परचेज प्रेफ़ैस को स्टेनुटरी अमलीजामा पहली बार पहनाया गया है। इससे जो चीजें खरीदनी हैं उनको सरकार के द्वारा प्राथमिकता दी जायेगी।

“11. For facilitating promotion and development of micro and small enterprises, the Central Government or the State Government may, by order nitify from time to time, preference policies in respect of procurement of goods and servies, produced and provided by micro and small enterprises, by its Ministries or departments and the case may be, or its aided institutions and public sector enterprises.”

वह भी एड कर लिया गया है। सरकार द्वारा सभी एड कर लिये गये हैं। इनके लिए एक स्पे ाल फण्ड बनाने का भी प्रावधान किया गया है ताकि इनकी मदद की जा सके। मानवीय सदस्य ने जो बात की है मैं उसको और आगे ले जाता हूं। सर, इसमें कहा गया है कि –

“ 12. There shall be constituted, by notification, one or more Funds to be called by such name as may be specified

in the notification and there shall be credited there to any grants made by the Central Government under section-13.

13. The Central Governemnt may, after due appropriation made by parliament by law in this behalf, credit to the Fund or Funds by way of grants for the purposes of this Act, such sums of money as that Government may consider necessary to provide.”

भारत सरकार एक गारंटी देगी जिससे एक फण्ड बन जायेगा और उसस इन उद्योगों की मदद की जायेगी। सर, इसके अलावा इसी कानून के अन्दर यह प्रावधान भी होगा क्योंकि स्पीकर सर, जो ये छोटे-छोटे लघु एवं कुटीर उद्योग हैं कल को अगर उनसे कोई सप्लाई ले लें और उनको पेमेंट न दें तो वे क्या करेंगे ? भारत सरकार उस फण्ड को देगी यह इसमें स्पष्ट लिखा है कि फण्ड बनाया जायेगा और वह फण्ड इसको फिर आगे फाईनैस करेगा। इस बात को कानूनी अमलीजामा पहनाया जा रहा है। स्पीकर सर, श्रीमती सोनिया गांधी की कांग्रेस सरकार के द्वारा यह बात भी देखी गई कि अगर कोई किसी छोटे और कुटीर उद्योग के मालिक से पैसा ले और पैसा उसको वापिस न दे इस पर वह बेचारा तो अदालतों के अन्दर जायेगा और वर्षों तक निर्णय नहीं होगा इसलिए उसका भी एक नायाब प्रावधान इस कानून के अन्दर किया गया है। Speaker Sir, I would like to draw attention of this August House that in section-15, it is clearly mentioned that -

“15. Where any supplier supplies any goods or renders any services to any buyer, the buyer shall make payment therefore on or before the date agreed upon between him and the supplier in writing or, where there is no agreement in this behalf, before the appointed day :

Provided that in no case the period agreed upon between the supplier and the buyer in writing shall exceed forty five days from the day of acceptance or the day of deemed acceptance.”

स्पीकर सर, सैक 11-16 के अन्दर यह लिखा है कि अगर वह 45 दिन के आगे चला जाये तो उसे छोटे और कुटीर उद्योग को three times of the bank rate of interest देना पड़ेगा। यह भी प्रावधान इसमें किया गया है। अब डिस्प्यूट रिड्रैसल मैकेनिज्म बनाया गया है। इसके लिए एक काऊंसिल बना दी गई है और इस प्रकार के जो विवाद हैं वे सैक 11-18 के तहत उस काऊंसिल को जायेंगे और अगर कोई व्यक्ति या संस्था लघु और कुटीर उद्योगों के हित में दिए गए उस काऊंसिल के फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाना चाहेगा तो उसे 75 प्रति सैक प्रति महीने पहले जमा करवानी पड़ेगी। इस प्रकार का सेफ मैकेनिज्म इसमें बनाया गया है और लघु एवं कुटीर उद्योगों की परिभाषा पहली बार सोनिया गांधी जी की सरकार ने दल दी है और माइक्रो, स्माल और मीडियम जो छोटे और कुटीर उद्योग हैं उनके अन्दर भी 3-3 परिभाषायें एड की गईं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ पहुंचे। मुझे लगता है कि यह कानून अपने आप में एक

इतिहास है और लघु एवं कुटीर उद्योगों के संरक्षण के लिए इस  
दे 1 के अन्दर उठाया गया आज तक का भायद यह सबसे बड़ा  
और ठोस कदम है। अध्यक्ष महोदय, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्ड की  
सरकार ने रोजगार सृजन करने के लिए जो प्रयास किया है उसी  
का यह नतीजा निकला है। इस बारे में बहुत थोड़े और स्पष्ट  
भाबदों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 33 हजार करोड़ रुपये की  
इन्वैस्टमेंट पिछले तीन सालों में अब तक हमारे पास आ चुकी है  
जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सर, पिछले 40 वर्षों में 42  
हजार करोड़ रुपये के करीब इन्वैस्टमेंट हुई थी। हमारे कार्यकाल  
के दौरा 33 हजार करोड़ रुपये का निवे 1 अकेले जमीन पर लग  
चुका है और इसके अलावा 66 हजार करोड़ रुपये के उद्योग इस  
समय हमारे पास पाईपलाइन में हैं। जिनकी प्रपोजल हमारे पास  
इस समय रिसीव हो गई है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी  
ने जो अमेरिका और कॅनेडा में यात्रा की थी उससे भी जो  
रिनाऊन अमेरिकन और कॅनेडियन कम्पनियां हैं उन्होंने 3750  
करोड़ रुपये का निवे 1 किया है। स्पीकर सर, स्टेट में अब तक  
10,500 करोड़ रुपये की डारेक्ट फॉरेन इनवैस्टमेंट आई है। जो  
अपने आप में और प्रदे 1 के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। अध्यक्ष  
महोदय, आपने निर्यात की चिन्ता की थी इसलिए मैं बताना चाहूंगा  
कि 2006-07 में प्रदे 1 का निर्यात 30 हजार करोड़ रुपये का था  
और इसके अलावा हमारे पास एच0एस0आई0आई0डी0सी0 के पास  
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में बहुत से मेगा प्रोजैक्ट आये  
हैं जिनसे हमारे प्रदे 1 के अन्दर बहुत सारी इनवैस्टमेंट होगी।

एक ऐसा माहौल बनेगा जिसमें रोजगार का सृजन हो और जिसमें छोटे और कुटीर उद्योगों को लाभ मिले। बड़े और मध्यम दर्जे के उद्योगों को भी लाभ मिले और बड़े उद्योग भी प्रदेश में महारूम न रहे, इस सरकार ने इसके लिए सतत प्रयास किये हैं। यही सब बातें थीं जिनका मैं ब्योरा देना चाहता था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जिस कानून की मैंने चर्चा की है वह “National Rural Employment Guarantee act.” है। इसके बाद इन्दौरा जी जो प्रस्ताव लेकर आये हैं उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि in the light of all issue that he has raised, are already taken care of by this force of statute passed by the Parliament of India. Either he should withdraw his resolution or this House should reject this resolution ?

**डॉ० सु गील इन्दौरा :** अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही लोग महत्व के विषय पर इस सदन में चर्चा हुई। मैं श्री भादी लाल बतरा, श्री नरेण्डा मलिक, श्री रामकुमार गौतम, डॉ० विठ्ठल भांकर भारद्वाज, श्री नरेण्डा भार्मा, श्री मान साहब, श्री सुखबीर सिंह फरमाणा, श्री मांगेराम गुप्ता व और साथी जो इस विषय पर बोले हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ तथा बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की और बहुत से अच्छे सुझाव भी रखे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार की तारीफ करने के साथ-साथ उन्होंने सरकार को अच्छे सुझाव भी दिये हैं। माननीय मंत्री जी ने भी अपने जवाब में बहुत सी ऐसी



बातें बताई जिससे कुटीर उद्योग को लाभ होता है लेकिन उसके बावजूद भी मेरी एक सोच है कि कुटीर उद्योग की तरफ जितना ध्यान देना चाहिए, हम उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि सं गेधन करके माननीय मंत्री जी इस प्रस्ताव को अपने पास रख लें और इस तरफ थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान दें या कमेटी बनाकर इसका और अध्ययन करवा लें। मैं समझता हूं कि सरकार को इस प्रस्ताव को एडॉप्ट करना चाहिए और इसको पास करना चाहिए।

**Mr. Speaker :** Question is -

This House expresses its great concern over the continuous demotion of the cottage industries, particularly traditional industries in the State as the cottage industry is only capable to provide employment to the skilled and unskilled labourer class of the rural of the State.

The motion was lost.

The resolution was rejected.

**Mr. Speaker :** Now, the House is adjourned till 2.00 P.M. on Monday, the 24<sup>th</sup> March, 2008.

**\*13.39 Hrs.**

(The Sabha then \*adjourned till 2.00 P.M. on Monday, the 24<sup>th</sup> March, 2008)